# चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 12 दिसंबर– 18 दिसंबर 2016 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

# मायावती का क़द

## मायावती ने सोशल-इंजीनियरिंग को 'सोशियो-रिलीजियस इंजीनियरिंग' में बदला

प्रभात रंजन दीन

समाजवादी पार्टी के अंतर्कलह का बहिर्लाभ बहुजन समाज पार्टी उठाने जा रही है. मायावती की पूरी कवायद सपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की है. समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में संशय की स्थिति है. यह संशय पार्टी की एकजुटता से लेकर टिकट बंटवारे के विरोधाभास तक है. सवा सौ टिकट मुसलमानों को देने के बसपाई ऐलान से मुसलमान खुश हैं और मायावती के पक्ष में वोट डालने का मूड बना रहे हैं.

दलित–मुस्लिम एकता के बसपाई एजेंडे को ठोस शक्ल देने की कोशिशें तेज होती जा रही हैं. मुस्लिमों के बीच बांटी जा रही एक बुकलेट मुसलमानों में काफी चर्चा में है. आठ पन्नों की इस किताब का नाम दिया गया है, 'मुस्लिम समाज का सच्चा हितैषी कौन? फैसला आप करें.' उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव में 128 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने की घोषणा मायावती पहले ही कर चुकी हैं. मुसलमानों में बंट रही किताब के कवर पर मायावती की फोटो है और हिंदी व उर्दू भाषा में मायावती ने मुसलमान मतदाताओं के बीच से उठ रहे विभिन्न सवालों पर सफाई पेश की है. इनमें कई सवाल भाजपा–बसपा गठबंधन को लेकर हैं. यह किताब खास तौर पर पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में तेजी से वितरित की जा रही है. भाजपा के साथ तीन बार सरकार बनाने के बारे में मायावती ने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया और भाजपा को अपना एजेंडा लागू करने की इजाजत नहीं दी. बसपा सरकार के रहते अयोध्या, मथुरा और काशी में कोई धार्मिक सुगबुगाहट नहीं होने दी. मायावती ने इस किताब में समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है. लिखती हैं कि राज्य में जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही है केंद्र में भाजपा की ताकत बढ़ी है. इस तर्क पर मायावती ने वर्ष 2009 और 2014 का उदाहरण प्रस्तुत किया है. उनका कहना है कि 2009 में जब बसपा की सरकार थी तब भाजपा को केवल नौ लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि 2014 में जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तब भाजपा 73 लोकसभा सीटों पर जीती. किताब में मायावती ने लिखा कि 1999 में भाजपा को बसपा ने ही सबक सिखाया था, जब एक वोट के कारण सरकार गिरी थी. बुकलेट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के साथ निकटता का भी हवाला दिया गया है और इसके लिए यादव परिवार की शादी में मोदी की सैफई में मौजूदगी का उदाहरण पेश किया गया है. बुकलेट में मायावती ने यह भी दावा किया है कि समाजवादी पार्टी का उदय भाजपा की मदद से हुआ था. कहा गया है कि जनसंघ की मदद से सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने पहली बार 1967 में जसवंतनगर सीट पर विजय हासिल की थी और चुनाव जीतने के बाद 1977 में उन्होंने जनसंघ की सहायता से सरकार बनाई और मंत्री बने थे. वर्ष 1989 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने दो लोकसभा सीटें जीतकर भाजपा को नया जीवन दिया था. उस समय लोकसभा में भाजपा की संख्या बढ़कर 88 हो गई थी. पुस्तिका में यह भी आरोप है कि मुलायम सिंह यादव ने 1990 में सोमनाथ से अयोध्या रथयात्रा के दौरान लालकृष्ण आडवाणी को मदद दी थी. इसी तरह के तर्कों–कुतर्कों पर आधारित बसपा की किताब मुसलमानों के बीच काफी असर जमा रही है.

समाजवादी पार्टी के ही मझोले दर्जे के एक मुस्लिम नेता कहते हैं कि इस बार मुसलमान सबसे अधिक अधर में हैं. वे पसोपेश में हैं कि वे किसके साथ जाएं. समाजवादी पार्टी का घरेलू कलह मुसलमानों को अधिक हताशा से भर रहा है, क्योंकि मुसलमान उसी दल को अपना समर्थन देंगे जो भाजपा से सीधा मुकाबला करता हुआ दिखेगा. सपा नेता अगर यह कहे कि मुसलमान मतदाता बसपा की तरफ खिसकता दिख रहा है, तो इसकी गंभीरता का एहसास किया जा सकता है. उल्लेखनीय है कि बाबरी विध्वंस के बाद से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मुस्लिम मतदाता मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे. पिछले कुछ चुनावों से मुसलमानों का मुलायम से मोहभंग भी होता दिखा. 2002 के विधानसभा चुनाव में सपा को 54 फीसदी मुस्लिम वोट मिला था, लेकिन 2007 के विधानसभा चुनाव में यह प्रतिशत घटकर 45 रह गया. 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी जीत मिली, लेकिन उसे मिलने वाले मुस्लिम मत का प्रतिशत घटकर 39 पर आ गया. आंकड़े स्पष्ट बताते हैं कि मुस्लिमों का रुझान धीरे–धीरे बसपा की तरफ बढ़ा. वर्ष 2002 में बसपा को नौ प्रतिशत मुस्लिम वोट मिले थे. 2007 के चुनाव में यह बढ़ कर 17 फीसदी हो गया. वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में हालांकि बसपा हार गई लेकिन उसे मिलने वाला मुस्लिम वोट 17 से बढ़ कर 20 प्रतिशत हो गया. मुसलमानों की थोड़ी तरजीह कांग्रेस को भी मिली. वर्ष 2002 के चुनाव में कांग्रेस को 10 फीसदी मुस्लिम वोट मिले थे जो 2012 में बढ़ कर 18 फीसदी हो गया. यानि, बसपा के साथ–साथ कांग्रेस की गतिविधियों पर भी मुसलमान मतदाताओं की गहरी नजर है.

उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की जनसंख्या 19 फीसदी के करीब है. तकरीबन 140 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी 10 से 20 फीसदी तक है. 70 सीटों पर 20 से 30 फीसदी और 73 सीटों पर 30 फीसदी से अधिक मुस्लिम आबादी है. स्पष्ट है कि मुस्लिम मतदाता 140 सीटों पर सीधा असर डालते हैं. यही कारण है कि चुनाव के समय सारे दल खास तौर पर मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर खींचने में सक्रिय हो जाते हैं. बुद्धिजीवी डॉ. मुहम्मद सरफे आलम कहते हैं कि मुस्लिम मतदाताओं का मत–चरित्र विधानसभा चुनाव में कुछ और होता है और लोकसभा चुनाव में कुछ और. डॉ. आलम मानते हैं कि मुस्लिम समुदाय का वोट कभी–कभार बंट भी जाता है, लेकिन अधिकतर एकमुश्त एक ही दल को जाता है. मायावती इसी कोशिश में हैं कि सपा के खिलाफ चल रही स्थितियों का पूरा फायदा बसपा को मिले और मुसलमानों का एकमुश्त वोट उसे मिले. मायावती का सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला इस बार बदल कर 'सोशियो रिलीजियस इंजीनियरिंग' फार्मूला बन गया है, जिसमें केवल मुसलमान और दलित केंद्र में हैं. इस बार ब्राह्मण बसपा की राजनीति के केंद्र में नहीं हैं. मुसलमानों का समाजवादी पार्टी से बिदकाव मुजफ्फरनगर दंगे के समय से ही होने लगा था. दादरी की घटना ने इसे और गहरा किया. बिहार चुनाव के दौरान महागठबंधन से अलग होने के मुलायम के ऐलान से भी उत्तर प्रदेश के मुसलमान मतदाता अचानक सकते में आ गए थे. मुसलमान सपा के इस फैसले को भाजपाई मिलीभगत के तौर पर देख रहे थे. इसे भांपते हुए ही मायावती ने मुसलमानों को (शेष पृष्ठ 2 पर)

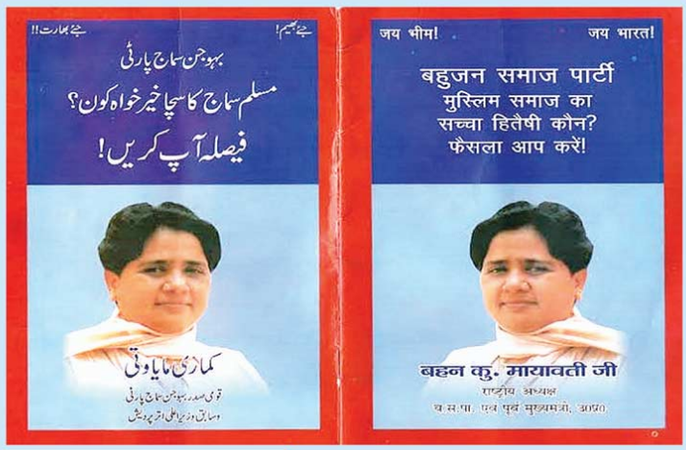


**मायावती सोच–समझ कर यह बयान दे रही हैं कि भाजपा और सपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में हारी हुई लड़ाई लड़ रही है, लिहाजा मुसलमान मतदाताओं को अपना वोट बेकार नहीं करना चाहिए. मायावती ने तीन तलाक के मसले पर और भोपाल में जेल से भागे सिमी के आठ कथित आतंकियों के मुठभेड़ में मारे जाने पर भी सीधी प्रतिक्रिया देकर मुसलमानों का ध्यान अपनी ओर खींचा. सिमी से प्रतिबंध हटाने से लेकर सिमी के समर्थन में खुला बयान देने वाले मुलायम सिंह की इस बार की चुप्पी मुसलमानों को खली है.**


वित्तमंत्री जी, इस क़ानून से सारे अपराधी छूट जाएंगे | P-3

नोटबन्दी के दौर में नक़ली नोट का ख़तरा | P-5

बिहार : भाजपाइयों ने ज़मीन में खपाया कालाधन! | P-7

# मायावती का क़द

पृष्ठ 1 का शेष

टिकट बांटने की दरियादिली दिखानी शुरू कर दी. विश्लेषकों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में 30 फीसदी तक वोट पाने वाली पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आ जाती है. यूपी में दलित और मुस्लिम समुदाय का मत प्रतिशत मिलकर 39 फीसदी होता है. यह आंकड़ा मायावती को लुभा रहा है और वे इसी प्रयास में हैं कि इन दो तबकों के वोट के सहारे वे सत्ता तक पहुंच जाएं. हालांकि कांग्रेस और छोटी पार्टियों का संभावित गठजोड़ और इसमें असदुद्दीन ओवैसी की मुस्लिम-दलित राजनीति मायावती के प्रयास में रोड़े डाल सकती है. उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में छोटे-छोटे मुस्लिम संगठनों के इत्तेहाद फ्रंट में डॉ. मोहम्मद अय्यूब की पीस पार्टी समेत कई मुस्लिम संगठन शामिल हैं. पिछले विधानसभा चुनाव में चार सीटें जीतने वाले डॉ. अय्यूब इस बात की संभावना जताते हैं कि फ्रंट में अभी कई और पार्टियां जुड़ेंगी. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस से भी एक साथ आने की बात चल रही है. कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी इस दिशा में सक्रिय हैं. कांग्रेस ने मुस्लिमों को प्रभावित करने के लिए ही गुलाम नबी आजाद को यूपी का प्रभारी बनाया, लेकिन फिलहाल इसका कोई खास असर पड़ता नहीं दिख रहा है. बसपा के एक नेता ने यह संभावना जताई कि असदुद्दीन ओवैसी बसपा के साथ आ सकते हैं, इसके प्रयास चल रहे हैं. बसपा नेता ने कहा कि ओवैसी भी दलित-मुस्लिम एकता की हिमायत करते हैं और मायावती पर कभी प्रहार नहीं करते. ओवैसी सैद्धांतिक रूप से बसपाई स्टैंड के साथ दिखते हैं.

इस चुनाव में मायावती मुस्लिम कार्ड खुल कर खेल रही हैं. उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अगर मुस्लिमों ने उनका साथ दिया तो बसपा भाजपा को हरा सकती है. मायावती सोच-समझ कर यह बयान दे रही हैं कि भाजपा और सपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में हारी हुई लड़ाई लड़ रही है, लिहाजा मुसलमान मतदाताओं को अपना वोट बेकार नहीं करना चाहिए. मायावती ने तीन तलाक के मसले पर और भोपाल में जेल से भागे सिमी के आठ कथित आतंकियों के मुठभेड़ में मारे जाने पर भी सीधी प्रतिक्रिया देकर मुसलमानों का ध्यान अपनी ओर खींचा. सिमी से प्रतिबंध हटाने से लेकर सिमी के समर्थन में खुला बयान देने वाले मुलायम सिंह की इस बार की चुप्पी मुसलमानों को खली है. मुसलमानों के कल्याण के लिए की गई घोषणाओं को अमल में नहीं लाए जाने के कारण भी मुसलमान सपा से नाराज हैं. सपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में मुसलमानों को 18 प्रतिशत आरक्षण देने, सच्चर समिति और रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिशों को अपने स्तर से लागू करने और आतंकवाद के आरोप में जेलों में बंद बेकसूर मुसलमानों के मुकदमे वापस लेने समेत कई वादे किये थे लेकिन ये वादे अधूरे ही रह गए.

समाजवादी पार्टी के किले में दिख रहे इन छेदों को और बड़ा करने और मुस्लिमों को अधिक से अधिक 'उकसाहित' और प्रभावित करने का दायित्व मायावती ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को सौंपा है. नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बेटे अफजल सिद्दीकी को भी इस अभियान में शरीक किया गया है. अफजल सिद्दीकी को मेरठ, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़ और आगरा डिवीजन का प्रभारी बनाया गया है. मायावती ने अपने नेताओं को निर्देश दिया है कि वे बूथ स्तर तक जाकर मुसलमानों के बीच काम करें और खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम युवकों को बसपा के साथ जोड़ें. इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर नसीमुद्दीन के बेटे को खास जिम्मेदारी सौंपी गई है. मायावती ने पिछले दिनों औपचारिक बयान जारी करते हुए कहा कि मुसलमानों का हित सपा में सुरक्षित नहीं है और सपा को वोट देने का मतलब है भाजपा की जीत सुनिश्चित करना. मायावती ने कहा, 'उत्तर प्रदेश के सर्वसमाज के साथ-साथ मुस्लिम समुदाय को यह समझना बहुत जरूरी है कि उनका हित सपा में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, अब दो खेमों में बंटी सपा को वोट देने का मतलब है भाजपा को मजबूत करना और उसे जिताना.' मायावती ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जबसे सपा सरकार बनी है, तबसे कानून का राज समाप्त हो गया है और उसकी जगह गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक, भ्रष्ट और साम्प्रदायिक तत्वों का जंगलराज चल रहा है. मायावती ने दावा किया कि 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट उनकी पार्टी को ही मिलेगा. मायावती का कहना है कि यूपी के मुस्लिम बहुजन समाज पार्टी के साथ वापस आ रहे हैं. मायावती ने कहा, 'अब मुस्लिम हमारे साथ आ गए हैं. अब उनके मन में कोई संशय नहीं है. सपा के अंदरूनी कलह से मुस्लिम वोट उनसे दूर हुआ है.' बसपा महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों का बिरयानी में तेजपत्ते की तरह इस्तेमाल करती है. इसका एहसास मुसलमानों को अब खुद ब खुद हो रहा है. समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को धोखा देने वाली पार्टी है. मुसलमान पिछले 25 साल से समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को क्या मिला? चुनाव होने के बाद सपा मुसलमानों को अकेला छोड़ देती है. सिद्दीकी ने मुसलमानों और दलितों के एकजुट होने का दावा किया और कहा कि अपने परिवार में ही एक-दूसरे से लड़ने वाले सपा नेताओं के लिए अब मुसलमान वोट नहीं डालने वाले. नसीमुद्दीन ने यह भी कहा कि मुसलमानों ने बसपा को वोट नहीं दिया तो यूपी में एक भी मुस्लिम विधायक नहीं बन पाएगा. ■

## लेकिन ये नहीं मानते मायावती के दावे में दम

कुछ मुसलमान नागरिक मायावती के दावे को जमीनी हकीकत नहीं मानते. इलाहाबाद के डॉ. नूर आलम कहते हैं कि मुसलमान सपा से अलग नहीं हो सकते. हालांकि वे यह भी कहते हैं कि जो कुछ काम होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुसलमान अखिलेश से नाराज नहीं हैं. शिवपाल ने भी बहुत संघर्ष किया है, उनसे भी लोगों को हमदर्दी है. पार्टी के टूटने की हालत में ही वोटों का बिखराव हो सकता है और तब मुसलमान बसपा की तरफ जा सकते हैं. लखनऊ के फुरकान का कहना है कि मुसलमान मुलायम के साथ ही रहेंगे. उनके सामने कोई और विकल्प नहीं है. पूर्व विधायक शेख सुलेमान कहते हैं कि मुसलमानों के लिए नेताजी ने बहुत कुछ किया है. इसलिए मुसलमान नेताजी के साथ खड़े हैं. मुसलमानों को विश्वास है कि मुलायम के रहते समाजवादी पार्टी में टूट नहीं हो सकती. लिहाजा, मुस्लिम वोटों में कोई बिखराव नहीं है. कन्नौज के हाजी जरार खां का कहना है कि मुसलमान अखिलेश के साथ हैं. पार्टी अगर बंटी भी तो मुसलमान अखिलेश के साथ चले जाएंगे. अखिलेश ने मुसलमानों को जो सहूलियतें दी हैं उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. मेरठ के गुलशेर मलिक कहते हैं कि मुसलमान तो अखिलेश की ही तरफ हैं. कब्रिस्तान की चारदीवारी बनाने का मसला हो या कई अन्य मामले, अखिलेश ने मुसलमानों के लिए बहुत काम कराए हैं. पार्टी में टूट हुई तो 80 फीसद मुसलमान अखिलेश की ही तरफ जाएंगे. बलिया के परवेज रौशन का कहना है कि जो लोग यह कह रहे हैं कि अखिलेश ने मुसलमानों के लिए काम नहीं किया, वे ठीक जानकारी नहीं रखते. अखिलेश ने मुसलमानों के लिए कोई गलत काम नहीं किया. मुलायम की असली विरासत हैं अखिलेश, इसलिए मुसलमान उनसे अलग नहीं हो सकते.

पूर्वांचल के मोहसिन खान कहते हैं कि अगर टिकट का वितरण और उम्मीदवारों का चयन निष्पक्ष तरीके से हुआ और उस पर कलह हावी नहीं हुआ तो आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा को स्पष्ट बहुमत मिलेगा. मोहसिन खान सपा के वे नेता हैं जिन्हें सपा के कलह का खामयाजा भुगतना पड़ा है. इसके बावजूद वे बसपाई दावे को पूरी तरह ठुकरा देते हैं. गोरखपुर के जिला अध्यक्ष मोहसिन खान और गोंडा के जिला अध्यक्ष मो. महफूज खान को हटाया गया, लेकिन इनकी सपा के प्रति वफादारी कायम है. मोहम्मद मोहसिन खान स्टेट गेस्ट हाउस कांड में अभियुक्त बनाए गए थे और जेल भी गए थे. वह मुकदमा आज भी चल रहा है. क्षेत्र के मुसलमान इस कार्रवाई से काफी खफा हैं कि पार्टी ने उन्हें टिकट भी नहीं दिया और जिला अध्यक्ष का पद भी छीन लिया.

## मुसलमानों में भ्रम बढ़ा गया नेताजी का बयान

समाजवादी पार्टी के रजत जयंती समारोह में मुलायम सिंह यादव के बयान ने मुसलमानों में भ्रम बढ़ा दिया. मुलायम ने कहा कि आज अगर सबसे ज्यादा जुल्म किसी पर हो रहा है तो वह मुसलमानों के साथ हो रहा है. मुसलमानों पर अत्याचार सपा सरकार में भी हो रहा है. मुलायम ने कहा, 'मैं अखिलेश यादव से कहता हूं कि वह प्रशासन को आदेश देकर ऐसा होने से रोकें. हमें देश के किसानों और युवाओं के साथ मिलकर साम्प्रदायिक शक्तियों से लड़ना है. हमारी लड़ाई साम्प्रदायिक शक्तियों के खिलाफ है. जनता निराश हो रही है, कार्यकर्ताओं को जनता के बारे में सोचना है. बहुत कुछ करना है. जो नारा देते हो, उसका पालन करो.' मुसलमानों में अधिक भरोसा पैदा करने के लिए कही गई मुलायम की बातों ने मुसलमानों के बीच मुलायम की हताशा को अधिक रेखांकित किया. ■

## किसे कितनी मिली मुस्लिम बहुल सीटें

(1989 से 2012)

| वर्ष | बसपा | सपा | भाजपा | कांग्रेस | रालोद | अन्य/जनता दल | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 06 | 00 | 20 | 20 | 00 | 76 | 122 |
| 1991 | 00 | 01 | 79 | 07 | 00 | 38 | 125 |
| 1993 | 05 | 31 | 69 | 06 | 00 | 16 | 127 |
| 1996 | 13 | 34 | 59 | 07 | 00 | 15 | 128 |
| 2002 | 24 | 43 | 32 | 09 | 10 | 11 | 129 |
| 2007 | 59 | 26 | 25 | 07 | 06 | 07 | 130 |
| 2012 | 24 | 78 | 20 | 04 | 04 | (पीपी-2, कौएद-1) | 133 |

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 08 अंक 41
12 दिसंबर- 18 दिसंबर 2016

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-65500786, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16++ (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

feedback@chauthiduniya.com

## आयकर संशोधन विधेयक, 2016

# वित्तमंत्री जी, इस क़ानून से सारे अपराधी छूट जाएंगे

**वित्त मंत्री अरुण जेटली से एक बड़ी गलती हुई है. ये जो नया कानून लाया गया है, इसका विफल होना तय है. इसमें कई सारी समस्याएं हैं. यह कानूनी तौर पर तार्किक नहीं है और न ही इसमें आय छिपाने वाले लोगों की मानसिकता को समझने की कोशिश की गई है. सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें 10 फीसदी पेनाल्टी यानी जुर्माने का प्रावधान है. अगर इस जुर्माने को अतिरिक्त टैक्स के रूप में लिया जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आयकर कानून में जैसे ही जुर्माना या पेनाल्टी शब्द का इस्तेमाल होता है तो कोई भी कंपनी या व्यक्ति इस कानून के तहत अपनी आय को सार्वजनिक नहीं करेगा. ये कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति और कंपनी खुद को क्रिमिनल साबित कराने के लिए खुद ही अपनी आय सार्वजनिक करेगा. वह ऐसा इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जब किसी व्यक्ति पर जुर्माना लगता है तो उसे कई और भी परिणाम झेलने पड़ जाएंगे. जैसे ही किसी व्यक्ति पर जुर्माना लगता है तो वह कानून की नजर में एक अपराधी बन जाता है. जुर्माना लगते ही वह कई चीजों के लिए अयोग्य करार दिया जाएगा.**

मनीष कुमार

सरकार जिस कानून के जरिए कालाधन को पकड़ना चाहती है उस जाल में तो कोई चूहा भी नहीं फंसने वाला है. वैसे नोटबंदी के बाद आयकर संशोधन बिल लाकर सरकार ने ये संकेत देने की कोशिश की है कि वो कालाधन को अर्थव्यवस्था से बाहर करने के लिए कठोर कदम उठाने को तैयार है. सरकार की इस पहल को जनता का समर्थन भी है. लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार की मंशा और उसके फैसले में कोई संबंध है? क्या जिस मकसद से नए कानून को लाया गया वो पूरा होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि अव्यवस्था और लचर कानून के कारण सरकार अपनी मुहिम में विफल हो जाएगी? इस कानून का असर व्यापक होने वाला है इसलिए इसके हर पहलू को समझना जरूरी है.

लोकसभा में हंगामे के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आयकर संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत कर दी. लोकसभा स्पीकर ने इसे मनी-बिल के रूप में स्वीकार किया. मतलब यह कि सरकार इसे राज्यसभा में ले जाने के मूड में नहीं थी. अगले दिन फिर लोकसभा में हंगामा चलता रहा, लेकिन उसी हंगामे के दौरान इस बिल को पास कर दिया गया. आयकर कानून में हुए बदलाव पर न तो संसद में चर्चा हुई और न ही विपक्ष ने विश्लेषण किया. हैरानी तो ये है कि मीडिया ने इस कानून में हुए बदलाव का अध्ययन किए बिना सरकार की दलीलों पर हामी भरकर इसे कालाधन पर शिकंजा कसने वाला कानून बता दिया. आयकर संशोधन विधेयक के प्रावधानों और अभिप्रायों का क्या नतीजा होगा, यह समझना जरूरी है.

फोटो- सुनील मल्होत्रा



सबसे पहले देखते हैं कि इस नए कानून में क्या नई बात है. सबसे पहली बात, इस कानून में कुछ नया नहीं है. यह एक वोलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इन्कम स्कीम यानी आय की स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना है, जिसे कई सरकार ने अपने-अपने हिसाब से लागू किया और हर बार अपने लक्ष्य को पाने में विफल रही है. इस विधेयक के मुताबिक, नोटबंदी के बाद कालाधन घोषित करने वालों की आय का 49.9 प्रतिशत हिस्सा कर, जुर्माना और पीएमजीके यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सेस में ही चला जाएगा. इस 49.9 प्रतिशत हिस्सा में अघोषित आय पर 30 प्रतिशत कर, 10 प्रतिशत जुर्माना और कर का 33 प्रतिशत पीएमजीके सेस में जाएगा. इसके अलावा 25 फीसदी रकम को बैंक में चार साल के लिए जीरो फीसदी ब्याज पर लॉक कर दिया जाएगा यानी उपभोक्ता मात्र 25 फीसदी रकम ही बैंक से निकाल पाएगा, बाकी 25 फीसदी के लिए चार साल इंतजार करना होगा. इसके अलावा, अघोषित आय का खुलासा नहीं करने वाले व्यक्तियों को पकड़े जाने पर अपनी अघोषित आय का 75 प्रतिशत हिस्सा कर और 10 प्रतिशत जुर्माने के तौर पर चुकाना पड़ेगा. मतलब जो इन्कम टैक्स की रेड में पकड़ा गया तो उसे अघोषित आय की 85 फीसदी रकम गंवानी पड़ेगी. पहली नजर में ये कानून तो कड़ा जरूर नजर आता है लेकिन इसके इस्तेमाल और आयकर के दूसरे कानून के साथ जोड़ कर देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसका सफल होना मुश्किल है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली से एक बड़ी गलती हुई है. ये जो नया कानून लाया गया है, इसका विफल होना तय है. इसमें कई सारी समस्याएं हैं. यह कानूनी तौर पर तार्किक नहीं है और न ही इसमें आय छिपाने वाले लोगों की मानसिकता को समझने की कोशिश की गई है. सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें 10 फीसदी पेनाल्टी यानी जुर्माने का प्रावधान है. अगर इस जुर्माने को अतिरिक्त टैक्स के रूप में लिया जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आयकर कानून में जैसे ही जुर्माना या पेनाल्टी शब्द का इस्तेमाल होता है तो कोई भी कंपनी या व्यक्ति इस कानून के तहत अपनी आय को सार्वजनिक नहीं करेगा. ये कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति और कंपनी खुद को क्रिमिनल साबित कराने के लिए खुद ही अपनी आय सार्वजनिक करेगा. वह ऐसा इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जब किसी व्यक्ति पर जुर्माना लगता है तो उसे कई और भी परिणाम झेलने पड़ जाएंगे. जैसे ही किसी व्यक्ति पर जुर्माना लगता है तो वह कानून की नजर में एक अपराधी बन जाता है. जुर्माना लगते ही वह कई चीजों के लिए अयोग्य करार दिया जाएगा. उदाहरण के तौर पर, आप फिर कभी किसी कंपनी के स्वतंत्र डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे. सरकार के बहुत सारे इनाम और पदों के लिए आप अयोग्य हो जाएंगे. उन्हें फिर भविष्य में बैंक लोन भी नहीं मिल पाएगा. अब अगर किसी के पास कालाधन है तो वो क्यों उसे सार्वजनिक करेगा. अगर सरकार को बैंक में पैसा लाना ही था और सरकारी खजाना को भरना था तो पूरा का पूरा टैक्स के रूप में उगाही करने का प्रावधान बनाया गया होता. इस चूक का नतीजा यही होगा कि इस स्कीम के तहत शायद ही कोई व्यक्ति या कंपनी स्वेच्छा से अपनी आय को सार्वजनिक करे. मतलब यह कि कालाधन को पकड़ने का काम आयकर विभाग को ही करना होगा.

सच्चाई ये है कि आयकर विभाग के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, जिसके जरिए सरकार करोड़ों लोगों द्वारा जमा किए गए पैसे को खंगाल सके. सारे बैंक एकाउंट का अध्ययन कर सके. कालाधन जमा करने वालों को पकड़ सके. फिलहाल, आमतौर पर एक इन्कम टैक्स एसेसिंग ऑफिसर यानी कर निर्धारण प्राधिकारी के पास लगभग सौ केस होते हैं. हालत ये है कि इन सौ मामलों की भी सही ढंग से जांच नहीं हो पाती है और न ही आरोपियों को कोर्ट से सजा दिलवा पाने में सफल हो पाते हैं. ज्यादातर मामलों में आरोपी कोर्ट से बरी हो जाते हैं. अब जब करोड़ों बैंक एकाउंट्स में पैसे जमा हुए हैं तो सभी मामलों की जांच तो नामुमकिन है. इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट 15 से 20 फीसदी मामलों की भी सही ढंग से जांच कर ले, तो यह आश्चर्य ही होगा. मतलब यह कि चुने हुए मामलों को ही आयकर विभाग उठाएगी. आयकर अधिकारी ही तय करेंगे कि किस मामले को उठाना और किसे छोड़ देना है. ऐसे में जो स्थिति बनेगी, उससे भ्रष्टाचार का एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा. हर एसेसिंग ऑफिसर उगाही का एक केंद्र बन जाएगा. जिन मामलों में कार्रवाई नहीं होगी तो आरोप ये लगेगा कि इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैसे लेकर आरोपियों को छोड़ दिया है. कई ऐसे मामले भी सामने आएंगे, जिसमें अधिकारी घूस लेकर लोगों को छोड़ देंगे. अगर किसी अधिकारी ने घूस नहीं ली और ईमानदारी से कार्रवाई की, तो आरोप ये लगेगा कि पैसा नहीं मिला तो कार्रवाई शुरू हो गई. यानी आयकर विभाग के अधिकारियों की दोनों तरफ से फजीहत होने वाली है. समस्या यहीं खत्म नहीं होती है. जिन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, वो भी कोर्ट से छूट जाएगा.

दरअसल, इस कानून के तहत जो कार्रवाई होगी, उसमें एक बड़ा लूपहोल है. आयकर विभाग में हर मामले की जांच आयकर विभाग के एसेसिंग अधिकारी यानी कर निर्धारण प्राधिकारी करते हैं. जब कोई व्यक्ति टैक्स की चोरी करता है या कालाधन के साथ पकड़ा जाता है तो निर्धारण अधिकारी ही उन पर आयकर कानून की अलग-अलग धाराएं लगाते हैं. अब नए कानून में जो जुर्माने का प्रावधान है, उसमें एक मूलभूत समस्या है. इसमें जिस धारा के तहत कार्रवाई होगी वो आयकर कानून के सेक्शन 68, 69, 69-ए, 69-बी और 69-सी है. आमतौर पर आयकर विभाग को हर मामले की पूर्वसूचना होती है, जिस पर विभाग एक्शन लेता है. पूर्वसूचना के रूप में फिलहाल आयकर विभाग के पास सिर्फ बैंक खातों के डिटेल हैं. इसी सूचना पर कार्रवाई होगी. एक तो इतने खातों को खंगालना मुश्किल है और अगर कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई भी तो वो छूट जाएंगे. इसकी वजह ये है कि इन्कम टैक्स नियम के जो सेक्शन 68, 69, 69-ए, 69-बी और 69-सी है, ये सारे के सारे डिस्क्रीशनरी नेचर के हैं. मतलब यह कि इनका इस्तेमाल अपने आप नहीं होता है, इन धाराओं का इस्तेमाल इन्कम टैक्स के अधिकारी अपने विवेक से करते हैं. जब जांच के दौरान एसेसिंग अधिकारी को ये लगता है कि आरोपी ने जांच में कुछ गड़बड़ी की है और कुछ छिपा रहा है, तब वो इन धाराओं को अपने विवेक से लगाता है. जब अधिकारी के विवेक पर ही इनका इस्तेमाल होता है तो ये अधिकारी पर निर्भर करता है कि किसी मामले में इन सेक्शन को लगाए या न लगाए. इसी वजह से अधिकारियों के पास उगाही करने का केंद्र बनने और भ्रष्टाचार का खतरा बना रहता है. ये इन सेक्शन की विशेषताएं हैं और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है. कमजोरी इसलिए क्योंकि जब ये मामला कोर्ट में जाता है, तब विवेक के इस्तेमाल पर मामला फंस जाता है और ज्यादातर आरोपी छूट जाते हैं. दूसरी समस्या ये है कि वित्त मंत्रालय ने जुर्माने को कानून का हिस्सा बना दिया है. जबकि, एसेसमेंट (जांच) और पेनाल्टी (जुर्माना) लगाना ये दोनों अगल-अलग काम हैं. इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट में दोनों की प्रक्रिया अलग है. जांच एक सिविल मामला है, जबकि पेनाल्टी लगाना क्रिमिनल मामला है. वैसे भी आयकर कानून में जुर्माना तो सिर्फ डराने के लिए रखा गया था क्योंकि रेवेन्यू जमा करने का ये कोई सही तरीका नहीं है. नए नियम की सबसे बड़ी गलती ये है कि सरकार ने जुर्माने को टैक्स के साथ कानून में जोड़ दिया. यह कहा जा सकता है कि जुर्माने को खुद लागू करने के प्रावधान की वजह से नए कानून का विफल होना तय है.

न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण रूल है, जिसे रेस ज्यूडिकाटा कहते हैं. इसके मुताबिक अगर एक काम्पीटेंट कोर्ट ने एक मामले में फैसला दे दिया है, तो वह उदाहरण बन जाएगा. उसी तरह का अगर दूसरा कोई मामला सामने आता है तो काम्पीटेंट कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. मतलब एक तरह के केस में अगर कोर्ट ने कोई फैसला ले लिया है तो उसी तरह के दूसरे मामले में कोर्ट अलग फैसला नहीं दे सकती है. ऐसा ही एक केस मायावती का था. उनके बैंक एकाउंट में जितना भी पैसा था, उसमें उनको क्लीन चिट मिल गई. इन्कम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल ने उन्हें छोड़ दिया. ट्रिब्यूनल ने साफ-साफ कहा कि बैंक एकाउंट में जितने भी पैसे हैं, वो गलत नहीं हैं. उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है. इस पर सेक्शन 68 लागू नहीं हो सकता है. ये अपने आप में हैरान करने वाला फैसला है. इस फैसले का मतलब यही है कि जिसको जितना कमाना है, कमाए और सारे पैसे बैंक में डाल दे. इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है. इस कानून के तहत हर मामले में कोर्ट मायावती के केस के मुताबिक फैसला लेगी. इसका मतलब यह कि जिन लोगों ने बैंक में पैसा जमा करा दिया उन्हें कोई सजा नहीं होगी.

कोर्ट की हालत ये है कि जब भी सेक्शन 68 सामने आता है तो जज साहब उस मामले को ही रफा-दफा कर देते हैं क्योंकि ये मामला अधिकारी के विवेक का मान लिया जाता है. मजेदार बात ये है कि नए कानून से व्यापारियों और दुकानदारों का बाल भी बांका नहीं होने वाला है. इन्कम टैक्स कानून में पचासों ऐसे प्रावधान हैं, जिसके जरिए वो अपने सारे धन को बचा सकते हैं. इन्कम टैक्स के तो ऐसे कानून हैं कि अगर कोई दुकानदार ये कह दे कि कोई व्यक्ति दस लाख रुपये दुकान में छोड़ कर चला गया तो वो सजा के किसी भी प्रावधान से बाहर हो गया है. इन्कम टैक्स कानून का एक सेक्शन है, 28 (4) जिसमें एनी अदर बेनिफिट की बात की गई है. जब तक ये कानून है, तब तक व्यापारियों और दुकानदारों को कई चिंता नहीं होगी. उनके पास जितना भी काला या सफेद धन है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता है. नोटबंदी का फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है. लोग ये जानते हैं कि ये एक कठिन फैसला है और इससे लोगों को परेशानी होगी. ऐसे में सरकार को कानून में ऐसे बदलाव लाने चाहिए थे, जिसमें अधिकारियों के विवेक के इस्तेमाल का स्थान नहीं होता. कालाधन और हाल में पुराने नोट जमा करने के दौरान हुई धपलेबाजी को पकड़ने और उन्हें सजा देने के लिए कोई साधारण लेकिन सख्त कानून लाना चाहिए था, जिसमें बचने का कोई रास्ता नहीं होता. अगर सरकार ऐसा कानून लाती, जिसमें हर बैंक एकाउंट के पिछले एक दो साल में जितना पैसा जमा हुआ और जो पैसा नोटबंदी के बाद जमा हुआ उसका ऑसत निकालते और जो भी रकम ज्यादा होता उस पर सीधे-सीधे 40 या 50 फीसदी टैक्स चुकाने का प्रावधान होता, तो न अधिकारियों को विवेक का इस्तेमाल करना होता और न ही ये मामले कोर्ट से बरी होते और न ही कोई बच पाता.

नोटबंदी हो या उसके बाद की स्थिति में कालेधन को गिरफ्त में लेने का मसला, सरकार के पास कोई स्ट्रैटेजी है या कोई विजन है. वही टैक्स रीजीम, वही इन्कम टैक्स एक्ट, वही कानूनी व्यवस्था, वही डिपार्टमेंट, वही अधिकारी, वही सारे टैक्स देने वाले लोग, फिर भी अगर सरकार ये सोचती है कि जिन लोगों ने कालाधन छिपा रखा है वो स्वत: अपने धन को सार्वजनिक करने के लिए लाइन में खड़े हो जाएंगे तो ये बेवकूफी है. ये लोग 30 फीसदी टैक्स से बचने के लिए हेराफेरी करते हैं. इन्होंने 45 फीसदी टैक्स देकर कालेधन को सफेद करने का मौका गंवा दिया. कह सकते हैं कि अब तक जितनी भी स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना आई, वो करदाता की मानसिकता को समझ नहीं पाई. यही वजह है कि ये सारी योजनाएं विफल हो गईं. उसी आधार पर ये कहा जा सकता है कि 50 फीसदी टैक्स और 25 फीसदी चार साल तक जब्त करने वाले कानून का सफल होना नामुमकिन है.■

manishbph244@gmail.com

जम्मू-कश्मीर : पब्लिक सेफ्टी एक्ट

# अंधे क़ानून का अंधाधुंध इस्तेमाल

**जंगल तस्करों को काबू में करने के लिए बनाए गए इस कानून का इस्तेमाल राजनीतिक विरोध को कुचलने के लिए शेख अब्दुल्ला की सरकार के दौरान शुरू हुआ था. दक्षिणी कश्मीर के पूर्व कांग्रेसी सरपंच सज्जाद अहमद मलिक को डेढ़ महीने पहले पुलिस ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया. वह पुलिस की कैद में थे. लेकिन एक दिसंबर को अचानक ही खबर आई कि वह एक संदिग्ध एनकाउंटर में मारे गए. कांग्रेस अध्यक्ष ने इसे हिरासत में हत्या की संज्ञा दी है.**

हारून रेशी

कश्मीर में पिछले पांच माह से जारी हिंसात्मक स्थिति में पुलिस के हाथों मानवाधिकार का धड़ल्ले से उल्लंघन हुआ है. पुलिस के हाथों में मानवाधिकार को कुचलने का जो सबसे कारगर हथियार है, उसका नाम है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट. आमतौर पर काला कानून कहे जाने वाले इस एक्ट के तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को पकड़ कर अदालत में पेश किए बगैर छह माह से दो साल के लिए जेल भेज सकती है.

दक्षिणी कश्मीर के इरु कोकरनाग के पूर्व सरपंच सज्जाद अहमद मलिक को पुलिस ने डेढ़ माह पहले पथराव करने के आरोप में इसी काले कानून के तहत पकड़ा था. उसके घर वालों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और जमानत पर उसकी रिहाई का अदालती आदेश हासिल किया. लेकिन पुलिस ने इस अदालती आदेश के बावजूद सज्जाद को रिहा नहीं किया. एक दिसंबर की शाम तीसरे पहर इलाके में जंगल की आग की तरह यह खबर फैल गई कि डेढ़ माह से कैद सज्जाद पुलिस के हाथों मारा गया है. सज्जाद के परिजनों ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस ने हिरासत के दौरान सज्जाद का कत्ल कर दिया है. लिहाजा, पुलिस का कहना है कि सज्जाद ने एक पुलिसकर्मी से राइफल छीनकर फरार होने की कोशिश की थी और बाद में मुठभेड़ के दौरान मारा गया. सज्जाद कांग्रेस पार्टी से संबंध रखता है, राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष जीए मीर ने इस घटना के बारे में चौथी दुनिया के साथ बात करते हुए कहा कि यह एक फर्जी पुलिस एनकाउंटर था, जिसमें सज्जाद मारा गया है. मीर ने कहा कि उन्होंने सरकार से इस घटना की न्यायिक जांच कराने की मांग की है. जीए मीर इस इलाके से असेंबली के लिए चुने गए हैं. उन्होंने कहा कि मैं सज्जाद को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और मुझे यकीन है कि पुलिस ने इस कत्ल को छुपाने के लिए एक फर्जी कहानी गढ़ ली है. गौर करने वाली बात ये है कि यह कश्मीर में होने वाली ऐसी पहली और अनोखी घटना नहीं है. बल्कि यहां इस तरह के दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं.

घाटी में मानवाधिकार के लिए काम करने वाले एक प्रमुख कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को पुलिस ने पिछले दिनों 76 दिन की कैद के बाद रिहा कर दिया. सरकार ने खुर्रम को सितंबर के दूसरे सप्ताह में जेनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार कौंसिल मीटिंग में शामिल होने से रोक दिया था. उसके कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया. राज्य की अदालत ने खुर्रम के केस की सुनवाई के दौरान पुलिस के आरोप को कमजोर और बिना सबूत के पाया और तुरंत उनकी रिहाई का आदेश दिया. पुलिस के आरोपों में कितना दम था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुर्रम के खिलाफ दर्ज केस में उनके पिता का नाम तक गलत लिखा गया. अदालत ने अपने फैसले में इस गिरफ्तारी को गैरकानूनी और ताकत का गलत इस्तेमाल करार देते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि खुर्रम को फौरन रिहा किया जाए. पुलिस सीनाजोरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फौरी रिहाई के अदालती आदेश के बावजूद खुर्रम को पांच दिन बाद छोड़ा गया.

खुर्रम परवेज



सज्जाद अहमद मलिक

पब्लिक सेफ्टी एक्ट के गलत इस्तेमाल के बुनियादी कारणों में एक कारण यह भी है कि इस कानून के तहत किसी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को अदालती आदेश लेने की जरूरत नहीं पड़ती है. यही वजह है कि पुलिस इस कानून के तहत कम उम्र के बच्चों को भी गिरफ्तार कर लेती है. एक दिसंबर को श्रीनगर हाईकोर्ट ने एक फैसले में साफ किया है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत पुलिस किसी नाबालिग को गिरफ्तार नहीं कर सकती है. यह आदेश अदालत ने एक केस की सुनवाई के दौरान दिया. इस केस के मुताबिक पुलिस ने दक्षिणी कश्मीर के मटन क्षेत्र के एक नाबालिग बच्चे तनवीर अहमद वट्टर को जन सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस आंकड़ों के मुताबिक पिछले पांच महीनों के दौरान गिरफ्तार किए गए हजारों लोगों में से 600 लोगों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है. कानूनविदों के मुताबिक पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत अगर कोई बेकसूर गिरफ्तार हो जाता है, तो उसको अदालत के संज्ञान में लाने में महीनों लग जाते हैं. श्रीनगर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट मियां अब्दुल कैय्यूम ने इस सिलसिले में चौथी दुनिया से बात करते हुए कहा कि हम जब पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बंद किसी व्यक्ति का केस लेकर अदालत में जाते हैं, तो पहली ही पेशी पर अदालत पुलिस को जवाब देने के लिए चार हफ्ते का वक्त दे देती है. अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस को जवाब देने में कई महीने लग जाते हैं. तब कहीं जाकर अदालत को यह समझने का मौका मिलता है कि यह आरोप सच्चा है या झूठा.

विशेषज्ञों का कहना है कि असल में पब्लिक सेफ्टी एक्ट को गलत आरोपों के तहत लोगों को बंद करने के लिए ही वजूद में लाया गया था. ये कानून 1977 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए लागू कराया था. हालांकि शुरू में ये कहा गया कि इस कानून को सिर्फ वन तस्करों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा ताकि यहां हरे-भरे जंगलों को लूटने-खसोटने से रोका जा सके. लेकिन बाद की परिस्थितियों ने ये साबित किया कि यह कानून राजनीतिक विरोधियों को काबू में करने के लिए बनाया गया है. इस कानून को राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करने का सिलसिला पहली बार 1977 में शुरू हुआ था. जब कश्मीर मोटर ड्राइवर एसोसिएशन के अध्यक्ष गुलाम नबी को जनता पार्टी का समर्थन करने की वजह से पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया. इस कानून के तहत होने वाली यह पहली गिरफ्तारी थी. यानी जंगल तस्करों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाए गए कानून का पहला इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों से निपटने के लिए किया गया.

मानवाधिकार की अंतरराष्ट्रीय संस्था ने हाल ही में पब्लिक सेफ्टी एक्ट को अंधा कानून करार दिया. अपनी रिपोर्ट में एमनेस्टी ने कहा कि 1991 से अबतक कश्मीर में 20 हजार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. मौजूदा उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने वर्ष 2004 में उस वक्त की यूपीए सरकार के द्वारा स्थापित वर्किंग ग्रुप के प्रमुख की हैसियत से कहा था कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के जरिए मानवाधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है. दिलचस्प बात यह है कि इस कानून का इस्तेमाल हर सरकार करती रही है. साल 2008 से 2014 तक नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस के शासन काल में 1127 लोगों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था. जबकि मौजूदा सरकार भी खासतौर पर पिछले महीने से इस कानून का अंधाधुंध इस्तेमाल करने में लगी हुई है. साफ जाहिर है कि कश्मीर में पुलिस के द्वारा मानवाधिकार हनन का सबसे बड़ा हथियार पब्लिक सेफ्टी एक्ट ही है. यह कानून जब तक लागू रहेगा, कसूरवारों के साथ-साथ न जाने कितने बेकसूर लोग भी इसकी बलि चढ़ते रहेंगे. ■

## यूपी में अति पिछड़ी जातियों को राजनीतिक दल फिर पकड़ाने लगे झुनझुना

# सामाजिक अन्याय की सियासत

सूफी यायावर

विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ी जातियों का आरक्षण ओबीसी कोटे से अलग करने की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है. ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट समेत कई सामाजिक-राजनीतिक संस्थाओं ने यह मांग की है. उत्तर प्रदेश में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण कोटा उपलब्ध है, लेकिन उसमें अतिपिछड़ी जातियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है. अति पिछड़ी जातियों की तादाद लगभग 33 प्रतिशत है. इस आबादी के आरक्षण लाभ का बड़ा हिस्सा ओबीसी की अगड़ी जातियां मसलन, यादव, कुर्मी और जाटों द्वारा हथिया ली जा रही हैं. लिहाजा, अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ तभी मिल सकता है जब उनकी आबादी के अनुसार उनका कोटा अलग कर दिया जाए.

मंडल आयोग ने भी अति पिछड़ी जातियों को अलग कोटा देने की बात कही थी. बिहार में यह व्यवस्था कर्पूरी ठाकुर फार्मूले के अंतर्गत काफी समय से लागू है. उत्तर प्रदेश में भी इसी उद्देश्य से 1976 में डॉ. छेदी लाल साथी की अध्यक्षता में सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था. आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पिछड़ी जातियों के कोटे को तीन हिस्सों, पिछड़े वर्ग की अगड़ी जातियों, हिन्दू अति पिछड़ी जातियों और मुस्लिम अति पिछड़ी जातियों में उनकी आबादी के अनुपात में बांटने की संस्तुति की थी, लेकिन उसे आजतक लागू नहीं किया गया. इसके विपरीत सपा और बसपा उन जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का झूठा आश्वासन देकर उनका वोट बटोरने की कोशिश करती रही है. किसी जाति को उस सूची में डालने या निकालने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है, प्रदेश सरकार को नहीं. फिर भी राजनीतिक पार्टियां इन जातियों को गुमराह करने में लगी हैं. सपा ने भी ऐसा ही किया. कांग्रेस ने अति पिछड़ी जातियों का कोटा अलग करने की मांग उठाई है, लेकिन यह इन जातियों को सामाजिक न्याय दिलाने के बजाय केवल चुनावी फायदा उठाने का नारा दिख रहा है. ऐसे में सामाजिक-राजनीतिक संस्थाओं की तरफ से यह मांग उठ रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुतियों को लागू कर अतिपिछड़ी जातियों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में ओबीसी कोटे में से अलग कोटा निर्धारित करे ताकि उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिल सके.

दूसरी तरफ कांग्रेस यह वादा कर रही है कि अगर वह सत्ता में आई तो आरक्षण के लाभ से वंचित रही अति पिछड़ी जातियों के लिए ओबीसी कोटे के भीतर अलग से आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा. कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी की यूपी के अति पिछड़े नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद लिया था. लेकिन कांग्रेस भी अति पिछड़ों का आरक्षण कोटा अलग करने की बात नहीं कर रही है. राष्ट्रीय निषाद संघ के राष्ट्रीय सचिव लौटन राम निषाद का कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने भी अति पिछड़ी जातियों को बेवकूफ बनाने का काम किया है. सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने भी 17 अति पिछड़ी जातियों को अनूसचित जाति की सूची में डालने की घोषणा कर उन्हें भ्रमित किया. मुलायम ने 17 अति पिछड़ी जातियों के नेताओं के साथ बैठक की और तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री राम गोविन्द चौधरी को एक समाह में 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया. जबकि किसी भी जाति या समुदाय को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में शामिल करने या विलोपित करने का अधिकार सिर्फ भारतीय संसद के पास है. इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है. साढ़े चार साल तक मुलायम सिंह यादव को 17 अति पिछड़ी जातियों की चिन्ता नहीं रही, लेकिन अब चुनाव सामने देखते हुए इन जातियों को भ्रमित करने व वोट बैंक हथियाने का कुचक्र किया जाने लगा. निषाद ने कहा कि अगर मुलायम 17 अति पिछड़ी जातियों को सामाजिक न्याय व आरक्षण का लाभ देना चाहते हैं तो मल्लाह, मांझी, केवट, बिन्द को मझवार नाम से, गोड़िया, धुरिया, रैकवार, कहार आदि को गोड़ नाम से, धीवर, धीमर को तुरैहा नाम से तथा राजभर को पासी, तड़माली नाम से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करने का शासनादेश निर्गत कराएं या 17 अति पिछड़ी जातियों को 7.5 प्रतिशत आरक्षण कोटा व ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाएं. निषाद यह भी कहते हैं कि अखिलेश सरकार ने मछुआ आवास को लोहिया आवास के पैटर्न पर बनाने का निर्णय लिया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. बड़ी सफाई से निषाद और मछुआ जातियों को बेवकूफ बना दिया गया. मछुआ आवास योजना के तहत 1435 आवास बनाने के लिए बजट आवंटित किया गया था. उत्तर प्रदेश सरकार ने मछुआ आवास बनाने का शासनादेश भी जारी किया, लेकिन मात्र 425 आवास का ही लक्ष्य रखा गया जो केंद्र सरकार के बजट में समायोजित कर दिया गया. राज्य सरकार ने इसके लिए कोई नया बजट जारी नहीं किया. इसी तरह 17 अति पिछड़ी जातियों को 30 विभाग की 76 योजनाओं में 7.5 प्रतिशत मात्रात्मक आरक्षण का शासनादेश लोकसभा चुनाव से पूर्व मार्च-2014 में ही जारी किया गया था, लेकिन इसका लाभ इन जातियों को आज तक नहीं मिला. सपा सरकार ने मात्रात्मक आरक्षण के नाम पर अति पिछड़ी जातियों को सिर्फ लॉलीपॉप दिखाने का काम किया. निषाद ने कहा कि यदि सरकार 17 अति पिछड़ी जातियों को सामाजिक न्याय देने की पक्षधर होती तो शिक्षा, नौकरियों व पंचायतों में 7.5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करती. 1959 से विमुक्त जातियों मल्लाह, केवट, कहार, लोध, बंजारा, भर, नायक, औंधिया, मेवाती आदि को अनुसूचित जनजाति के समान शिक्षण-प्रशिक्षण में आरक्षण मिल रहा था, जिसे अखिलेश सरकार ने 10 जून 2013 को समाप्त कर दिया. सपा सरकार अति पिछड़ी जातियों को हर स्तर पर पीछे करने व सामाजिक-राजनीतिक न्याय से वंचित करने का काम कर रही है. सपा के शासनकाल में समाजवाद के नाम पर केवल एक परिवार व जाति को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है. निषाद ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वर्ष 2013 में ही मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिए जाने व मछुआ आयोग का गठन करने की घोषणा की थी. लेकिन, अभी तक उनकी ये दोनों घोषणाएं हवा-हवाई ही साबित हुई हैं. ■

# 5 साल पहले चौथी दुनिया ने बताया था कैसे चलता है नक़ली नोट का खेल

# नोटबन्दी के दौर में नक़ली नोट का ख़तरा

**अगस्त 2010 में सीबीआई की टीम ने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के वॉल्ट में छापा मारा. सीबीआई अधिकारियों का दिमाग़ तब सन्न रह गया, जब उन्हें पता चला कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के ख़ज़ाने में नक़ली नोट हैं. रिज़र्व बैंक से मिले नक़ली नोट वही थे, जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी नेपाल के रास्ते भारत भेज रही है. सवाल यह है कि भारत के रिज़र्व बैंक में नक़ली नोट कहां से आए? क्या आईएसआई की पहुंच रिज़र्व बैंक की तिजोरी तक है या फिर कोई बहुत ही भयंकर साज़िश है, जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को खोखला कर चुकी है. अब सवाल यह है कि सीबीआई को मुंबई के रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में छापा मारने की ज़रूरत क्यों पड़ी?**

चौथी दुनिया ब्यूरो

8 नवंबर को विमुद्रीकरण की घोषणा के बाद 14 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 500 और 1000 के पुराने नोट अमान्य हो गए. इन पैसों को बैंक में जमा करना है, ताकि ग्राहकों को नए नोट मिल सकें. जाहिर है, ये एक बहुत बड़ी रकम है, इतना नोट छापने में काफी समय लगेगा. यही वजह है कि बैंक और एटीएम से निकासी की सीमा तय की गई है, ताकि सभी को जरूरत भर का पैसा मिल सके. आरबीआई के मुताबिक 24 घंटे नए नोट की छपाई चल रही है. खैर, यह एक सरकारी प्रक्रिया है, इसमें जितना वक्त लगना है, लगेगा. लेकिन, हम यहां अपने पाठकों और सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं. हम यहां उन्हीं बातों को दोहराना चाहते हैं, जिसे चौथी दुनिया साल 2010 से लिखता आ रहा है. एक-एक कर हम बिन्दुवार इन मुद्दों पर फिर से चर्चा करेंगे, जिन पर हमने 2010 से 2012 के बीच चर्चा की थी. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भारत में छपने वाले नोटों के लिए कागज और इंक विदेश से आते हैं. इस पर कुल छपाई का 40 फीसदी पैसा खर्च होता है. संभवत:, जो कंपनियां भारत को ये कागज और इंक देती हैं, वही कंपनियां कागज और इंक पाकिस्तान को भी देती हैं. बहरहाल, आज की बात करें तो अभी तक ये स्थिति साफ नहीं है कि क्या हम विदेशों से भी नोट छपवाने की सोच रहे हैं या हम अपना सारा नोट खुद ही छापेंगे. (ध्यान रखिए, अगर हम खुद भी छापेंगे तो भी कागज और इंक विदेश से ही आना है). यदि किसी सूरत में हमें विदेशों से नोट छपवाना पड़ा तो हमें क्या सावधानी रखनी होगी. हम इस पर भी चर्चा करेंगे.

## विदेश में नोट छपाई के ख़तरे

साल 2010 में संसद की एक समिति ने भारतीय नोटों की छपाई के संबंध में जो बातें कहीं, वे ख़ासी चिंताजनक थीं. वी किशोर चंद्र एस देव की अध्यक्षता में लोकसभा की सरकारी उपक्रम से संबंधित समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 1997-98 के दौरान भारत सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये मूल्य के बराबर भारतीय नोटों की छपाई विदेशों में कराई. इससे पहले और इसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ. एक लाख करोड़ रुपये के उक्त नोट अमेरिका, जर्मनी और इंग्लैंड में छपवाए गए थे. समिति ने अपनी रिपोर्ट में साफ-साफ कहा कि भारतीय नोटों की विदेशों में छपाई का मामला एक तरह से भारत की आर्थिक संप्रभुता को ख़तरे में डालने के बराबर था. चिदंबरम के वित्त मंत्री रहते ही एक लाख करोड़ रुपये मूल्य के बराबर के सौ और पांच सौ रुपये के नोट ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी की कंपनियों में छपवाए गए थे. वी किशोर चंद्र देव की अध्यक्षता वाली समिति ने जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) से विदेशों में नोट छपवाने की वजह जाननी चाही, तो इस पर आरबीआई का जवाब था कि उस वक्त उसकी विभिन्न शाखाओं को जितने नोटों की आवश्यकता थी, भारतीय टकसाल उनकी आपूर्ति कर पाने में सक्षम नहीं थी. इसके अलावा कटे-फटे और पुराने नोटों की संख्या भी ज़्यादा हो गई थी और उसे जल्द से जल्द नए नोट चाहिए थे. आंकड़ों के मुताबिक, 1996-97 के दौरान आरबीआई को 3 लाख 35 हज़ार 900 करोड़ रुपये मूल्य के बराबर नोटों की ज़रूरत थी. जबकि उस वक्त कुल उत्पादन (छपाई) सिर्फ 2 लाख 16 हज़ार 575 करोड़ रुपये मूल्य के बराबर ही था. इस तरह आरबीआई को एक लाख 20 हज़ार करोड़ रुपये मूल्य के बराबर नोटों की ज़रूरत थी. यही कारण बताकर आरबीआई और तत्कालीन सरकार के वित्त मंत्री ने विदेशी एजेंसियों से भारतीय नोट छपवाने का निर्णय लिया था. आरबीआई के लिखित जवाब के मुताबिक, नोट छपाई में अपनाए गए विशेष सुरक्षा मानकों के रख-रखाव, छपाई से पहले और अनुबंध ख़त्म होने के बाद की ज़िम्मेदारी छपाई करने वाली कंपनी की थी. इसके अलावा नोट छापने के लिए ज़रूरी प्लेट्स के निर्माण की ज़िम्मेदारी भी कंपनी की थी. इतना ही नहीं, फोटो प्रिंट, डाई एवं नंबरिंग बॉक्स इत्यादि की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी भी उक्त कंपनियों की ही थी. ज़ाहिर है, जिस कंपनी के पास नोट छपाई के बारे में इतनी जानकारी है, वह यदि चाहे तो कभी भी इसका दुरुपयोग कर सकती है. एक ही नंबर के कई लाख नोट छाप सकती है. प्लेट्स या डाई का इस्तेमाल बाद में कर सकती है. ऐसे में अगर संसदीय समिति ने यह चिंता जाहिर की कि यह निर्णय देश की आर्थिक संप्रभुता को ख़तरे में डालने के बराबर था तो इसे आधारहीन नहीं माना जा सकता.

**1997-98 में विदेशों में छपवाए गए नोट**

| | |
|---|---|
| अमेरिकन बैंक नोट कंपनी (अमेरिका) | 635 मिलियन पीस (100 रुपये के नोट). |
| थॉमस डी ला रियू ( इंग्लैंड) | 1365 मिलियन पीस (100 रुपये के नोट). |
| जीसेके एंड डेब्रिएंट कंसोर्टियम(जर्मनी) | 1600 मिलियन पीस (500 रुपये के नोट). |

## नक़ली नोट, रिजर्व बैंक और सरकार

अगस्त 2010 में सीबीआई की टीम ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वॉल्ट में छापा मारा. सीबीआई अधिकारियों का दिमाग़ तब सन्न रह गया, जब उन्हें पता चला कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के ख़ज़ाने में नक़ली नोट हैं. रिज़र्व बैंक से मिले नक़ली नोट वही थे, जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी नेपाल के रास्ते भारत भेज रही है. सवाल यह है कि भारत के रिजर्व बैंक में नक़ली नोट कहां से आए? क्या आईएसआई की पहुंच रिज़र्व बैंक की तिजोरी तक है या फिर कोई बहुत ही भयंकर साज़िश है, जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को खोखला कर चुकी है. अब सवाल यह है कि सीबीआई को मुंबई के रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में छापा मारने की ज़रूरत क्यों पड़ी? रिजर्व बैंक से पहले नेपाल बॉर्डर से सटे बिहार और उत्तर प्रदेश के 70-80 बैंकों में छापा पड़ा. इन बैंकों में छापा इसलिए पड़ा, क्योंकि जांच एजेंसियों को ख़बर मिली कि पाकिस्तान की खुफ़िया एजेंसी आईएसआई नेपाल के रास्ते भारत में नक़ली नोट भेज रही है. बॉर्डर के इलाक़े के बैंकों में नक़ली नोटों का लेन-देन हो रहा है. आईएसआई के रैकेट के ज़रिए 500 रुपये के नोट 250 रुपये में बेचे जा रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि रिज़र्व बैंक में मिले नक़ली नोट वही नोट थे, जिन्हें आईएसआई नेपाल के ज़रिए भारत भेजती है.

**तहक़ीक़ात के दौरान एक सनसनीखेज सच सामने आया. डे ला रू कैश सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 2005 में सरकार ने दफ्तर खोलने की अनुमति दी. यह कंपनी करेंसी पेपर के अलावा पासपोर्ट, हाई सिक्योरिटी पेपर, सिक्योरिटी प्रिंट, हॉलोग्राम और कैश प्रोसेसिंग सोल्यूशन में डील करती है. यह भारत में असली और नक़ली नोटों की पहचान करने वाली मशीन भी बेचती है. मतलब यह है कि यही कंपनी नक़ली नोट भारत भेजती है और यही कंपनी नक़ली नोटों की जांच करने वाली मशीन भी लगाती है. शायद यही वजह है कि देश में नक़ली नोट भी मशीन में असली नज़र आते हैं. इस मशीन के सॉफ्टवेयर की अभी तक जांच नहीं की गई है, किसके इशारे पर और क्यों?**

## डे ला रू और नक़ली नोट

सवाल उठता है कि ये नक़ली नोट छापता कौन है. हमारी तहक़ीक़ात डे ला रू नामक कंपनी तक पहुंची. जो जानकारी मिली, उससे यह साबित होता है कि नक़ली नोटों के कारोबार की जड़ में यही कंपनी है. डे ला रू कंपनी का सबसे बड़ा करार रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ था, जिसे यह स्पेशल वाटरमार्क वाला बैंक नोट पेपर सप्लाई करती रही है. पिछले कुछ समय से इस कंपनी में भूचाल आया हुआ है. जब रिजर्व बैंक में छापा पड़ा तो डे ला रू के शेयर लुढ़क गए. यूरोप में ख़राब करेंसी नोटों की सप्लाई का मामला छा गया. इस कंपनी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कुछ ऐसे नोट भी दे दिए, जो असली नहीं थे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की टीम इंग्लैंड गई, उसने डे ला रू कंपनी के अधिकारियों से बातचीत की. नतीजा यह हुआ कि कंपनी ने हंपशायर की अपनी यूनिट में उत्पादन और आगे की शिपमेंट बंद कर दी. डे ला रू कंपनी के अधिकारियों ने भरोसा दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह कहा कि कंपनी से जुड़ी कई गंभीर चिंताएं हैं. अंग्रेजी में कहें तो सीरियस कंसर्नस. टीम वापस भारत आ गई. डे ला रू कंपनी की 25 फीसदी कमाई भारत से होती है. इस ख़बर के आते ही डे ला रू कंपनी के शेयर धराशायी हो गए. यूरोप में हंगामा मच गया, लेकिन हिंदुस्तान में न वित्त मंत्री ने कुछ कहा, न ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई बयान दिया. रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधियों ने जो चिंताएं जताईं, वे कैसी हैं. इन चिंताओं की गंभीरता कितनी है. रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ डील बचाने के लिए कंपनी ने माना कि भारत के रिज़र्व बैंक को दिए जा रहे करेंसी पेपर के उत्पादन में जो ग़लतियां हुईं, वे गंभीर हैं. बाद में कंपनी के चीफ एक्जीक्यूटिव जेम्स हसी को 13 अगस्त, 2010 को इस्तीफ़ा देना पड़ा.

5 जनवरी, 2011 को यह ख़बर आई कि भारत सरकार ने डे ला रू के साथ अपने संबंध ख़त्म कर लिए. पता चला कि 16,000 टन करेंसी पेपर के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने डे ला रू की चार प्रतियोगी कंपनियों को ठेका दे दिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डे ला रू को इस टेंडर में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित भी नहीं किया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? इस फैसले के पीछे क्या तर्क हैं? सरकार ने संसद को भरोसे में क्यों नहीं लिया? 28 जनवरी को डे ला रू कंपनी के टिम कोबोल्ड ने यह भी कहा कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि डे ला रू का अब आगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ कोई समझौता होगा या नहीं. इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी डे ला रू से कौन बात कर रहा है और क्यों कर रहा है?

तहक़ीक़ात के दौरान एक सनसनीखेज सच सामने आया. डे ला रू कैश सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 2005 में सरकार ने दफ्तर खोलने की अनुमति दी. यह कंपनी करेंसी पेपर के अलावा पासपोर्ट, हाई सिक्योरिटी पेपर, सिक्योरिटी प्रिंट, हॉलोग्राम और कैश प्रोसेसिंग सोल्यूशन में डील करती है. यह भारत में असली और नक़ली नोटों की पहचान करने वाली मशीन भी बेचती है. मतलब यह है कि यही कंपनी नक़ली नोट भारत भेजती है और यही कंपनी नक़ली नोटों की जांच करने वाली मशीन भी लगाती है. शायद यही वजह है कि देश में नक़ली नोट भी मशीन में असली नज़र आते हैं. इस मशीन के सॉफ्टवेयर की अभी तक जांच नहीं की गई है, किसके इशारे पर और क्यों? जांच एजेंसियों को अविलंब ऐसी मशीनों को जब्त करना चाहिए, जो नक़ली नोटों को असली बताती है. सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिए कि डे ला रू कंपनी के रिश्ते किन-किन आर्थिक संस्थानों से हैं. नोटों की जांच करने वाली मशीन की सप्लाई कहां-कहां हुई है?

## डे ला रू का नेपाल और आईएसआई कनेक्शन

कंधार हाईजैक की कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन इस अध्याय का एक ऐसा पहलू है, जो अब तक दुनिया की नज़र से छुपा है. नेपाल से अपहृत भारतीय विमान में एक ऐसा शख्स बैठा था, जिसके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे. इस आदमी को दुनिया भर में करेंसी किंग के नाम से जाना जाता है. इसका असली नाम है रोबर्टो ग्योरी. रोबेर्टो खुद दो देशों की नागरिकता रखता है, जिसमें पहला है इटली और दूसरा स्विट्जरलैंड. रोबेर्टो को करेंसी किंग इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह डे ला रू नाम की कंपनी का मालिक है. दुनिया की करेंसी छापने का 90 फीसदी बिजनेस इस कंपनी के पास है. यह कंपनी दुनिया के कई देशों के नोट छापती है. यही कंपनी पाकिस्तान की आईएसआई के लिए भी काम करती है. जैसे ही यह जहाज हाईजैक हुआ, स्विट्जरलैंड ने एक विशिष्ट दल को हाईजैकर्स से बातचीत करने कंधार भेजा. साथ ही उसने भारत सरकार पर यह दबाव बनाया कि वह किसी भी क़ीमत पर करेंसी किंग रोबेर्टो ग्योरी और उनके मित्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करे. ग्योरी बिजनेस क्लास में सफ़र कर रहा था. आर्तकियों ने उसे प्लेन के सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा दिया. लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन ग्योरी आराम से अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था. उसके पास सैटेलाइट, पेन ड्राइव और फोन थे. यह आदमी कंधार के हाईजैक जहाज में क्या कर रहा था, यह बात किसी की समझ में नहीं आई है. नेपाल में ऐसी क्या बात है, जिससे स्विट्जरलैंड के सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया भर के नोटों को छापने वाली कंपनी के मालिक को वहां आना पड़ा.■

feedback@chauthiduniya.com

# केजरीवाल के 7 चुनावी मंत्र

जिस तरह दिल्ली में केजरीवाल ने शीला दीक्षित के ऊपर आरोप लगाए या फिर अरुण जेटली पर डीडीसीए में हो रहे भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाए, उसी तरह अब पंजाब में भी अकाली दल नेता मजीठिया और उप-मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर भी आरोप लगा रहे हैं. उन्हें जेल भेजने की घोषणा प्रत्येक भाषण में की जा रही है. यही केजरीवाल का कट-पेस्ट फार्मूला है, जिसका इस्तेमाल वे पंजाब विधानसभा चुनाव में कर रहे हैं. केजरीवाल का सातवां मंत्र उनकी संगठन क्षमता है. 2014 में आप ने पूरे देश में 432 उम्मीदवार खड़े किये थे. उम्मीदवारों की यह संख्या भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों से भी ज़्यादा थी. लोकसभा चुनाव में बुरी तरह विफल होने के बाद केजरीवाल को समझ में आ गया कि केवल मीडिया में हवा बनाकर चुनाव नहीं जीता जा सकता.

हेमेन्द्र झा

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने बहुत ही कम समय में देश के राजनैतिक बिसात पर एक सफल और विशिष्ट भूमिका तैयार कर ली है. 2015 में दिल्ली की 2 करोड़ जनता को लुभाकर 70 में से 67 सीटें जीत लेना उनकी बड़ी उपलब्धि थी. हालांकि जिस तरह वे और उनके विधायक लगातार विवादों में फंस रहे हैं, उससे दिल्ली का विकास जरूर बाधित हो रहा है. इस कारण आम आदमी पार्टी की किरकिरी हो रही है. केजरीवाल ने गत महीनों में दिल्ली का उत्तरदायित्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सौंप दिया है. वे अपना अधिकतम समय पंजाब के विधानसभा चुनाव की तैयारी करने में लगा रहे हैं. ज्ञात हो कि आम आदमी पार्टी पंजाब और गोवा में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है. रोचक बात यह है कि इन दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी की जीत की संभावना से अभी इनकार नहीं किया जा सकता है. भाजपा और कांग्रेस पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व भी आम आदमी पार्टी के इन राज्यों में बढ़ते हुए कद पर नजर रखे हैं. आखिर केजरीवाल के चुनावी मंत्र क्या हैं? जनता की ऐसी कौन सी नब्ज़ पर हाथ रखे हैं, जिसे थामे वे अपनी पार्टी को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ा रहे हैं.

सर्वप्रथम, केजरीवाल की रणनीति उन राज्यों में चुनाव लड़ने की है, जिनमें भाजपा और कांग्रेस के बीच द्विध्रुवी संघर्ष रहता है. यह केजरीवाल का पहला चुनावी मंत्र है. दिल्ली में आम आदमी पार्टी की फरवरी 2015 में अभूतपूर्व जीत का सबसे बड़ा कारण इसी तथ्य को माना जा सकता है. ऐसे राज्यों में जनता के पास कोई तीसरा मजबूत विकल्प नहीं होता है. इन राज्यों में बारी-बारी से या तो भाजपा की सरकार बनती रही है या कांग्रेस की. ऐसा हर 5-10 साल में होता रहता है. राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड आदि राज्य ऐसे उदाहरण हैं. वर्ष 2012 में पंजाब के पिछले विधानसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल, जो भाजपा की लंबे समय से सहयोगी पार्टी रही है, को राज्य में बहुमत मिला और अकाली दल-भाजपा ने कुल 117 में से 68 सीटों पर बहुमत हासिल किया. कांग्रेस को सिर्फ 46 सीटें ही मिलीं. जहां अकाली दल-भाजपा का मत प्रतिशत लगभग 42 प्रतिशत था वहीं कांग्रेस को 40 प्रतिशत मत मिले थे. परंतु 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बढ़-चढ़कर अपने उम्मीदवार उतारे. देश के तमाम हिस्सों में तो आम आदमी पार्टी के अधिकतर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गयी, पर पंजाब में अप्रत्याशित रूप से केजरीवाल को सफलता मिली. आप को पंजाब लोकसभा चुनाव में 24.4 प्रतिशत मत मिले, जहां कांग्रेस का मत प्रतिशत 12.5 प्रतिशत, अकाली दल का 7.5 प्रतिशत और भाजपा का 1.5 प्रतिशत गिरा. गौरतलब है कि आप को जो वोट पंजाब में मिले, वो इन्हीं पार्टियों के वोट बैंक में सेंध लगाने से मिले. लोक सभा में 4 सीटें जीतने के बाद केजरीवाल का मनोबल काफी ऊंचा हो गया और अब 2017 में आम आदमी पार्टी पंजाब के सभी 117 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है.

**केजरीवाल की रणनीति उन राज्यों में चुनाव लड़ने की है, जिनमें भाजपा और कांग्रेस के बीच द्विध्रुवी संघर्ष रहता है. यह केजरीवाल का पहला चुनावी मंत्र है. दिल्ली में आम आदमी पार्टी की फरवरी 2015 में अभूतपूर्व जीत का सबसे बड़ा कारण इसी तथ्य को माना जा सकता है. ऐसे राज्यों में जनता के पास कोई तीसरा मजबूत विकल्प नहीं होता है. इन राज्यों में बारी-बारी से या तो भाजपा की सरकार बनती रही है या कांग्रेस की. ऐसा हर 5-10 साल में होता रहता है.**

गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में यूं तो कांग्रेस पार्टी सक्रिय है, परंतु पिछले तीन विधानसभा चुनावों में भाजपा को लगातार बहुत मिली है. पंजाब और गोवा के बाद केजरीवाल की मंशा इन्हीं राज्यों में पैर पसारने की है. इस तरह के राज्यों की जनता को लुभाना केजरीवाल के लिए आसान होता है, क्योंकि जनता एक नए बदलाव के लिए तैयार रहती है. पंजाब में किसानों के पुराने ऋण माफ कराने, शराब और ड्रग माफिया से आज़ादी और करदाताओं के बोझ को हल्का करने का वादा इसी लोक-लुभावन रणनीति के तहत आप पार्टी कर रही है.

केजरीवाल का दूसरा मंत्र मोदी की नीतियों का हर संभव विरोध करना है. विपक्षी पार्टियों के अनुसार मीडिया में बने रहने के लिए केजरीवाल के लिये यह सबसे आसान तरीका है. नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण नीति से राजनैतिक पार्टियों की सारी गोटियों को तितर-बितर कर दिया है. विमुद्रीकरण नीति का समाधान काले धन पर कितना असरदार होगा या गरीबों को मूलभूत सुविधाएं दिलाने में कितना कारगर होगा, यह अभी विवेचना का विषय है. इसके लिए 30 दिसंबर तक का हमें इंतज़ार करना चाहिए. केजरीवाल का तीसरा चुनावी मंत्र उनका अपना एक अलग सामाजिक-आर्थिक वर्ग उत्कीर्ण करना है. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की नब्ज़ पर उनकी अच्छी पकड़ है. रेहड़ी-पटरी वाले, छोटे व्यापारी, रोजाना दिहाड़ी पर काम करने वाले मज़दूर और कारीगर पूरे जोर-शोर से उनकी पार्टी को वोट करते हैं. यही कारण है कि 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में 77 प्रतिशत मुस्लिम मतदाताओं और 57 प्रतिशत सिख मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया.

उनका चौथा, पांचवां और छठा मंत्र मुफ्त चीजें बांटना, बड़े-बड़े वादे करना और सत्तारूढ़ सरकार के नेताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप लगाना है. केजरीवाल की इन तीनों दक्षताओं पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है. केजरीवाल के ये तीनों मंत्र कट-पेस्ट फॉर्मूले की तरह काम करते हैं. जिस तरह दिल्ली में उन्होंने मुफ्त बिजली, पानी और इंटरनेट देने का वादा किया, उसी तरह पंजाब में भी किसानों के पुराने कर्जे माफ़ करने का वादा जोर-शोर से किया जा रहा है. हालांकि, किसानों के लिए सर छोटू राम एक्ट, 1934 को फिर से अधिनियमित करने का प्लान केजरीवाल की एक अच्छी पहल है, जिसके तहत ब्याज की राशि कभी भी मूल क़र्ज़ से ज़्यादा नहीं हो सकती. ये काफी फिक्र की बात है कि पंजाब के 85 प्रतिशत किसान क़र्ज़ में डूबे हैं और राज्य में किसानों पर करीबन 70,000 करोड़ का क़र्ज़ है. कुल क़र्ज़ की राशि में से 13,000 करोड़ की राशि निजी सूदखोरों की है, जो ब्याज समय पर नहीं मिलने पर बाहुबल का इस्तेमाल कर किसानों की ज़मीन आसानी से हड़प सकते हैं. पंजाब में प्रत्येक छोटे किसान पर करीब पौने तीन लाख रुपये का क़र्ज़ है और मध्यवर्गीय किसानों पर साढ़े पांच लाख रुपये का क़र्ज़ है. जिस तरह दिल्ली में केजरीवाल ने शीला दीक्षित के ऊपर आरोप लगाए या फिर अरुण जेटली पर डीडीसीए में हो रहे भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाए, उसी तरह अब पंजाब में भी अकाली दल नेता मजीठिया और उप-मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं. उन्हें जेल भेजने की घोषणा प्रत्येक भाषण में की जा रही है. यही केजरीवाल का कट-पेस्ट फार्मूला है, जिसका इस्तेमाल वे पंजाब विधानसभा चुनाव में कर रहे हैं. केजरीवाल का सातवां मंत्र उनकी संगठन क्षमता है. 2014 में आप ने पूरे देश में 432 उम्मीदवार खड़े किये थे. उम्मीदवारों की यह संख्या भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों से भी ज़्यादा थी. लोकसभा चुनाव में बुरी तरह विफल होने के बाद केजरीवाल को समझ में आ गया कि केवल मीडिया में हवा बनाकर चुनाव नहीं जीता जा सकता. चुनाव जीतने के लिए एक मजबूत राजनैतिक संगठन का होना ज़रूरी है. पंजाब-जोड़ो अभियान के तहत आप ने पंजाब में लगभग दस लाख लोगों को पार्टी की मेंबरशिप दी है. लोकसभा चुनाव के दौरान पंजाब में आप के मेंबर्स की संख्या सिर्फ कुछ हज़ार थी. आज पंजाब के सभी 22 जिलों में, प्रत्येक बूथ लेवल पर केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं को नियुक्त करने में सफल रहे हैं. आप की राज्य इकाई के संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर के निष्कासन के बाद से ही आप की पंजाब में जीत की संभावनाओं पर तीन महीनों से प्रश्नचिन्ह लग रहा है. यूथ मेनिफेस्टो में अपने चुनाव चिन्ह झाड़ू को गोल्डन टेम्पल के साथ-साथ छाप देना भी पंजाब के लोगों को उचित नहीं लगा. इससे पार्टी की पंजाब में बढ़ती लोकप्रियता को ज़ोरदार धक्का लगा. श्री हरमिंदर साहिब के इस अपमान के लिए केजरीवाल ने प्रायश्चित भी किया और मंदिर परिसर में कप-प्लेट धोए. आप जिस तरह से भाजपा के पूर्व राज्य सभा सदस्य और प्रसिद्ध क्रिकेटर नवजोत सिद्धू को पार्टी में शामिल करने में विफल रही, वह कहीं न कहीं पंजाब में पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा लिए गए लचर फैसलों को दर्शाता है. इन खामियों के बाद भी पिछले सप्ताह भटिंडा और मुक्तसर जिले में आप की रैलियों में लोगों ने काफी रुचि दिखाई और अच्छी-खासी भीड़ जुटी. इन रैलियों में केजरीवाल ने पंजाब की जनता को अपने पुराने अंदाज़ में कहा कि यदि नए नोट कांग्रेस या अकाली दल दें, तो नोट ले लेना पर वोट आप पार्टी को ही करना.

पंजाब चुनाव के बाद हमें साफ-साफ पता चल जाएगा कि दिल्ली की जीत महज़ एक राजनीतिक संयोग था या फिर एक सोची-समझी कूटनीति. अगले 100 दिनों में पंजाब की राजनीति में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.■

feedback@chauthiduniya.com

## तीन दिनी भोपाल इज्तिमा

# 14 लोगों से शुरू हुआ था अब आते हैं 14 लाख

सोरिन शर्मा

आलमी तब्लीगी इज्तिमा का आगाज 26 नवंबर को हुआ था. तब्लीगी इज्तिमा में शरीक होने इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, फिलिपींस, सऊदी अरब, कुवैत, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस व सोमालिया से लोग आए थे. शनिवार की सुबह फजिर की नमाज के साथ मजहबी तकरीरें शुरू हो गईं. इज्तिमा स्थल पर वजू के लिए 9 हजार टोंटियां लगाई गई थीं. शुरुआती दो दिनों में करीब 4 लाख जमाती इज्तिमा स्थल पर मौजूद रहे. इज्तिमा कमेटी के प्रवक्ता अतीक अल इस्लाम ने बताया कि इज्तिमा स्थल पर एक महीने से तैयारियां चल रही थीं. भोपाल में तीन दिनी आलमी तब्लीगी इज्तिमें का आगाज मजहबी तफरीरों और अल्लाह के बताये रास्ते पर चलने की नसीहत के साथ हुआ. इज्तिमे के कुछ समय पहले राजधानी में हुए जेल ब्रेक कांड और विदिशा में हुई सांप्रदायिक झड़प को देखते हुए प्रशासन ने इस वर्ष सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे.

### क्लीन एंड ग्रीन की तर्ज पर हुआ इज्तिमा

आलमी तब्लीगी इज्तिमा के दौरान इज्तिमागाह क्लीन और ग्रीन की तर्ज पर संपन्न हुआ. आयोजन के दौरान कार्यक्रम स्थल पर पॉलीथिन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी थी. यहां सिगरेट, बीड़ी, गुटका, पाउच का सेवन भी प्रतिबंधित था. आलमी तब्लिगी इज्तिमा इन्तजामिया कमेटी के अतीत उल इस्लाम ने बताया कि इज्तिमागाह पर बड़ी तादाद में वालंटियर पहुंचे और तैयारियों को पूरा करने में सहयोग दिया. उन्होंने बताया कि दुनिया भर से आने वाले जमाती यहां से बेहतर इंतजाम और सुखद वातावरण का संदेश अपने साथ लेकर गए. इसी मंशा के साथ इज्तिमागाह को पूरी तरह पॉलीथिन मुक्त जोन घोषित किया गया था.

26 नवंबर की सुबह एक आम सुबह की तरह ही थी, लेकिन भोपाल से 11 किलोमीटर की दूरी पर ईंटखेड़ी के पास ग्राम घासीपुरा में नज़ारा कुछ अलग ही था. फज़िर यानी सुबह की पहली नमाज़ दुनिया भर से आए 50 से ज्यादा जमातों और अन्य इस्लामी धर्मावलंबियों सहित 10 लाख लोगों ने एक साथ अदा की. इससे पहले इज्तिमा स्थल पर 66 एकड़ में लगे पंडाल में जुमे की नमाज़ अदा की गई. इसमें लगभग डेढ़ लाख लोगों ने शिरकत की.

इस धार्मिक समागम में मुख्य रूप से दिल्ली मरकज़, मुम्बई, लखनऊ, अलीगढ़ आदि स्थानों के उलेमाओं के बयान हुए. बयान की शुरुआत दिल्ली के मौलाना जमशेद मोहम्मद से हुआ. यहां होने वाले निकाह और अंतिम दिन की दुआ का भी खास महत्व है. निकाह असिर और मग़रिब के बीच यानी शाम 5 से 6 के बीच संपन्न हुआ तथा दुआ अंतिम दिन सुबह के बयान के बाद 12 बजे हुआ.

### क्या है इज्तिमा

इज्तिमे का शाब्दिक अर्थ होता है, एक स्थान पर लोगों का जमा होना. इसे मज़मा, मजलिस, महफिल सभा या समागम भी कह सकते हैं. तब्लीगी यानी धार्मिक और आलमी मतलब विश्वस्तरीय. इज्तिमा का मुख्य उद्देश्य इस्लाम की शिक्षा के साथ-साथ दुनिया भर में शांति और एकता का संदेश देना भी है. इसमें दिए जाने वाले बयान यानी प्रवचनों में लोगों को अपनी जिंदगी इंसानियत की राह पर चलकर गुजारने की सलाह दी जाती है. इज्तिमे की शुरुआत 67 वर्ष पहले नवाबी दौर में 1946 में भोपाल स्थित मस्जिद शकूर खां में हुई थी. इसमें महज़ 14 लोगों ने शिरकत की थी. मौलाना मिस्कीन साहब ने इसकी नींव रखी थी. कारवां चलना शुरू हुआ तो फिर लगातार चलता रहा, लोग जुड़ते रहे. 1949 में इस सालाना इज्तिमे को नया ठिकाना मिला मस्जिद ताजुल मस्जिद में. बाद में यह तादाद हजारों से होती हुई लाखों में पहुंची तो एशिया की यह सबसे बड़ी मस्जिद भी छोटी पड़ने लगी. इसे ग्यारह साल पहले शहर से 11 किलोमीटर दूर घासीपुरा में शिफ्ट करना पड़ा.

50 से ज्यादा जमातें, पाक-बांग्लादेश को आमंत्रण नहीं

इसमें देश-विदेश से 50 से ज्यादा जमातें शरीक हुई थीं. आईएसआईएस के युद्ध के चलते सीरिया की जमात नहीं पहुंची, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश को बुलाया ही नहीं गया था.■

feedback@chauthiduniya.com

# बिहार

# भाजपाइयों ने ज़मीन में खपाया कालाधन!

चौथी दुनिया ब्यूरो

आठ नवंबर को नोटबंदी की अचानक की गयी घोषणा के बाद जैसे हालात उत्पन्न हुए वे इतने अप्रत्याशित थे कि न तो केंद्र सरकार और न ही भारतीय जनता पार्टी ने इसकी कल्पना की थी. केंद्र के इस फैसले के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक प्रभाव आने वाले दिनों में स्पष्ट होते जायेंगे, लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि मोदी सरकार के लिए यह अब तक की सबसे गंभीर चुनौती बन कर सामने आई है. आम लोगों को नोटबंदी से होने वाली भारी दुश्वारियों के बाद विपक्ष के ताबड़तोड़ हमले के बीच बिहार में अचानक भारतीय जनता पार्टी के सामने दूसरी मुसीबत आ कर खड़ी हो गयी. मीडिया के एक हिस्से में यह खबर आयी कि नोटबंदी से एक हफ्ते पहले तक भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के 23 जिलों में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए करोड़ों रुपये की जमीन खरीदी है. खबर इतनी प्रमाणिक थी कि इसके उजागर होने के बाद बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की न सिर्फ बोलती बंद हो गयी बल्कि इस मुद्दे पर उनकी तमाम बहानेबाजियां और तमाम तर्क भी ध्वस्त होते चले गये. विरोधी दलों ने चुभते सवालों के तीर दागने शुरू कर दिये. पूछा जाने लगा कि कालेधन के खिलाफ भाषणबाजी करने वाले भाजपा के नेता बतायें कि क्या उन्होंने नोटबंदी की घोषणा के पहले करोड़ों की जमीन अपने कालेधन को सफेद बनाने के लिए खरीदी? सवाल यह भी किये जाने लगे कि नोटबंदी के एक हफ्ता पहले तक जमीन के प्लॉट खरीदने का यह मतलब तो नहीं कि भाजपा को सरकार ने पहले ही बता दिया था कि वह आठ नवम्बर से पहले हजार और पांच सौ के तमाम नोटों का इस्तेमाल कर ले? ऐसे तमाम आक्रामक सवालों के जवाब के लिए भाजपा न तो पहले से तैयार थी और न ही उसे आभास था कि जमीनों के प्लॉट की खरीद की भनक सार्वजनिक हो पायेगी. लेकिन 25 नवम्बर को यह खबर प्रदेश भाजपा के नेताओं के लिए परेशानी का सबब बन गयी. इसकी अपेक्षा नहीं होने के कारण यह स्वाभाविक था कि भाजपा नेताओं ने जवाब देने में गलतियां की और उन्हें फजीहत तक झेलनी पड़ी.

सबसे पहले, विधानसभा सत्र की शुरुआत के दिन पत्रकारों ने विधान मंडल के विरोधी दल के नेता सुशील मोदी को घेरा. उनसे जमीन खरीदने से संबंधित सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाजपा पिछले दो वर्षों से हर जिले में कार्यालय बनाने के लिए जमीन खरीद रही है. नोटबंदी के फैसले से इसका कोई लेना-देना नहीं है. लगे हाथ उन्होंने इन तमाम खरीददारियों में निर्धारित प्रक्रिया अपनाने की बात कही. लेकिन सुशील मोदी का इतना कह देना काफी नहीं था. क्योंकि प्लॉट खरीद के तमाम दस्तावेज सार्वजनिक हो चुके थे, जिनके अवलोकन से यह साफ हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे जुड़े सवालों का जवाब दे पाना कठिन है. ऐसा इसलिए कि जमीनों की खरीद के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह द्वारा अधिकृत किये गए व्यक्तियों या नेताओं से जुड़ा दस्तावेज भी सार्वजनिक हो चुका था. अमित शाह ने अपने लेटर पैड पर भाजपा विधायक संजीव चौरसिया व लालबाबू प्रसाद को लिखित रूप से अधिकृत किया था. उस लेटर पैड पर साफ लिखा था कि 'पार्टी के लिए अचल संपत्ति खरीदने के लिए उन्हें अधिकृत किया जाता है'. ऐसे में अधिकृत किये गये नेता, संजीव चौरसिया और लालबाबू प्रसाद तो पहले मीडिया के सवालों से बचते नजर आये लेकिन बार-बार दोहराये गये सवाल के जवाब में, लालबाबू प्रसाद ने स्वीकार किया कि उन लोगों ने जमीनें नगद पैसे से खरीदी हैं, इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने चंदा दिया है. लालबाबू प्रसाद की इस स्वीकारोक्ति के बाद जमीन खरीद के कुछ ऐसे डिड्स भी सार्वजनिक हो गये जिनमें जमीन बेचने वाले व्यक्ति ने रजिस्ट्रार के समक्ष लिखित में स्वीकार किया था कि उसे जमीन के बदले कैश प्राप्त हुए. इस खुलासे के बाद तो भाजपा नेताओं की बोलती ही बंद हो गयी. यहां यह याद दिलाना जरूरी है कि इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने न्यूज चैनलों से कह दिया था कि पेमेंट आरटीजीएस के माध्यम से किये गये. लेकिन दस्तावेजों के सार्वजनिक होने और लालबाबू प्रसाद की कैश पेमेंट की स्वीकारोक्ति के बाद जैसे बिहार की राजनीति में भूचाल सा आ गया. जदयू के वरिष्ठ प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो यहां तक कह डाला कि भूमि घोटाला ने भाजपा को नंगा कर दिया और इससे उसका दोहरा चेहरा उजागर हो गया है. जबकि जदयू के एक अन्य प्रवक्ता नवल शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने हजार और पांच सौ के नोटों पर रोक लगाने की घोषणा से पहले भाजपा राज्य इकाई को इसकी सूचना दे दी थी. ताकि वे आठ नवंबर, यानी नोटबंदी लागू होने के पहले ही अपने पुराने नोटों का इस्तेमाल कर के उस कालेधन को सफेद कर लें. नवल शर्मा ने मोदी सरकार पर आक्रामक होते हुए कहा कि अपनी पार्टी को नोटबंदी की पूर्व सूचना देना भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा प्रशासकीय विश्वासघात है.

भाजपा इस पूरे मामले में एक दिन की रणनीतिक चुप्पी के बाद नये तेवर में आ गयी. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय ने एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की और जदयू प्रवक्ताओं के ताबड़तोड़ हमले का प्रमाणिक जवाब देने के बजाय उनके हमले का जवाब हमले में देना उचित समझा. उन्होंने तमाम जदयू प्रवक्ताओं को मूर्ख, गंवार और अनपढ़ों की टोली कहा, जिसे पैन कार्ड, आयकर तक की जानकारी नहीं है. पांडेय ने कहा कि जमीन खरीद के लिए भुगतान, आरटीजीएस या इंटरनेट ट्रांसफर के माध्यम से हुई है. जदयू प्रवक्ताओं पर प्रहार में वे यहां तक कह गए कि वह उन्हें इन तकनीकी मामलों पर मुफ्त में प्रशिक्षण देने को तैयार हैं.

भले ही भाजपा नेता मंगल पांडेय या सुशील मोदी बार-बार यह दावा कर रहे हों कि जमीन खरीद का पेमेंट आरटीजीएस के माध्यम से हुआ है, लेकिन बिहार के एक स्थानीय न्यूज चैनल ने जमीन खरीददारी का एक दस्तावेज सार्वजनिक कर दिया जिसमें जमीन के मालिक ने स्वीकार किया कि उसे पैसे कैश में प्राप्त हुए हैं.

उधर राजद ने इस मामले में लम्बी चुप्पी के बाद अपना मुंह खोला. राजद विधायक दल की नेता राबड़ी देवी ने कहा कि देश भर में 600 स्थानों पर भाजपा द्वारा की गयी खरीद की जांच सीबीआई से कराई जाये. उधर नोटबंदी के फैसले और काले धन पर आरोप-प्रत्यारोप के बीच राजद और कांग्रेस का अधिकृत स्टैंड, जदयू से अलग रहा. जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बार-बार नोटबंदी का समर्थन किया. इसलिए जदयू के प्रवक्ताओं ने नोटबंदी के बहाने काले धन को टार्गेट करके भाजपा द्वारा जमीन खरीद के मामले में उस पर हमला बोला. नीतीश कुमार के द्वारा अपने धुर विरोधी भाजपा के नोटबंदी के फैसले का समर्थन करना, भाजपा के लिए यह राहत की बात रही. इसके कारण यह कयासबाजी भी तेज हो गयी कि नीतीश भाजपा के करीब आ रहे हैं. लेकिन नीतीश ने बाद में खुल कर कहा कि नोटबंदी का फैसला सही है, इसलिए वह इसका समर्थन कर रहे हैं. लेकिन दूसरी तरफ उनकी पार्टी ने भाजपा की जमीन खरीद मामले पर अपने हमले में कोई नरमी नहीं बरती. इसलिए भाजपा का पशोपेश में रहना स्वाभाविक है.

अब जरा इस बात पर गौर करें कि जब आठ नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में नोटबंदी की घोषणा की, तो वह इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे थे कि इस कदम का मकसद देश में कालेधन पर पूरी तरह रोक लगाना है. लेकिन दूसरी तरफ अगर उनकी ही पार्टी नोटबंदी के हफ्ता दिन पहले तक कैश पेमेंट दे कर जमीन खरीद रही हो तो विपक्षी दलों का उस करोड़ों रुपये के कैश के लेन-देन और उसके स्रोत के बारे में पूछना कोई गैर मौजू सवाल तो नहीं है. विरोधी दलों के इसी सवाल का जवाब जब मीडिया ने सुशील मोदी से पूछा, तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि इसका हिसाब उनकी पार्टी किसी अन्य पार्टी को क्यों दे? उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर इनकम टैक्स महकमा यह सवाल करेगा तो उनकी पार्टी उसे जवाब देगी. लेकिन सुशील मोदी के जवाब के बाद भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, जो भाजपा को मुश्किल में डालने के लिए काफी है. यह सवाल बिहार सरकार के राजस्व की चोरी से जुड़ा है. राज्य के 23 जिलों में दर्जनों एकड़ जमीन की खरीददारी की गयी. लेकिन इन सौदों में चौंकाने वाली बात यह है कि कई ऐसे प्लॉट जो कमर्शियल प्लॉट घोषित हैं, उनकी आवासीय प्लॉट के नाम पर रजिस्ट्री करायी गयी. यहां यह भी ध्यान देने की बात है कि आवासीय प्लॉट की सरकारी कीमत (सहरसा के बनगांव में) एक लाख 60 हजार रुपये प्रति डिसिमल है जबकि कमर्शियल प्लॉट की कीमत चार लाख 90 हजार रुपये प्रति डिसिमल है. यह प्लॉट सहरसा के बनगांव में 12 अगस्त को खरीदा गया. इसी तरह 19 सितंबर को किशनगंज के फरिंगोला मोहल्ले में 26 डिसिमल जमीन खरीदी गयी. इसे भी कमर्सियल के बजाये आवासीय प्लॉट बताया गया. ध्यान रहे कि आवासीय प्लॉट के नाम पर खरीदी गयी जमीन और कमर्सियल जमीन की कीमत में बहुत फर्क होता है. इन सौदों के कारण सरकार को मिलने वाले राजस्व का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ. हालांकि इस मामले में भाजपा के जमीन खरीदने के लिए अधिकृत लोग जितने दोषी हैं, उतने ही दोषी रजिस्ट्री ऑफिस के पदाधिकारी भी हैं.

भाजपा के लैंड डील का मामला सामने आने के बाद पार्टी का दावा है कि वह राज्य के तमाम 38 जिलों समेत देश के अन्य राज्यों में भी अपना जिला कार्यालय खोलने के लिए जमीन खरीदने में लगी है. अभी तक जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं, उनके अनुसार, उसने 3 जिलों में जमीन खरीद ली है. इसमें खास बात यह है कि जमीन के कुछ प्लॉट नवंबर के पहले हफ्ते खरीदे गये. जबकि पीएम नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा 8 नवम्बर को की. ■

feedback@chauthiduniya.com

## खरीदे गये कुछ प्लॉट

| | |
|---|---|
| अररिया | - 56.50 लाख का प्लॉट |
| किशनगंज | - 70 लाख का प्लॉट |
| पूर्णिया | - 32.2 लाख का प्लॉट |
| कटिहार | - 1.16 करोड़ का प्लॉट |
| मधेपुरा | - 81.1 लाख का प्लॉट |
| मधुबनी | - 73.5 लाख का प्लॉट |
| अरवल | - 32 लाख का प्लॉट |

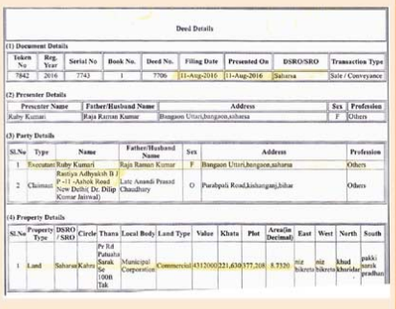



Deed Details

(1) Document Details

| Token No | Reg. Year | Serial No | Book No. | Deed No. | Filing Date | Presented On | DSRO/SRO | Transaction Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7842 | 2016 | 7743 | 1 | 7706 | 11-Aug-2016 | 11-Aug-2016 | Saharsa | Sale / Conveyance |

(2) Presenter Details

| Presenter Name | Father/Husband Name | Address | Sex | Profession |
|---|---|---|---|---|
| Ruby Kumari | Raja Raman Kumar | Bangaon Uttari,bangaon,saharsa | F | Others |

(3) Party Details

| Sl.No | Type | Name | Father/Husband Name | Sex | Address | Profession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Executant | Ruby Kumari | Raja Raman Kumar | F | Bangaon Uttari,bangaon,saharsa | Others |
| 2 | Claimant | Rastiya Adhyaksh B J P -11 -Ashok Road New Delhi( Dr. Dilip Kumar Jaiswal) | Late Anandi Prasad Chaudhary | O | Purabpali Road,kishanganj,bihar | Others |

(4) Property Details

| Sl.No | Property Type | DSRO / SRO | Circle | Thana | Local Body | Land Type | Value | Khata | Plot | Area(in Decimal) | East | West | North | South |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Land | Saharsa | Kahra | Pr Rd Patuaha Sarak Se 1008 Tak | Municipal Corporation | Commercial | 4312000 | 221,630 | 377,208 | 8.7320 | niz bikreta | niz bikreta | khud kharidar | pakki sarak pradhan |

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

# महान कार्य का आकलन परिणाम से होता है, भाषण से नहीं

अगर मैं बैंक जाता हूं और बैंक में पैसा नहीं है, तो फिर मैं आगे से बैंक में पैसा क्यों रखूंगा? उस पैसे को मैं अपने पास रखूंगा, इसलिए भारत जैसे देश में बिना इसके प्रभाव के बारे में सोचे, इस तरह की योजना की घोषणा करना कोई बुद्धिमानी नहीं है. योजना की घोषणा हो चुकी है, अब हमें इससे गुजरना ही होगा. आम आदमी को कम से कम 31 मार्च तक इसके बोझ को ढोना ही होगा. हर दिन नोटों की छपाई अभी चल ही रही है. मैं यह उम्मीद करता हूं कि मार्च तक यह समस्या अतीत का हिस्सा बन जाएगी. अब मूल मुद्दा यानी कालाधन की बात करते हैं. इस देश में एक बहुत बड़ी जनसंख्या आयकर के दायरे से बाहर है. मिसाल के तौर पर कृषि क्षेत्र या 1-2-3 लाख के फिक्स्ड डिपोजिट पर सवाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह आयकर के दायरे में नहीं आता है. जो लोग टैक्स के दायरे में आते हैं, वे अपना पैसा इनके जरिए जमा करवाएंगे. आप एक पुलिस स्टेट नहीं बना सकते हैं. सरकार द्वारा शेखी बघारना और ये प्रलाप करना अब हास्यास्पद लगने लगा है. सरकार कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे. आप कैसे कार्रवाई करेंगे?

8 नवंबर को घोषित विमुद्रीकरण से समस्या अभी तक बनी हुई है. कई सारे निर्णय लिए जा चुके हैं कि आप कितना पैसा निकाल सकते हैं, कितना जमा कर सकते हैं, कब तक पुराना नोट कहां पर स्वीकार किया जा सकता है, आदि-आदि. अब आयकर कानून में संशोधन किया गया है, जिसके मुताबिक एक निश्चित प्रतिशत तक कर देकर धन को जमा और सफेद कराया जा सकता है. इसका मतलब है, एक और स्वैच्छिक आय घोषणा योजना. जाहिर है, उन्होंने ये महसूस किया कि विमुद्रीकरण से जिस लाभ की उम्मीद थी, वो उतनी सफल नहीं हुई, इसलिए इसे आंशिक रूप से स्वैच्छिक आय घोषणा योजना में तब्दील कर दिया गया. 30 दिसंबर के बाद ही हम यह जान पाएंगे कि कितनी पुरानी करेंसी बैंकों में वापस जमा हुई. उनकी उम्मीद थी कि 14 लाख करोड़ में से 3 से 4 लाख करोड़ रुपये वापस नहीं आएंगे. इस तरह उतना कालाधन सिस्टम से बाहर हो जाएगा. इससे रिजर्व बैंक के बैलेंस शीट को उतना लाभ होगा और सरकार की देयता खत्म हो जाएगी. यह एक बहस का विषय है कि क्या यह एकाउंटिंग का सही तरीका है, लेकिन दिलचस्प तथ्य यह देखना होगा कि 14 लाख करोड़ में से कितने लाख करोड़ रुपये वापस बैंकों में नहीं आते हैं? जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, अब लोग बात करने लगे हैं कि अब पूरे के पूरे 14 लाख करोड़ रुपये वापस आ जाएंगे. इसका अर्थ है कि विमुद्रीकरण का फैसला प्रभावी साबित नहीं हुआ. यह एक अनावश्यक कदम रहा. पहले तो आपको पर्याप्त नोटों की छपाई कर लेनी चाहिए थी. काला या सफेद धन की बात भूल जाएं. पहले नोट बदले जाने चाहिए थे. कराधान की बात अलग है, लेकिन यदि आपके पास नोट एक्सचेंज करने के लिए नोट नहीं हैं, तो यह एक दुखद और खतरनाक स्थिति है. दुखद इसलिए क्योंकि यह प्रशासन की कमी को दर्शाता है और खतरनाक इसलिए क्योंकि अब आम आदमी का भरोसा बैंक और करेंसी से उठने लगा है. आप चाहते हैं कि लोग कैशलेस बनें और बैंक में उनका भरोसा ज्यादा बढ़े, लेकिन इस कदम से तो उल्टा प्रभाव पड़ेगा.

अगर मैं बैंक जाता हूं और बैंक में पैसा नहीं है, तो फिर मैं आगे से बैंक में पैसा क्यों रखूंगा? उस पैसे को मैं अपने पास रखूंगा, इसलिए भारत जैसे देश में बिना इसके प्रभाव के बारे में सोचे, इस तरह की योजना की घोषणा करना कोई बुद्धिमानी नहीं है. योजना की घोषणा हो चुकी है, अब हमें इससे गुजरना ही होगा. आम आदमी को कम से कम 31 मार्च तक इसके बोझ को ढोना ही होगा. हर दिन नोटों की छपाई अभी चल ही रही है. मैं यह उम्मीद करता हूं कि मार्च तक यह समस्या अतीत का हिस्सा बन जाएगी.

अब मूल मुद्दा यानी कालाधन की बात करते हैं. इस देश में एक बहुत बड़ी जनसंख्या आयकर के दायरे से बाहर है. मिसाल के तौर पर कृषि क्षेत्र या 1-2-3 लाख के फिक्स्ड डिपोजिट पर सवाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह आयकर के दायरे में नहीं आता है. जो लोग टैक्स के दायरे में आते हैं, वे अपना पैसा इनके जरिए जमा करवाएंगे. आप एक पुलिस स्टेट नहीं बना सकते हैं. सरकार द्वारा शेखी बघारना और ये प्रलाप करना अब हास्यास्पद लगने लगा है. सरकार कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे. आप कैसे कार्रवाई करेंगे? हमें इसका मैकेनिज्म बताइए. एक किसान जाता है और दो लाख रुपए डिपोजिट करता है. आप कह रहे हैं कि तुम जमा कर सकते हो, लेकिन महीने में दस हजार से अधिक नहीं निकाल सकते. एक बार फिर, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप एक ऐसा स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां मैं अपने ही पैसे का इस्तेमाल




नहीं कर सकता. लंबे वक्त में यह एक दुखद स्थिति होगी. निश्चित तौर पर आप कालाधन को रोकने और अधिक कर वसूलने के लिए एक बुद्धिमतापूर्ण और बेहतर रास्ता अपना सकते हैं. लेकिन इस तरह के लचर और टेररिस्ट टाइप अटैक जैसा काम सही नहीं है. एक नया शब्द आया है, सर्जिकल स्ट्राइक. चाहे पाकिस्तान की बात हो या कालाधन की, ये हर जगह सर्जिकल स्ट्राइक ही करना चाहते हैं. ये मूर्खतापूर्ण है. भारत में इसे बचकाना हरकत कहते हैं. भारत जैसे देश में यह सब काम बेहतर तरीके से होना चाहिए.

कैशलेस सोसाइटी की ओर जाने का समग्र लक्ष्य अब संशोधित होकर लेस कैश सोसाइटी हो गया है, जो सराहनीय है. दुनिया की कोई भी सोसाइटी कैशलेस नहीं है. पश्चिमी देशों में जहां लोग ज्यादा शिक्षित हैं, ज्यादा बैंकिंग सुविधाएं हैं, वहां लोग कैश इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं क्योंकि चेक इस्तेमाल करना सुरक्षित है. भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कैश पर चलती है और यह काला नहीं, सफेद है. कृषि पर कोई कर नहीं लगता है. किसान अपनी उपज को नगद में बेचते-खरीदते हैं. शहरी और ग्रामीण सेक्टर के लिए अलग नियम होना चाहिए. कॉरपोरेट सेक्टर लगभग कैशलेस है. विमुद्रीकरण से कौन प्रभावित है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन विमुद्रीकरण से कौन प्रभावित नहीं है, ये मुझे पता है. ये कॉरपोरेट सेक्टर है. ये चेक और क्रेडिट कार्ड से पैसा ले और दे रहे हैं. केवल गरीब ही इस समस्या को झेल रहा है. यदि आप लेस कैश सोसायटी की ओर जाना चाहते हैं, तो पहले आपको ऐसे उपाय करने चाहिए, जहां लोगों को कैश की जरूरत ही न पड़े. लेकिन आप पहले विमुद्रीकरण करते हैं और फिर कहते हैं कि बैंक अकाउंट खोलो. आप पानी की व्यवस्था किए बगैर आग लगा देते हैं और फिर कहते हैं कि आग बुझाओ.

इसी तरह आधार कार्ड. सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है. यह एक वैकल्पिक कार्ड है. मैं समझता हूं कि इस सरकार को जो सबसे पहला सुधार (रिफॉर्म) करना चाहिए, वो यह कि जो लोग भी करदाता हैं और जिनके पास पैन कार्ड है, (यह कुल जनसंख्या का अधिक से अधिक 5 फीसदी होगा), उनके पास आधार कार्ड हो ही नहीं सकता. आधार कार्ड सरकारी लाभ पाने के लिए होना चाहिए. करदाता भी सरकारी लाभ लेना चाहते हैं. करदाता को भी सब्सिडी का लाभ देना चाहिए. आधार कार्ड केवल उनलोगों को दिया जाना चाहिए, जो करदाता नहीं हैं. जैसे ही आप करदाता बनते हैं, अपना आधार कार्ड सरेंडर (वापस) कीजिए. यहां हम आय करदाता को जबरदस्ती उच्च कराधान क्षेत्र में धकेल रहे हैं. मैं बहुत ही उच्च आय वाले दायरे में हूं. अगर आप मुझे आधार कार्ड ऑफर करेंगे तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन मुझे आधार कार्ड रखना ही होगा क्योंकि आपने ऐसे कई नियम बना दिए हैं, जहां आधार कार्ड आवश्यक हो गया है. अगर आपके पास पैन कार्ड है, तो आधार कार्ड की जरूरत ही नहीं है और यहां तक कि राशन कार्ड की भी जरूरत नहीं है. राशन कार्ड एक राज्य का विषय है, लेकिन भाजपा शासित राज्यों को यह कहना चाहिए कि सब्सिडी वाला अनाज केवल उन्हें मिलेगा, जो आय करदाता नहीं हैं. केवल गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के पास ही राशन कार्ड होना चाहिए. मुंबई जैसे शहर में राशन कार्ड आवासीय सबूत दिखाने के लिए है. सैकड़ों साल पुराने इस तरह के कानूनों को खत्म किए जाने की जरूरत है, इसलिए अगर आप रिफॉर्म्स (सुधार) की बात करते हैं, तो ऐसे सुधार करें, जिनकी जरूरत है. यह कोई रहस्य नहीं है, हर कोई जानता है कि राशन कार्ड सिस्टम में दुकानदार अनाज को कालाबाजार में बेचता है और गरीब को अनाज नहीं मिलता. आप ऐसी चीजों को रिफॉर्म करना चाहते हैं, जो रिफॉर्म नहीं हो सकती. भारत एक जुगाड़ वाला देश है. आज से छह महीने बाद सब कुछ अपने पुराने ढर्रे पर लौट आएगा. आप सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते हैं. आप भारत में निवेश चाहते हैं, आप भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (बिजनेस करने में आसानी) चाहते हैं. आप चाहते हैं कि लोग यहां आएं और फिर आप इस तरह के काम करते हैं, जिससे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसे लोग पसंद नहीं करते, जिससे लोगों को कठिनाई होती है.

पिछले 70 सालों में हमने भारत को ठीक तरीके से चलाया है. मैं उनलोगों में से नहीं हूं, जो कहते हैं कि पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ. केवल मूर्ख ही ऐसा कह सकते हैं. भारत 1947 में कहां था और अब कहां है, इसे कोई भी आसानी से महसूस कर सकता है. यह सब कांग्रेस ने किया है या किसी और ने किया है, यह महत्वपूर्ण नहीं है. यह देश सबका है. हमने अच्छा काम किया है. भाखड़ा-नांगल बांध, स्टील प्लांट, परमाणु रिएक्टर, मिसाइल, मंगलयान, आईआईटी, आईआईएम, ये सब किसने बनाया? बेशक लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इसका श्रेय जवाहरलाल नेहरू को जाएगा और ये नाम वे सुनना नहीं चाहते हैं. आप इतिहास को मिटा नहीं सकते. 2014 में आप प्रधानमंत्री बने, आपने एक ऐसा फैसला लिया, जिस पर अर्थशास्त्रियों की राय आपसे अलग है. भले ही मोदी भक्त बोल रहे हों कि एक बहुत ही महान काम हुआ है, लेकिन महान कार्य का आकलन परिणाम से किया जाता है. महान कार्य का आकलन भाषण से नहीं होता. अगर 4 से 5 लाख करोड़ रुपए बैंक में वापस नहीं आते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हां, कालाधन सिस्टम से खत्म हुआ. यह काम 30 दिसंबर तक होना है. लोग अब ये बोल रहे हैं कि तब तक सारा पैसा बैंक में आ जाएगा. पुराने नोट के बदले जो आप नए नोट दे रहे हैं, उसके बारे में लोग बोल रहे हैं कि उसका रंग उतर रहा है. आज एक बहुत ही अजीब स्थिति है.

एक बार फिर से यह अफवाह है कि सभी लॉकर्स को देखा जाएगा, सरकार सोना तलाश रही है. वित्त मंत्रालय को स्पष्टीकरण देना पड़ा कि सोना को लेकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है. भारत के लोग क्या करें? सोना भारत में घरों में प्राचीन काल से रखा जाता रहा है. गरीब भी थोड़ा बहुत सोना रखते हैं, क्योंकि भारत में लोग सोना पर भरोसा करते हैं. यह मुसीबत में काम आता है. दक्षिण भारत में जाइए, वहां तकरीबन हर ब्राह्मण महिला के शरीर पर सोना जरूर होता है. उन्हें इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए. अगर बैलेंस ऑफ़ पेमेंट की समस्या है तो सरकार कुछ सोना गिरवी रख सकती है, हालांकि यह भी लोग पसंद नहीं करेंगे. लेकिन भारत को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए यह किया जा सकता है. यहां अगर आप लोगों के सोना के पीछे जाएंगे तो तब मानिए कि आपकी सरकार बच नहीं पाएगी. उम्मीद करिए कि चीजें सही हो जाएंगी. तब तक ये तमाशा देखते रहिए.■

feedback@chauthiduniya.com

# विश्वास बहाली का कारगर उपाय है एलओसी व्यापार


शुजात बुखारी

अगर जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की बात की जाए, तो 23 नवंबर 2003 को घोषित युद्ध विराम को एकमात्र उपलब्धि के रूप में पेश किया जा सकता है. इस घोषणा से एक नई शुरुआत का रास्ता खुला और नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ विश्वास बहाली के दो बड़े पहल किए गए. वर्ष 2013 में युद्ध विराम ने एक दशक पूरा किया और राज्य की 725 किलोमीटर लंबी एलओसी के नज़दीक रहने वाले हजारों लोग इसकी सफलता से खुश हुए और इसकी निरंतरता की कामना की. हालांकि इस दौरान कई बार युद्ध विराम के उल्लंघन भी हुए, लेकिन लोगों में उसके स्थायी होने की उम्मीदें बाकी रहीं. आखिरकार इस घोषणा ने नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ से होने वाली गोलाबारी की आवाजों को एकदम खामोश कर दिया था और लोगों को इससे होने वाली परेशानियां भी अचानक ख़त्म हो गई थीं. पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ द्वारा संघर्ष विराम की घोषणा के तुरंत बाद नई दिल्ली ने भी उस घोषणा की ताईद की थी. इसके बाद हजारों लोग अपने घरों को लौट सके थे.

बहरहाल, पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थिति फिर ख़राब हुई है. पिछले कुछ महीनों में संघर्ष विराम के उल्लंघन की वजह से दोनों तरफ से होने वाली गोलाबारी में मरने वाले नागरिकों की संख्या में इजाफ़ा हुआ है. तनाव में नए सिरे से हो रही वृद्धि ने हज़ारों लोगों को अपना घर-बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया है. चूंकि स्थिति सामान्य करने की दिशा में भारत और पाकिस्तान सहमत होते नहीं दिख रहे हैं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि हालात सुधारने में लंबा समय लग सकता है. जनरल कमर बाजवा पाकिस्तानी सेना के नए अध्यक्ष बने हैं. अब गौर करने वाली बात यह होगी कि वो भारत के लिए कैसी नीति अपनाते हैं? बहरहाल, उनकी नीति निश्चित रूप से दोनों देशों के आगामी संबंधों को परिभाषित करेगी. लेकिन जहां तक मोदी सरकार का सवाल है तो उसके लिए विमुद्रीकरण के कारण उपजे गुस्से और उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों के मद्देनज़र पाकिस्तान के साथ तनाव उपयुक्त होगा.

हालांकि बंदूकों की घनगरज उसी तेज़ी से जारी है, इसके बावजूद कुछ आशापूर्ण चीज़ें दिखाई दे रही हैं. उनमें से एक है नियंत्रण रेखा व्यापार, जिसने 21 अक्टूबर को अपना आठ साल पूरा कर लिया, और जो कई रुकावटों के बावजूद विश्वास बहाली का एक कामयाब उपाय साबित हुआ है. इस कामयाबी को दिल्ली स्थित ब्यूरो ऑफ रिसर्च ऑन इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक फंडामेंटल्स (ब्रीफ) ने कांसीलिएशन रिसोर्सेज (लंदन) की मदद से तैयार एक विस्तृत रिपोर्ट में ज़ाहिर किया है. इस रिपोर्ट का लोकार्पण दिल्ली और जम्मू में किया गया, जिसमें पिछले आठ साल के दौरान व्यापार में हुई तरक्की को दिखाया गया है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान एलओसी के दोनों तरफ 699 मिलियन डॉलर का व्यापार हुआ, जो बुनियादी ढांचे से संबंधित अड़चनों को देखते हुए एक बड़ी उपलब्धि है.

उचित व्यवस्था के अभाव और एलओसी व्यापार के ख़िलाफ जारी षड्यंत्र के बावजूद यह जारी रहा. दरअसल यह दोनों तरफ के लोगों का एक-दूसरे से एकता बनाए रखने की इच्छा का प्रदर्शन भी है. भारत और पाकिस्तान के हमेशा जारी रहने वाले तनावपूर्ण रिश्तों के कारण बस सेवा की तरह सार्थक व्यापार भी दूर की कौड़ी ही रही है. फिर भी यह व्यापार, जिसका एक बड़ा प्रतीकात्मक महत्व रहा है, जारी रहा है. केवल रिश्तों में तनाव का साया ही इसपर हावी नहीं रहा है, बल्कि व्यापारियों के छोटे-मोटे आपसी झगड़ों के साथ-साथ नशीले पदार्थों की तस्करी का षड्यंत्र भी इस के सामने एक बड़ा ख़तरा रहा है. यदि एलओसी पर गोलीबारी की वजह से दोनों तरफ का व्यापार कई हफ्तों तक स्थगित रहा, तो वहीं 2014 और 2015 के बीच पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से आने वाले ट्रकों से नशीले पदार्थों की खेप बरामद किए जाने के बाद कुछ दिनों के लिए इसे रोक दिया गया. इन ट्रकों के ड्राइवर आजतक बारामूला जेल में सलाखों के पीछे बंद हैं.

इस व्यापार को नवीनतम ख़तरा अमृतसर और लाहौर के व्यापारियों की तरफ से है, जो इस व्यापार को अवैध और हवाला व्यापार कह रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि यह व्यापार दो संप्रभु देशों की देख-रेख में किया जा रहा है. उन व्यापारियों की चिंताएं वास्तविक हो सकती हैं, क्योंकि वे इसे एक समानांतर व्यापार की तरह देख रहे हैं जो उनके व्यवसाय को प्रभावित कर रहा है. इस व्यापार को इस नज़रिए से अलग हट कर देखना होगा, क्योंकि इस व्यापार की शुरुआत क्षेत्र में शांति बनाने और विश्वास बहाली के लिए की गई थी. जैसा कि 26 नवम्बर 2016 को जम्मू में ब्रीफ रिपोर्ट का लोकार्पण करते हुए प्रख्यात राजनीति शास्त्री रेखा चौधरी ने बिल्कुल ठीक कहा कि यदि हम इस व्यापार को आर्थिक नफा-नुकसान के तौर पर देखेंगे तो हम गलती करेंगे, ऐसे समय में जब (दोनों देशों के बीच) सारी चीज़ें धराशायी हो गई हैं, तो केवल यही एक चीज है जो अभी भी जारी है. इसने पुराने जम्मू-कश्मीर राज्य को एक विचारात्मक एकता प्रदान की है. आज इस व्यापार को मुख्य रूप से बैंकिंग से जुड़ी समस्याओं के कारण अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि भारत सरकार ने बैंकिंग शुरू करने की पेशकश की है, लेकिन पाकिस्तान इसको लेकर सकारात्मक नहीं है.

हालांकि एलओसी व्यापार को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 2004 में ही सहमति बन गई थी, लेकिन इसे वास्तविक रूप 2008 में अमरनाथ भूमि विवाद के चलते हो रहे विरोध-प्रदर्शन और हड़तालों के मद्देनजर दिया गया. जब जम्मू के व्यापार निकायों ने आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा की, तो कश्मीर में व्यापारियों ने मुजफ्फराबाद से पारंपरिक व्यापार मार्ग को फिर से खोलने की मांग की. इसके बाद 'मुजफ्फराबाद चलो' का संयुक्त रूप से आह्वान किया गया, जिसमें वरिष्ठ अलगाववादी नेता शेख अजीज सहित कई लोग पुलिस फायरिंग में उस समय मारे गए थे, जब जुलूस श्रीनगर-मुजफ्फराबाद सड़क पर शीरी के पास रोक दिया गया था. लोगों में बढ़ते असंतोष के कारण नई दिल्ली की स्थिति नाजुक हो गई और भारत ने एलओसी व्यापार को एकतरफा स्वीकृति दे दी. पाकिस्तान ने भारत के फैसले को मान लिया और 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ जरदारी व्यापार मार्ग खोलने पर सहमत हो गए.

बाद में दोनों कश्मीर के व्यापारियों ने व्यापार में आने वाली अड़चनों और बाधाओं को दूर करने के लिए, अनौपचारिक तौर पर जम्मू कश्मीर जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (जेकेजेसीसीआई) स्थापित किया, लेकिन सरकारों ने इसे मान्यता नहीं दी. जेकेसीसीआई आपसी मेल-मिलाप की एक शानदार उपलब्धि है, क्योंकि इसके सदस्यों में जम्मू-कश्मीर, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, मीरपुर और गिलगित-बालतिस्तान दोनों तरफ के लोग शामिल हैं.

विडंबना यह है कि मौजूदा वित्त मंत्री हसीब द्राबू द्वारा अक्टूबर 2008 में दिए गए फॉर्मूले की मौजूदा सरकार में सुध लेने वाला कोई नहीं है. एक अर्थशास्त्री के रूप में हसीब द्राबू उस समय जम्मू एंड कश्मीर बैंक के प्रमुख थे. उन्होंने एक बैंकिंग तंत्र स्थापित करने का सुझाव दिया था, जिसमें ऋण पत्र (लेटर ऑफ़ क्रेडिट) की आपसी स्वीकृति हो, एक संचार नेटवर्क हो, ताकि व्यापारियों को दोनों तरफ की प्रचलित दरों की जानकारी हो सके. एक परिवहन नेटवर्क हो, व्यापार की संरचना का निर्धारण करने के लिए एक नियामक नेटवर्क हो और विवादों के समाधान के लिए एक कानूनी नेटवर्क हो. द्राबू फॉर्मूला (जैसा कि बाद में इसे जाना गया) इस सिलसिले में सार्थक साबित हो सकता था. आज द्राबू खुद अपने इस फ़ॉर्मूले पर कायम हैं या नहीं, यह मालूम नहीं है.

अगर आज कोई चीज़ इस व्यापार को कमज़ोर कर रही है, तो वह है इस सिलसिले में दोनों देशों की सरकारों की स्पष्ट उदासीनता. हालांकि यह अभी तक इसलिए जारी है, क्योंकि इस व्यापार में शामिल लोगों ने अपने हित इसके साथ जोड़ लिए हैं. साथ ही साथ यह व्यापार (दोनों देशों के बीच) तनाव के प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में उभरा है और एकता की उम्मीद को जिंदा रखे हुए है.■

*-लेखक राइजिंग कश्मीर के संपादक हैं.*

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

## जब तोप मुक़ाबिल हो



# जितेंद्र सिंह जी यह ग़ुस्सा पौरुषहीन है

हम अपने को उस भीड़ में चाह कर भी शामिल नहीं कर पाते, जो भीड़ विरुदावली गाती है, जो भीड़ चंदवर दाई की श्रेणी की है और जो भीड़ ताकतवर और सत्ताधारियों के कशीदे पढ़ती है. दरअसल हमारे दिमाग में पत्रकारिता के उस सिद्धांत का फितूर भरा है कि किसी भी पत्रकार को विरुदावली गाने की भीड़ से हमेशा अलग रहना चाहिए. उन चीजों की तरफ इशारा अवश्य करना चाहिए, जो किसी भी ताकतवर, जिसमें सत्ताधारी और विरोध पक्ष शामिल हैं, के काम करने के तरीके से अगर लोगों के ऊपर तकलीफ आने के अंदेशे हों, तो उन अंदेशों को अवश्य सामने रखना चाहिए. आजकल ऐसा नहीं हो रहा है. नक्कारखाना तेजी से आवाजें निकाल रहा है. दूसरी तरफ, कहावत है कि नकटों के गांव में अगर कोई नाक वाला पहुंच जाए तो उस नाक वाले को नकटे कहते हैं, देखो नक्कू आ गया, नाक वाला आ गया. ये कहावत आज की स्थिति को ही ध्यान में रखकर बनाई गई होगी. हजारों साल पहले कुछ ऐसा ही हुआ होगा. यह कहावत हजारों साल से चरितार्थ होती आ रही है.

हम यह चाहते हैं और अगर कहीं ईश्वर है, तो उससे प्रार्थना भी करते हैं कि वो हमारी शंकाएं सौ फीसदी गलत साबित करे और हमें अपने ऊपर पछताने का अवसर दे. पहला सवाल, अगर हमारे बैंकों में 1000 और 500 के 11 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट जमा हो गए, तो इसका मतलब क्या निकलता है? अगर कहीं 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा नोट जमा हो गए तो उसका मतलब क्या निकलता है? अगर कहीं 17 लाख करोड़ रुपए जमा हो गए तो आर्थिक तंत्र के ऊपर क्या असर पड़ेगा? मैं चाहता हूं कि इसका जवाब वे सारे लोग दें, जो अर्थव्यवस्था को जानते और समझते हैं.

ये नोटबंदी या जिसे 1000 या 500 के नोटों का बदलना कहते हैं, बहुत सोच-समझकर हुआ होगा, वरना किसी भी देश का प्रधानमंत्री ऐसा फैसला ले ही नहीं सकता. उसने आने वाले संकटों, लोगों को होनी वाली परेशानियों और लोगों को फिर कितने दिनों में राहत दी जाय, इसका आकलन जरूर किया होगा, अन्यथा प्रधानमंत्री पद पर बैठने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं माना जा सकता. मैं मानता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने इस सारी चीजों के ऊपर बहुत ध्यान दिया होगा. अगर शंकाओं में कोई दम है, तो वो इतनी कि 25 दिन बीतने के बाद भी आम लोग परेशान हैं, उनके पास कैश नहीं है. बहुत सारी जगहों पर, जहां की रिपोर्ट हमारे टेलीविजन और अखबारों में नहीं आ पाती है, वहां लोग दूध, सब्जी और रोजाना के खाने के सामान के लिए तरस गए हैं. उन्हें उधार मिलना मुश्किल हो रहा है. कई जगहों पर बार्टर सिस्टम भी शुरू हो चुका है, लेकिन उसमें भी लोग दोनों के अंतर को देखकर बहुत सफलतापूर्वक इस सिस्टम को नहीं चला पा रहे हैं.

सबसे बड़ा सवाल, जिसका जवाब सरकार तो नहीं देगी लेकिन अर्थशास्त्री या बैंकिंग सिस्टम को जानने वाले लोग जवाब दें कि देश में जितने नकली नोट थे, उनको इस कदम ने असली साबित कर दिया और वे सारे के सारे बैंक में जमा हो गए. कालाधन, जो नोटों की शक्ल में बाहर था और मोटे अंदाज में लगभग 10 प्रतिशत कालाधन ही नोटों के रूप में था, वो भी बैंकों में पहुंच गया. यानी हमारी फेक करेंसी, नकली करेंसी भी बैंकों में पहुंच गई. हमारा कालाधन भी बैंक में पहुंच गया. यह तब साबित होगा, जब 30 दिसंबर को सरकार यह आंकड़ा देगी कि उसके पास कितना पैसा आया. यह लिखे जाने तक बैंकों में लोगों का लगभग 10 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुका है, जिसे सरकार कहती है कि यह कालाधन है, लेकिन जनता कहती है, यह उनकी गाढ़ी कमाई है, जो बुरे वक्त के लिए 125 करोड़ लोगों ने अपने घर में जमा कर के रखा था. चूंकि नोट चलन से बाहर हो गए हैं, इसलिए उन्होंने उसे या तो बदलवाया है या अपने या किसी पड़ोसी के खाते में जमा किया है. इससे पहले अंदाजा यह था कि हमारी अर्थव्यवस्था में 50 प्रतिशत सही और 50 प्रतिशत नकली नोट हैं. अगर 14 लाख 60 हजार करोड़ की मुद्रा प्रचलन में थी और 10 लाख करोड़ जमा हो चुके हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि नकली मुद्रा असली के नाम पर बैंकों में जमा हो चुकी है. इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, ये हम विशेषज्ञों से जानना चाहते हैं. हम अज्ञानी हैं, इसलिए विशेषज्ञों का फर्ज बनता है कि हमें बताएं.

भारत सरकार ने जान-बूझकर सोचा होगा कि हम नोट कम छापें, क्योंकि नोट कम छापने से लोगों की देशभक्ति का पता चलता है. लोग लाइन में खड़े हैं, पैसे जमा कर रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे हैं. देश बदलने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया है, उस कदम का इस देश का गरीब समर्थन कर रहा है और टेलीविजन पर आकर इस कदम की भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहा है और कह रहा है कि सीमा पर अगर सिपाही खड़ा रह सकता है, तो क्या हम दो दिन लाइन में नहीं लगे रह सकते हैं. लगभग इस तरह की बाइट्स, इस तरह के बयान टेलीविजन लगातार दिखा रहे हैं. हमें भी इसके ऊपर भरोसा हो गया कि सारा देश देशभक्तों की बाढ़ से भर गया और वो सारा पैसा बैंक में जमा कर रहा है और देश की सेवा कर रहा है. इसमें कहीं भी गांव के 60 प्रतिशत लोगों की बात नहीं आ रही है, जिनकी खरीफ की फसल खेतों में पड़ी है, जो बिकी नहीं क्योंकि आढ़ती बिना नकद दिए फसल खरीदते नहीं, न आढ़तियों के पास नकद देने को पैसा है और न किसान नकद लेगा क्योंकि नोट बदल गए हैं और नए नोट आए नहीं हैं. वो फसल खेत में पड़ी है, बिना बिके. रबी की फसल बोने, बीज और खाद के लिए किसान के पास पैसा नहीं है. बड़े किसानों के पास पैसा है, उनके नोट भी बदल गए लेकिन छोटे या मझोले किसानों के पास तो बिल्कुल पैसा नहीं है. वह किसान तकलीफ व्यक्त नहीं कर पा रहा है, मानना चाहिए कि वह इसका समर्थन कर रहा है और सारा कष्ट सह रहा है. उसके बच्चों की फीस नहीं जा पा रही है, उसके घर में खाने का सामान नहीं आ रहा है. किसान अपने फसल बेचकर ही परिवार की खुशियों के लिए कुछ खरीद पाता है. उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो किसान इसका समर्थन कर रहा है और मुझे ये स्थिति बहुत अच्छी लग रही है.

नंबर तीन, अर्थशास्त्री ये डर निर्मूल करें कि जितनी करेंसी बैंकों में जमा हो गई है, उतनी करेंसी लोगों के पास पहुंच गई है, यानी 14 लाख 60 हजार करोड़ रुपये, अगर वो लोगों के पास तक पहुंच गई है, तो इससे कालेधन के ऊपर चोट कहां हुई. क्योंकि 10 लाख करोड़ अगर 30 नवंबर तक बैंकों में पहुंच गया है और सिर्फ 4 लाख 60 हजार करोड़ या 64 हजार करोड़ रुपया बाहर है, जो 30 दिसंबर आते-आते पूरा हो जाएगा, तो कालेधन के ऊपर चोट कहां हुई, इसमें लोगों को तकलीफ हुई. नकली नोट बैंक में पहुंच गए, देश को इससे क्या मिला? ये आकलन किसी अर्थशास्त्री या सरकार को कर के देना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री दोनों कह रहे हैं कि कालेधन वाले लाइन में खड़े हैं और बैंकों में अपना पैसा जमा करा रहे हैं.

पहली बार डॉलर और रुपए का अनुपात बहुत विकराल हो गया है. क्या डॉलर 70 रुपए को पार कर जाएगा? अगर पार कर जाएगा तो सामानों के दाम कितने बढ़ेंगे और उसका हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर क्या असर पड़ेगा? भारत का विशाल औद्योगिक ढांचा है, जिसमें पैदा हुई बहुत सारी चीजें हम बाहर भेजते हैं और बहुत सारी खरीदते हैं. अगर डॉलर 70 के पास चला गया, तो क्या होगा? उसका असर हमारे बाजार पर क्या पड़ेगा? रोज की चीजों के भाव क्या होंगे और कितने पैसे में हम उन्हें खरीद पाएंगे? जिनके पास पैसा नहीं है, वे क्या करेंगे? वो अपनी भूख मिटाने के लिए या परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? ये मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मेरे दिमाग में सवाल उठता है और इन सवालों को मैं विरुदावली गाने वाले पत्रकारों, टेलीविजन के एंकरों से, जो भड़ैतों की भीड़ में शामिल हैं, उनसे भी पूछता हूं और अर्थशास्त्रियों से भी पूछता हूं, क्या आप इसका उत्तर जनता को देंगे?

डर ये भी है कि अगर 20 दिसंबर तक स्थिति सामान्य नहीं हुई, रुपए पूरे नहीं बदले गए, रुपए लोगों के हाथों में खर्च करने के लिए नहीं पहुंचे, तो ये अपनी दैनंदिन जरूरतों या अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कहीं किसी तरह के अराजक तरीके तो नहीं इस्तेमाल करने लगेंगे? मेरा मानना है कि ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब देशभक्त लोग हैं और हर चीज हमारे यहां देशभक्ति से जोड़ी जा रही है. अगर आप नोटबंदी का विरोध करेंगे तो आप देशद्रोही हैं. अगर आप कहेंगे कि अभी युद्ध का माहौल मत बनाइए, तो आप देशद्रोही हैं. आपको देशभक्ति साबित करने के लिए पहले पाकिस्तान को गाली देनी है, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री जितेंद्र सिंह कहते हैं, जो वह खुलकर तो नहीं कहते लेकिन उसका मतलब यही है कि हम पाकिस्तान का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन जो लोग यहां पर युद्ध का विरोध करते हैं या जिनकी बातों से पाकिस्तान का समर्थन नजर आता है, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी. जितेंद्र सिंह जी, इसे पौरुष-हीन गुस्सा कहते हैं. आपके अपने पास करने की कोई ताकत नहीं है, न आप अपने देश की जनता को नोट सप्लाई कर पा रहे हैं और न आप पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ पा रहे हैं. अगर आप में ताकत है, तो सीमा पर कुछ कर के दिखाइए. मुझे कश्मीर के एक नेता ने कहा कि रोज-रोज कश्मीर को लेकर लड़ाई की धमकी से बेहतर है, एक बार भारत क्यों नहीं पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देता है और पूरे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत में मिला लेता है. कश्मीर की समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि कश्मीर के लोग चाहते हैं कि पूरा कश्मीर एक हो. यह या तो बातचीत से हो सकता है या युद्ध से हो सकता है और आप इतने ज्यादा ताकतवर हैं, जितेंद्र सिंह जी, आप प्रधानमंत्री से रोज बात करते हैं. आप उनको समझाइए कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर पूरा कश्मीर हिंदुस्तान में मिला लें, हमेशा के लिए कश्मीर समस्या को हल कर लें. लेकिन आप ये नहीं करेंगे. आप गुस्सा किनके ऊपर उतारेंगे, किनको धमकी देंगे, जिनको आपने आज दी है. क्या हम हिंदुस्तान के उन बुद्धिजीवियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जो युद्ध का विरोध करते हैं, जो नोटबंदी का विरोध करते हैं. इसका मतलब ये पाकिस्तान के समर्थन में हवा बना रहे हैं, दरअसल हवा तो आप बना रहे हैं जितेंद्र सिंह जी, पाकिस्तान को इतना ताकतवर बताकर. आपके जैसे वो खरीदे हुए बुद्धिजीवी हवा बना रहे हैं, जो पाकिस्तान का नाम पानी पी-पी कर लेते हैं और पाकिस्तान को कोसते हैं, मानो हिंदुस्तान की हर चीज को नियंत्रित करने का काम पाकिस्तान कर रहा हो. पाकिस्तान को बड़ा बनाने के जिम्मेदार ये लोग हैं, जिनमें आप खुद भी शामिल हैं.

मेरा निवेदन है कि सरकार को अब थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए और सरकार को बहुत सारे सवालों के जवाब देने चाहिए. आने वाली शंकाओं को गलत साबित करने के लिए तमाम खतरे उठाने चाहिए. अपने संपूर्ण रक्षा व्यवस्था का विश्लेषण कीजिए जितेंद्र सिंह जी. अभी आपके जम्मू-कश्मीर में हाल में हुए हमले में पहले दिन सेना के लोगों ने कहा कि वो हमारी चूक की वजह से हुआ. आपने वो रिपोर्ट देखी? आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि आप रिपोर्ट देखने में बहुत भरोसा नहीं करते हैं. आप जैसे लोगों को मैं सलाम करने, आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देने और देश के भविष्य के लिए अफसोस करने के सिवाय और क्या कर सकता हूं.■

editor@chauthiduniya.com



**सबसे बड़ा सवाल, जिसका जवाब सरकार तो नहीं देगी लेकिन अर्थशास्त्री या बैंकिंग सिस्टम को जानने वाले लोग जवाब दें कि देश में जितने नकली नोट थे, उनको इस कदम ने असली साबित कर दिया और वे सारे के सारे बैंकों में जमा हो गए. कालाधन, जो नोटों की शक्ल में बाहर था और मोटे अंदाज में लगभग 10 प्रतिशत कालाधन ही नोटों के रूप में था, वो भी बैंकों में पहुंच गया. यानी हमारी फेक करेंसी, नकली करेंसी भी बैंकों में पहुंच गई. हमारा कालाधन भी बैंक में पहुंच गया. यह तब साबित होगा, जब 30 दिसंबर को सरकार यह आंकड़ा देगी कि उसके पास कितना पैसा आया. यह लिखे जाने तक बैंकों में लोगों का लगभग 10 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुका है, जिसे सरकार कहती है कि यह कालाधन है, लेकिन जनता कहती है, यह उनकी गाढ़ी कमाई है, जो बुरे वक्त के लिए 125 करोड़ लोगों ने अपने घर में जमा कर के रखा था. चूंकि नोट चलन से बाहर हो गए हैं, इसलिए उन्होंने उसे या तो बदलवाया है या अपने या किसी पड़ोसी के खाते में जमा किया है.**

# साकार होगा नीतीश का जगमग बिहार का सपना!

इर्शादुल हक

दिसम्बर 2018 तक बिहार में पूरी तरह उजाले ही उजाले होंगे. कहीं अंधियारा नहीं होगा. गोया हर घर बिजली 24 घंटे. सोचिये यह एक ऐसा सपना है, जिसे देखते हुए बिहार की चार-चार पीढ़ियां गुजर गयीं. अगर यह सपना साकार हुआ तो बिहार की रौनक फ्रांस की मानिंद होगी. यह दीगर बात है कि फ्रांस का बिजली संचरण अत्याधुनिक है, जिसमें बत्ती गुल होने की संभावनायें रेयर होती हैं. लेकिन जहां तक बिजली उपलब्धता की बात है, अगर नीतीश सरकार का दावा सच साबित हुआ, तो बिहार लालटेन-ढिबरी युग से पूरी तरह से बाहर आ जायेगा. लेकिन सवाल यह है कि क्या यह दो साल में संभव हो पायेगा? राज्य सरकार के वादे और इरादे अगर पक्के साबित हुए तो इस सवाल का जवाब निश्चित तौर पर हां होगा, बशर्ते संसाधनों की कमी नहीं हो. इसी वादे और इरादे के तहत 15 नवम्बर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली लगातार योजना की शुरुआत की. यह योजना नीतीश के कुल सात निश्चयों में से एक है. बकौल नीतीश, अपने नये कार्यकाल के एक साल के भीतर उन्होंने अपने सातों निश्चयों पर अमल शुरू कर दिया है. हर घर बिजली के अलावा हर घर को नल का पानी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण, बेरोजगार युवाओं को भत्ता, हर गांव की अपनी पक्की सड़क, हर घर को शौचालय आदि शामिल हैं. इन तमाम निश्चयों पर सरकार ने विगत 6-8 महीने में अमल शुरू कर दिया है. रही बात बिजली की, तो यह नीतीश के सात निश्चयों में से आखिरी निश्चय था, जिसे पूरा करने की शुरुआत उन्होंने बाजाब्ता तौर पर 15 नवम्बर को कर दी. यहां यह याद रखना चाहिए कि 2015 के चुनावों से पूर्व नीतीश कुमार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इन सात निश्चयों का जिक्र किया था. नाम दिया गया था 'नीतीश निश्चय'. तब इन निश्चयों की जबर्दस्त ब्रांडिंग की गयी थी. प्रचार और प्रसार का ऐसा नुस्खा अपनाया गया था कि भाजपा के कॉर्पोरेट व डिजिटल प्रचार को अगर कोई दमदार चुनौती पेश कर रहा था, तो वह नीतीश कुमार थे. उस चुनावी प्रचार में कहीं भी दूर-दूर तक कोई तीसरा नजर नहीं आ रहा था. इसके लिए चुनाव से कई महीने पहले प्रचार के एक ऐसे कॉकटेल का बंदोबस्त भी किया गया था, जिसमें एक मिशन की तरह राज्य सरकार के सारे संसाधन झोंके गये थे. इस मिशन को 'बढ़ चला बिहार' कहा गया था. कहना न होगा कि नीतीश कुमार ने अपने सात निश्चयों की कल्पना अगस्त 2015 में ही कर ली थी और जब बीते 15 नवम्बर को वह अपने आखिरी निश्चय यानी 'हर घर बिजली लगातार' योजना का उद्घाटन कर रहे थे, तो जोर दे कर कह भी रहे थे कि उनके तमाम निश्चय समय पर पूरे हो कर रहेंगे. नीतीश यह भी कह रहे थे कि वह प्रचार व प्रसार में विश्वास नहीं करते, केवल काम करते हैं और उनका काम ही बोलता है. लेकिन अगर गौर से देखें तो उनके दो निश्चय ऐसे हैं जिनकी चुनौतियां बहुत ही जोखिम भरी हैं. पहला, हर घर नल का जल और दूसरा हर घर को बिजली. यह जोखिम भले ही चाहे जितना बड़ा हो पर आवाम की उम्मीदें इन दो योजनाओं पर

ठहरी हैं. नीतीश कुमार को इस बात का बखूबी एहसास भी है. लगभग ग्यारह करोड़ की आबादी वाले प्रदेश को रौशन करने, नल का पानी की आपूर्ति करने समेत उनकी तमाम योजनाओं पर लगभग 2 लाख सत्तर हजार करोड़ की जरूरत है, जिसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और अन्य एजेंसियों के बूते किया जाना है. इसलिए यह कहना मुश्किल नहीं कि इन योजनाओं को धरातल पर लाने में सरकार के पसीने नहीं छूटेंगे. हर घर बिजली योजना की शुरुआत करते हुए नीतीश की यह पीड़ा कई बार सामने आयी कि केंद्र उन्हें इस मामले में अपेक्षित मदद नहीं कर रहा है. उन्होंने कहा भी कि पहले राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के क्रियान्वयन में केंद्र की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत थी. लेकिन जब नयी सरकार आयी और उसने इस योजना का नाम बदल कर दीनदयाल उपाध्याय विद्युतिकरण योजना रख दिया, तो केंद्र ने अपनी हिस्सेदारी घटा कर महज 60 प्रतिशत कर दी. यानी अब राज्य सरकार को दस प्रतिशत के बजाये चालीस प्रतिशत धन खर्च करने होंगे. दूसरी तरफ राज्य की एक और चुनौती है. यह चुनौती राजस्व वसूली की कमी से जुड़ी है. शराबबंदी से बिहार को प्रतिवर्ष लगभग 3300 करोड़ रुपये के राजस्व से हाथ धोना पड़ा है. हालांकि इस राजस्व की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों, वाहन से जुड़े टैक्स के अतिरिक्त अन्य कई करों को आम जनता पर लादा है और अपने राजस्व कलेक्शन को मजबूत बनाये रखने की कोशिश की है. पैसों के अतिरिक्त और चुनौतियां भी हैं, जो नीतीश निश्चय को पूरा करने में कठिनाइयां उत्पन्न करेंगी. इनमें से एक चुनौती नौकरशाही से जुड़ी है.

नौकरशाही की लेटलतीफी और कामों को टालते रहने की उनकी नियति देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी व्याप्त है. योजना के अनुसार राज्य के 50 लाख परिवारों को बिजली कनेक्शन से जोड़ा जाना है. नीतीश कुमार को अपने शाशकीय अनुभव से यह बखूबी पता है कि प्रखंड स्तर से ले कर उच्च नौकरशाही के काम करने की गति क्या है. उन्हें यह भी पता है कि भ्रष्ट तंत्र भी इस काम में बड़ा अड़ंगा लगायेगा. इसीलिए इस योजना की शुरुआत करते हुए उन्होंने यह भी जोर दे कर कहा कि इस काम से जुड़ी नाकारा एजेंसियों को सिर्फ टर्मिनेट ही नहीं किया जायेगा, बल्कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज किये जायेंगे. राजनीतिक स्तर पर सरकार महज फैसले ले सकती है, लेकिन उन फैसलों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी मूल रूप से नौकरशाही के विशाल तंत्र पर होती है. पिछले ग्यारह वर्षों से नीतीश सत्ता में हैं और विरोधी भी यह स्वीकार करेंगे कि पिछले एक दशक में राज्य में विकास और बदलाव के बहुत काम हुए हैं. 2005 में सत्ता संभालने के बाद नीतीश ने जिन दो-तीन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया वह सुशासन के मूल मंत्र पर आधारित था. इसके तहत कानून व्यवस्था को ठीक करना, राज्य की जर्जर सड़कों का कायाकल्प करना और गांव-गांव तक बिजली पहुंचना प्रमुख थे. चूंकि सुशासन एक सतत प्रक्रिया का नाम है, इसपर बहुत कहने-सुनने की जरूरत नहीं, लेकिन सड़कों के निर्माण में नीतीश कुमार के काम की प्रशंसा राज्य से बाहर के संस्थाओं ने भी की. लेकिन बिजली के मामले में उन्हें आलोचनायें भी सुनने को मिली. यह आलोचना उनके उस कथित वादे को ले कर थी, जिसमें उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि अगर वह राज्य में बिजली की दशा नहीं सुधारेंगे तो, 2015 में मतदाताओं से वोट मांगने नहीं आयेंगे. लेकिन 2015 के चुनाव से पहले तक राज्य का बहुत बड़ा इलाका अंधियारे में डूबा था. जहां बिजली के पोल तक नहीं पहुंचे थे. विरोधी दलों ने नीतीश के इस कथित वादे को मजबूती से धर लिया और लगातार हमले करते रहे. हकीकत यह भी रही है कि पिछले दस-ग्यारह सालों में बिजली की हालात में व्यापक सुधार होने के बावजूद उद्योग और कारोबार से जुड़े लोगों की भी यह आम शिकायत रही कि बिजली की अनुपलब्धता के कारण उद्योग धंधों में भारी रुकावट हुई है. हालांकि 2005 से, जब नीतीश कुमार की सरकार आयी है, बिजली की उपलब्धता, संचरण और जेनेरशन में हुई तरक्की को बार-बार नीतीश कुमार ने उजागर किया है. 15 नवम्बर वाले कार्यक्रम में नीतीश ने इस बात को दुहराया भी. उनके साथ ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने भी गिनाया कि 2005 में जहां राज्य में 700 मेगावाट बिजली की उपलब्धता थी, वह आज बढ़ कर 4000 मेगावाट तक पहुंच गयी है. तब जहां प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 70 यूनिट थी वह अब बढ़ कर 258 यूनिट हो चुकी है. लेकिन सरकार इस बात को भी स्वीकार करती है कि राज्य में बिजली जेनेरशन की हालत संतोषजनक अब भी नहीं हुई है. तभी तो बिजली खरीद कर आपूर्ति की जा रही है. हालांकि नीतीश कुमार के पिछले बयानों को देखें जिसमें वह, यह कहने से नहीं चूकते थे कि बिहार बिजली जेनेरेशन के मामले में न सिर्फ आत्मनिर्भर हो जायेगा बल्कि बिजली बेचा भी जायेगा.

इन तमाम वादों, इरादों और कामों पर राज्य सरकार 2005 से ही अमल कर रही है और उसे दस वर्ष यानी 2015 तक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना था. जिसे अब बढ़ा कर 2018 कर दिया गया है. यह लक्ष्य 2018 तक पूरा हो सकेगा इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता. क्योंकि खुद ऊर्जा सचिव प्रत्यय अमृत स्वीकार करते हैं कि अभी तक 72 प्रतिशत गांव में ही सर्वे का काम पूरा हो सका है. यानी अब भी 28 प्रतिशत गांवों में सर्वे समेत पोल गाड़ने की प्रक्रिया बाकी है. अमृत विश्वास दिलाते हैं कि इसी दिसम्बर तक सर्वे का काम पूरा हो जायेगा. सरकार के इन वादों और उसके निर्धारित लक्ष्यों पर भाजपा के विरोधी दल के नेता सुशील कुमार मोदी जिन सवालों को उठाते हैं, उन सवालों पर आम तौर पर सरकार खामोश रहना ही बेहतर समझती है. वह याद दिलाते हैं कि राज्य के 83 लाख बीपीएल परिवारों में से पिछले 8 वर्षों में मात्र 15 लाख परिवार को ही बिजली कनेक्शन दिया जा सका है. राज्य में बिजली के हालात ये हैं कि हर महीने 975 करोड़ खर्च करके 470 करोड़ वसूली हो पाती है. 300 करोड़ सब्सिडी देने के बाद भी पावर होल्डिंग कंपनी को हर माह 200 करोड़ का घाटा होता है. भले ही सरकार सुशील मोदी के इन सवालों पर चुप्पी साध ले, लेकिन ग्रामीण स्तर पर एक हकीकत यह भी है कि जिन सैकड़ों या हजारों राजस्व गांव में बिजली की आपूर्ति दो-तीन साल से हो रही है वहां पर उपभोक्ताओं से एक तिहाई भी बिजली बिल की वसूली नहीं हो पाती हैं. ग्रामीणों की इस मामले में स्पष्ट शिकायत रहती है कि उन्हें बिल ही नहीं दिया जाता. ऐसे में आर्थिक संसाधनों से जूझ रहे बिहार में बिजली कम्पनियों के घाटे का पहाड़ अगर बढ़ता ही चला जाय और हर घर बिजली से रौशन हो पाने का लक्ष्य 2018 के बाद दो वर्ष और बढ़ा दिया जाय तो कोई अचरज नहीं होनी चाहिए. वैसे भी राज्य में विधानसभा चुनाव 2020 में ही होने हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

# प्रकाशपर्व की तैयारियां जोरों पर

**25 दिसंबर से 10 जनवरी तक सिख श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी में हरेक बेड के साथ एक लॉकर की चाबी दी जाएगी, ताकि वे अपना सामान सुरक्षित रखकर कहीं भी दर्शन, भ्रमण और गुरुवाणी में शामिल हो सकें. गांधी मैदान में डोरमेटरी का निर्माण होगा, जबकि न्यू बाईपास और कंगन घाट पर अलग-अलग टेंट-तंबू लगेंगे.**

बूतन मिश्रा

feedback@chauthiduniya.com

10वें सिख गुरु का 350वां जन्मदिन समारोह पटना में तख्त श्री हरमंदिर साहिब में आयोजित होने जा रहा है. 5 जनवरी 2017 को आयोजित होने वाले इस समारोह में दुनिया भर से तीर्थयात्रियों के भाग लेने की संभावना है. प्रकाश पर्व को लेकर तख्त परिसर को भव्य बनाया गया है. अभी से गुरुधर जगमग करने लगा है. इस मौके पर राजधानी क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर टेंट सिटी में 55 हजार से अधिक सिख श्रद्धालुओं के लिए बेड लगाए जाएंगे. श्रद्धालुओं के सामान की सुरक्षा के लिए सभी टेंट सिटीज में लॉकर की व्यवस्था भी की गई है. औसत 20 लोगों के लिए एक स्नान घर और शौचालय का इंतजाम रहेगा. देश-विदेश से भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गांधी मैदान, कंगन घाट और न्यू बाईपास पर टेंट सिटी में अतिथि सेवा की तैयारी की जा रही है.

**गांधी मैदान में रहेंगे 14 हजार श्रद्धालु :** पर्यटन विभाग की ओर से गांधी मैदान में 14 हजार, न्यू बाईपास पर 36 हजार और कंगन घाट पर 5000 बेड का टेंट सिटी बनाया जा रहा है. इन जगहों पर अतिथि सत्कार के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं. पर्यटकों के लिए बन रहे टेंट सिटी में जन सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है. प्रकाश पर्व की तैयारी की मॉनिटरिंग अब एक दिन के अंतराल पर की जा रही है.

25 दिसंबर से 10 जनवरी तक सिख श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी में हरेक बेड के साथ एक लॉकर की चाबी दी जाएगी, ताकि वे अपना सामान सुरक्षित रखकर कहीं भी दर्शन, भ्रमण और गुरुवाणी में शामिल हो सकें. गांधी मैदान में डोरमेटरी का निर्माण होगा, जबकि न्यू बाईपास और कंगन घाट पर अलग-अलग टेंट-तंबू लगेंगे.

**तीन लोगों पर एक ब्लॉवलर :** ठंढ के मद्देनजर तीन लोगों पर एक ब्लॉवलर का इंतजाम किया जा रहा है. सुबह में स्नान के लिए पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी सुलभ कराने का इंतजाम किया जा रहा है. रात में सर्दी का अधिक असर होता है इसलिए गर्म हवा के लिए पर्याप्त संख्या में ब्लोअर लगाने की व्यवस्था की जाएगी.■

ईम्पोर्टेड केमिकल से तैयार, लैब टेस्टेड
पेन्ट डिस्टेम्पर
कोई भी हो
वॉल पुट्टी केवल ईटालियन वॉल पुट्टी
Laboratory Tested
Please Compare Lab Report
Made from Imported Chemicals
ईटालियन व्हाईट वॉल पुट्टी
Slight Costly but Superior
लैब रिपोर्ट अवश्य चेक करें ।
लैब रिपोर्ट हमारे सभी डीलर्स के यहां उपलब्ध है
प्रखण्ड स्तर या अपने क्षेत्र हेतू सप्लायर / डीलरशिप के लिए सम्पर्क करें ।
Mob : 9431234022 / 9435040133 Mail ID : mcwaterproof@yahoo.com
सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, घर को मजबुत बनाऐ
सीमेन्ट
कोई भी हो परन्तु
वाटरप्रूफिंग केमिकल सिर्फ
मिस्टर केमिस्ट
सीमेन्ट कोई भी हो लेकिन वाटरप्रूफिंग केमिकल मिस्टर केमिस्ट ही हो, क्योंकि मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग केमिकल ईम्पोर्टेड केमिकल से बनाया गया है, प्रत्येक पैक पर नम्बर युक्त होलोग्राम से नकल से पूरी तरह सुरक्षित १, ५, १०, २० एवं २०० लीटर होलोग्रामिक पैक में अब आपके यहां भी उपलब्ध । मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, घर को मजबुत बनाए ।
Mob : 9431234022 / 9435040133 Mail ID : mcwaterproof@yahoo.com

## पैक्स अध्यक्ष की हत्या के बाद गैंगवार की तरफ दियारा

# सुलगने लगी कोसी

राजेश सिन्हा
feedback@chauthiduniya.com

नदियों के कोख से निकली जमीन पर मालिकाना हक जताने के कारण अक्सर खून से लाल होती रही कोसी की धरती एक बार फिर सुलगने लगी है. महज पैंतीस बीघे जमीन को लेकर न केवल गैंगवार की आशंका प्रबल होती जा रही है, बल्कि एक पैक्स अध्यक्ष की गोली मारकर की गई हत्या के बाद दो आपराधिक पृष्ठभूमि के जनप्रतिनिधि भी आमने-सामने आ गए हैं. जनप्रतिनिधियों के द्वारा दो अलग-अलग आपराधिक गिरोहों का साथ दिए जाने के कारण कोसीवासी एक बार फिर दहशत के साए में जीने को मजबूर हो गए हैं. संभावित अनहोनी को लेकर कोसी या यू कहें कि फरकिया के लोग रतजग्गा करने को विवश हैं. हालांकि इस तरह का वाकया पहली बार सामने नहीं आया है. कोसी-बागमती के साथ-साथ अन्य नदियों के कोख से निकली जमीन पर कब्जा जमाने को लेकर अक्सर कोसी का दियारा इलाका गोलियों से थर्राता रहा है और खून की नदियां बहती रही है. यहां कभी तूतली सिंह गिरोह की तूती बोली तो कभी कैलू मियां गिरोह प्रतिद्वंदी गिरोह पर भारी पड़ा. समय-समय पर स्थितियां बदली हैं. राजा टोडरमल के जमाने में खगड़ा घास अर्थात जंगली घास के कारण जमीन की पैमाइस संभव नहीं होने के कारण फरक किए गए फरकिया की जमीन को लेकर यहां खूनी संघर्ष होता रहा है. सहेन्द्र शर्मा गिरोह के द्वारा प्रतिद्वंदी गिरोह के सोलह अपराधियों को मार कर शवों के टुकड़े कर देने की घटना अब भी लोगों में सिहरन पैदा करती है. समय-समय पर चले पुलिसिया अभियान और आपराधिक गिरोहों के बीच छिड़े गैंगवार में लगभग आधे दर्जन गिरोहों का सफाया तो हो चुका है. लेकिन कुख्यात दस्यु सरगना रामानंद यादव गिरोह का सिक्का दशकों से कोसी में चलता आ रहा है. रामानंद यादव उर्फ रामानंद पहलवान भले ही भूपतियों के साथ-साथ नक्सलियों के लिए नासूर साबित हुआ हो, लेकिन वह हमेशा गरीबों का हमदर्द रहा है. कई बार तो नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में रामानंद यादव गिरोह ने पुलिस के लिए सहयोगी की भूमिका भी अदा की है. कहा जाता है कि शायद इसीलिए रामानंद गिरोह का सफाया अब तक संभव नहीं हो सका है. छोटे-मोटे आपराधिक गिरोहों ने ऐसे ही बड़े और ताकतवर गिरोहों के दम पर आपराधिक वैतरणी पार की है.

**राजनीतिक प्रतिद्धंदिता के कारण रामानंद यादव को पैक्स अध्यक्ष हत्याकांड का नामजद अभियुक्त बनाया गया है. सच्चाई क्या है, यह तो पुलिस के लिए गहन पड़ताल का विषय है. लेकिन एसटीएफ के द्धारा रामानंद यादव के पुत्र रौशन यादव सहित पांच अपराधियों को हथियारों के जखीरा सहित गिरफ्तार किया जाना कोसी वासियों को नागवार गुजरा है.**





ऐसी बात नहीं है कि पुलिस के द्वारा अपराधिक गिरोहों पर लगाम लगाने की दमदार कोशिशें नहीं हुई हैं. ऐसे गिरोहों को नेस्तनाबूद किए जाने को लेकर अक्सर कोसी के दियारा में पुलिसिया अभियान चला है और कई बार अपराधिक गिरोह के सदस्य पुलिस के हत्थे भी चढ़े हैं. कई नामी-गिरामी अपराधी मुठभेड़ में भी मारे गए हैं. लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार महज पैंतीस बीघे जमीन को लेकर गैंगवार की जो पृष्ठभूमि तैयार हुई है, इसकी पटकथा समस्तीपुर जिले के एक अपराधिक पृष्ठभूमि के जनप्रतिनिधि ने लिखी है. इसमें सहरसा के एक बाहुबली नेता के भी शामिल होने की बात कही जा रही है. स्थिति विस्फोटक होती जा रही है. पटना से आई एसटीएफ टीम ने दो नदियों को पार कर इस खूनी खेल पर विराम लगाने की कोशिश की. लेकिन पैक्स अध्यक्ष राजेश यादव हत्याकांड के नामजद अभियुक्त कुख्यात दस्यु सरगना रामानंद यादव की गर्दन पुलिस के हाथ नहीं आ सकी. हालांकि चर्चा यह भी है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण रामानंद यादव को पैक्स अध्यक्ष हत्याकांड का नामजद अभियुक्त बनाया गया है. सच्चाई क्या है, यह तो पुलिस के लिए गहन पड़ताल का विषय है. लेकिन एसटीएफ के द्वारा रामानंद यादव के पुत्र रौशन यादव सहित पांच अपराधियों को हथियारों के जखीरा सहित गिरफ्तार किया जाना कोसी वासियों को नागवार गुजरा है. खगड़िया-सहरसा सीमा के समीप स्थित चिड़ैया थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एसटीएफ ने जिस तरह से आधी रात को धावा बोला, उससे भी ग्रामीण गुस्से में हैं. वैसे लगभग पांच वर्षों से कोसी का दियारा इलाका शांत पड़ा था. 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए नदियों के कोख से निकली जमीन पर अपराधिक गिरोह हुकूमत कर रहे थे. लेकिन पैक्स अध्यक्ष राजेश यादव हत्याकांड ने शांत नदी में पत्थर मारने का काम किया है. इसके बाद रामानंद पहलवान गिरोह तथा एसटीएफ के बीच मध्य रात्रि में हुई गोलीबारी, हलचल के रूप में सामने आई है. इस घटना ने बिहार के अपराध जगत, आर्थिक तंत्र और राजनीति को भी प्रभावित किया है. अभी भी खूनी टकराव की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता. ■

feedback@chauthiduniya.com

# अपनी बदहाली पर रो रहा है गांधी स्टेडियम

सुरेश चौहन
feedback@chauthiduniya.com

वादा किया गया था गांधी स्टेडियम को 'चक डे इंडिया' बनाने का, लेकिन वह बन गया खंडहर. यूं तो बेगूसराय को खेलकूद की नर्सरी कहा जाता है, लेकिन सुयोग्य माली के बिना इस नर्सरी का वांछित विकास नहीं हो पा रहा है. यहां खिलाड़ी अपने दमखम, आत्मबल एवं दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर खेल जगत में अपनी खास पहचान बना रहे हैं. कबड्डी, वॉलीबॉल, ताइकान्डो, फुटबॉल, एथलेटिक्स आदि में बेगूसराय की कोई सानी नहीं है. लेकिन बिहार सरकार एवं जिले के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा एवं उदासीनता से जिले में खूलकूद का स्तरीय उन्नयन नहीं हो पा रहा है. जिले में खेलकूद के संसाधनों की भारी किल्लत है. खेलकूद उपकरण की बात तो दूर, एक भी स्तरीय स्टेडियम नसीब नहीं है. आज जिले के सैकड़ों खिलाड़ी अपने दमखम पर वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर रेलवे, बिहार पुलिस, राज्य ट्रान्सपोर्ट, पी. एण्ड टी. सहित अनेक प्रतिष्ठानों में सेवारत हैं.

भारतीय खेल प्राधिकरण के सर्वे रिपोर्ट में कहा गया था कि, बेगूसराय जिला गंगा एवं गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है. यहां के बच्चों में वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स एवं कुश्ती आदि खेलकूद की प्रतिभा पायी जाती है. अत: यहां क्रीड़ा विकास केन्द्र की स्थापना की जाय. उक्त रिपोर्ट के आधार पर बेगूसराय में वॉलीबॉल का क्रीड़ा विकास केन्द्र स्थापित किया गया. प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के आधार पर खिलाड़ियों का चयन कर इस केन्द्र में सरकारी खर्च पर पढ़ाई के साथ प्रशिक्षण प्रारम्भ हुआ. लेकिन क्षेत्रवाद की राजनीति एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के कारण बेगूसराय के क्रीड़ा विकास केन्द्र को दूसरे जिले में शिफ्ट कर दिया गया.

सरकार सहित सभी खेलकूद संगठनों द्वारा हमेशा यह कहा जाता है कि स्कूल स्तर से ही बच्चों में खेलकूद के प्रति जागरूकता पैदा कर रूचि के अनुरूप इसके प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए. बेगूसराय जिले के 85 उच्च विद्यालयों में से लगभग 20 के पास खेलकूद का मैदान उपलब्ध है. जहां आउटडोर/इनडोर स्टेडियम का निर्माण कराया जा सकता है. वर्ष 2008 में तत्कालीन उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा, बेगूसराय ने पत्रांक 117 दिनांक 28/05/2008 द्वारा बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को विद्यालयों की एक सूची समर्पित की थी. जिसमें कहा गया था कि जिले में खूलकूद के विकास के लिए कॉलेजिएट इन्टर स्कूल, उच्च विद्यालय मटिहानी, शाम्हो, वीरपुर, तेयाय, मनसूरचक, बलिया, शालिग्रामी, नावकोठी, मंझौल, सकरपुरा एवं उच्च विद्यालय गढ़पुरा में आउटडोर और बीहट, आरकेसी, नारेपुर एवं उच्च विद्यालय छौड़ाही में इन्डोर स्टेडियम का निर्माण कराया जाय. इसके साथ ही जीडी कॉलेज बेगूसराय, एपीएसएम कॉलेज बरौनी में आउटडोर स्टेडियम के निर्माण का भी प्रस्ताव भेजा गया था. लेकिन आज 8 साल बाद भी इस दिशा में कदम नहीं उठाया जाना राज्य सरकार के खेलकूद के प्रति नकारात्मकता को उजागर करता है.

यूं तो जिले में गांधी स्टेडियम बेगूसराय, बरौनी रिफाइनरी स्टेडियम एवं खेलगांव स्टेडियम बरौनी फ्लेग है. जिला मुख्यालय का गांधी स्टेडियम खेल का मैदान नहीं रहकर मल्टीपरपस मैदान बनकर रह गया है. यहां डिजनीलैंड मेला, विकास मेला लगता है. स्टेडियम के पूर्वी भाग का गैलरी खंडहर बन चुका है. यह स्टेडियम जुए का अड्डा एवं पैरेडग्राउन्ड बनकर रह गया है. तत्कालीन स्थानीय विधायक एवं बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री डा. भोला सिंह ने गांधी स्टेडियम में आयोजित खेल पुरस्कार वितरण समारोह में घोषणा की थी कि गांधी स्टेडियम का 'चक डे इंडिया' के तर्ज पर विकास कर दूधिया रोशनी से जगमग किया जाएगा. स्टेडियम तो खंडहर बन गया, लेकिन माननीय लोक सभा पहुंच गए. बरौनी रिफाइनरी स्टेडियम निजी है जबकि बरौनी फ्लेग के स्टेडियम का निर्माण कार्य ठप है. उपरोक्त तीनों स्टेडियम स्तरीय नहीं है. उच्च विद्यालय मटिहानी एवं बरौनी कॉलेज में आउटडोर स्टेडियम निर्माण के लिए अग्रिम राशि का आवंटन भी आया लेकिन जिला पदाधिकारी की उदासीनता के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है. दूसरी ओर जिला का खेल कार्यालय एक आदेशपाल के सहारे चल रहा है. ■

टीबी का इलाज है आसान
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
डॉ. एन. आजम एम.डी. फिजिशियन
नेशनल हेल्थ केयर हरिश्चन्द्र स्टेडियम के अपोजिट अरविन्द प्रेस, नवादा

नवादा में डॉ. एन.आजम ने अपने निजि क्लीनिक से बात करते हुए जानकारियां शेयर की उन्होंने बताया कि एक टी.बी. का मरीज एक बार खांसता है तो 40 हजार से ज्यादा बैक्टिरिया बाहर निकलता है जिससे लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं। इस तरह यदि वह हंसता है या बोलता है तो उससे भी बैक्टिरिया निकलता है, इस तरह से इन मरीजों को पट्टी लगा कर रहना चाहिए। टी.बी. सिर्फ फेफड़े का ही नहीं बल्कि शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। डॉ. आजम का कहना है कि हर जगह वातावरण में बैक्टिरिया मौजूद है और यह आप पर डिपेन्ड करता है कि आप अपना इन्म्यूनिटी कितना मजबूत रखते हैं। सरकार के बेहद प्रयास के बावजूद आज भी टी.बी. और हेपटाइटिस बी के मरीजों की संख्या है। हेपटाइटिस बी के बारे में बताया कि इसकी पहचान हमें किसी और बीमारी के चेकअप के दौरान और खासकर जॉन्डीस के मरीजों में दिख जाती है तो वहीं उन्होंने टी.बी. के मरीजों की संख्या में खास कमी नहीं होने पर भी चिंता जताई और बताया कि अभी भी अवेयरनेस की जरूरत है टी.बी. के मरीजों में 15 दिनों से अधिक खांसी रहती है साथ ही कफ रहता है जिसमें बलगम आता रहेगा। शुरूआती स्टेज में पता नहीं चलता इसलिए लोगों को सर्तक होकर इसकी जांच करवा लेनी चाहिए खखार के साथ यदि रेडिस आता है तो यह दूसरे स्टेज में है इससे पहले यदि बलगम के साथ शाम को फीवर रहता हो, भूख नहीं लग रहा हो वजन घट रहा हो आदि लक्षणों के बाद आप तुरंत सतर्क हो जाएं। अपने इम्यूनिटि सिस्टम को मजबूत रखने के लिए ढेर सारा पानी पिने के अलावे दैनिक दिनचर्या में बैलेंस डायट, के साथ-साथ एक्सरसाईज अपनायें। ■ भारती

ACOBA CAP/SYP/INJ
Methylcobalmin, Lycopene, Multivitamin Multimineral, Ginseng & Antioxident
Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
ASRFEN-P
Acedofenac+Paracetamol Serratiopeplidase Tab.
ECTALOPAM
Escilalopram oxalate & Clonazepam Tablets
SILIPLEX
Silymarin, Vitamin B-Complex & Lactic acid, Calcium, Bacillus Cap/Syp
NOKSIRA
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.

बालमुकुन्द
डायमंड टी.एम.टी.
IS:1786
CM/L5125752
नं01 छड़ बालमुकुन्द पीढ़ियां चलें
इसमें है दम
FE 500+
यही है नम्बर 1
सभी प्रकार के निर्माण में मजबूती एवं सुरक्षा की गारन्टी
To know more about Balmukund Diamond TMT
Website : www.balmukundtmt.com, Email : bconcast@yahoo.com

# सपा का पारिवारिक झगड़ा, बसपा का मुस्लिम वोटों

# झगड़ा और रगड़ा में चुनाव तगड़ा

प्रभात रंजन दीन

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सामने है. सारे राजनीतिक दल अपने-अपने पैंतरे और अपने-अपने हथकंडे से आम जनता पर प्रभाव कायम करने में लगे हैं. लेकिन आप विहंग दृष्टि डालें तो पाएंगे कि हर चुनाव में मुद्दे बदल जाते हैं और नेताओं के बयान नई-नई शक्लें ले लेते हैं.

2017 का विधानसभा चुनाव भी इस बार नई शक्ल में सामने आ रहा है. आम जन से जुड़ा मुद्दा नदारद है. समाजवादी पार्टी का पारिवारिक झगड़ा है, बसपा का मुस्लिम वोटों के लिए रगड़ा है और नोटबंदी पर भाजपा का जोर तगड़ा है. विकास के नाम पर एक्सप्रेस-वे और मेट्रो है, किसानों की पीड़ा, गन्ना किसानों के अरबों के बकाये, युवाओं की भारी बेरोजगारी, श्रम जगत और गैर-सरकारी नौकरी से आजीविका चलाने वाले मध्यम वर्ग की भीषण दुश्वारियां और आम आदमी की सुरक्षा जैसे मसलों पर कहीं भी किसी भी दल में चिंता का कोई भाव नहीं दिखता. सारे दल आम जनता को फिर से बेवकूफ बना कर वोट हथियाने की जुगत में लगे हैं. जनता के पास बेवकूफ बनने के सिवा और कोई चारा भी नहीं है. वोट देने के अधिकार के अलावा उसके पास कुछ नहीं और उस अधिकार में शक्ति कुछ नहीं.

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में नेताओं के चरित्र की तरह बदलते रहे मुद्दों पर विहंगम दृष्टि डालें तो पाते हैं कि प्रत्येक विधानसभा चुनाव में मुद्दे अलग-अलग रूप से लेते हैं. 1989 से उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकार है. इसके 28वें साल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के पुनर्जीवित होने का कोई संकेत नहीं मिल रहा है. कांग्रेस के पास कोई ऐसा मुद्दा भी नहीं रहा है, जो आम-जन को छू सके. 27 वर्षों में उत्तर प्रदेश में सात चुनाव हुए जिसमें केवल तीन बार ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनी. 1991 में कल्याण सिंह की सरकार, 2007 में बसपा सरकार और 2012 में सपा सरकार पूर्ण बहुमत से आई. हालांकि अयोध्या आंदोलन और बाबरी विध्वंस के कारण कल्याण सिंह की सरकार अधिक दिन नहीं चल पाई थी. अब फिर 2017 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इस चुनाव पर पूरे देश की दृष्टि लगी हुई है. केवल बहुमत की सरकार का मसला नहीं है, मसला प्रतिष्ठा से जुड़ा है. अंतर्कलह झेल रही सपा सत्ता में वापस लौटती है कि नहीं, बसपा सोशल-सिलीजियस इंजीनियरिंग के बूते सत्ता हासिल करती है कि नहीं, भाजपा मोदी-नोटबंदी के बल पर उभर कर राजनीतिक-परिदृश्य पर छाती है कि नहीं. इसमें कांग्रेस या छोटे दलों की भूमिका क्या होती है, यह कदाचित उतना मायने नहीं रखेगा.

## 1989 में था बोफोर्स और गैर-कांग्रेसवाद

1989 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा और लोकसभा का चुनाव दोनों ही बोफोर्स के मुद्दे और गैर-कांग्रेसवाद के नारे पर हुआ था. केंद्र में वीपी सिंह के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़े गए. गैर-कांग्रेसवाद के नारे पर हुए चुनाव में भाजपा और जनता दल ने एक साथ मिलकर 415 सांसदों वाली भारी बहुमत की कांग्रेस की सरकार को धराशाई कर दिया था. केंद्र में भाजपा के समर्थन से वीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी. उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में 5 दिसम्बर 1989 को सरकार का गठन हुआ था. इस चुनाव में कांग्रेस 28 प्रतिशत मत पाकर 94 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि जनता दल ने 29.59 प्रतिशत मत पाकर 204 सीटों पर कामयाबी पाई थी. भाजपा 11.68 प्रतिशत मत पाकर 57 सीटों पर काबिज हुई थी. उस चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता कांशीराम के नेतृत्व में गठित बसपा को जनता की तरफ से मिली मान्यता थी. पहली बार 9.33 प्रतिशत वोट पाकर बसपा 13 सीटों पर जीती थी. उस बार के चुनाव में निर्दलियों की संख्या भी काफी थी. 15.32 प्रतिशत मत के साथ 40 निर्दलीय सदस्य विधानसभा पहुंचे थे. इन निर्दलियों में दर्जनभर से अधिक विधायक आपराधिक पृष्ठभूमि के थे. 1989 के चुनाव में लोकदल (बी) नाम से बने दल ने 204 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन उसे महज दो सीटें मिली थीं. चौधरी अजित सिंह जनता दल के महत्वपूर्ण नेता के रूप में शामिल थे.

## धार्मिक उन्माद में बदल गया था 1991 का विधानसभा चुनाव

1991 में विधानसभा चुनाव धार्मिक उन्माद के माहौल में हुआ, जिसमें भाजपा पहली बार बहुमत की सरकार बनाने की ताकत के साथ उभर कर सामने आई. कल्याण सिंह के नेतृत्व में 24 जून 1991 को भाजपा की बहुमत की सरकार बनी. 1991 के चुनावी मुद्दे में मंडल और कमंडल की राजनीति हावी रही थी. 1989 में केंद्र में बनी वीपी सिंह की सरकार का भविष्य अधर में था. चंद्रशेखर और देवीलाल जैसे अगरधत्तों की खींचतान थी. देवीलाल पिछड़ों के सर्वमान्य नेता के रूप में उभर कर शक्ति-संतुलन बिगाड़ रहे थे. ऐसे में वीपी ने मंडल रिपोर्ट लागू कर देशभर में राजनीतिक-सामाजिक सनसनी फैला दी. पूरे देश में बवाल खड़ा हो गया. अगड़े पिछड़े की जंग छिड़ गई. छात्रों के आत्मदाह होने लगे. इस हालात में भाजपा ने वीपीसिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया. भाजपा ने मंडल के खिलाफ कमंडल का आंदोलन शुरू कर दिया. लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में सोमनाथ से (शेष पृष्ठ 2 पर)

## मुद्दे तो बदल रहे, पर सर्वेक्षण अब भी निगाह में

कुछ अर्सा पहले उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के बीच किया गया एक सर्वेक्षण तात्कालिक तौर पर खूब सुर्खियों में रहा, लेकिन जैसे-जैसे समय आगे खिसक रहा है और तेज गति से मुद्दे बदल रहे हैं, वह सर्वेक्षण अप्रासंगिक होता जा रहा है. हालांकि राजनीतिक समीक्षकों का कहना है कि वह सर्वेक्षण अब भी निगाह में है और बदलते समीकरण को सर्वेक्षण की कसौटी पर भी रख कर देखा जा रहा है. उक्त सर्वेक्षण एक समाचार चैनल और सर्वे एजेंसी ने साझा तौर पर किया था. उस सर्वेक्षण पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया भी जताई थी, क्योंकि सर्वे ने मायावती को सम्भावित मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया था.
सर्वे में सामने आया था कि प्रदेश के मतदाता पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को 2017 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं. लोगों की पसंद के आधार पर सर्वे में मायावती को 31 फीसदी, अखिलेश को 30 फीसदी, राजनाथ को 18 फीसदी, राहुल गांधी को सात फीसदी, स्मृति को चार फीसदी और प्रियंका गांधी को दो फीसदी मत मिले थे. सर्वे में लोगों से जब अखिलेश सरकार के चार साल का हाल पूछा गया तो सामने आया कि अखिलेश सरकार से 32 फीसदी लोग संतुष्ट हैं, जबकि 34 फीसदी ने खराब और बहुत खराब कहा. इसका विस्तार यह है कि सात फीसदी लोगों ने अखिलेश सरकार को बहुत अच्छा कहा, 25 फीसदी ने अच्छा बताया और 29 फीसदी लोगों ने औसत बताया. 23 फीसदी लोगों ने अखिलेश सरकार को खराब कहा और 11 फीसदी लोगों ने बहुत खराब बताया. मार्च महीने में हुए सर्वे में लोगों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताया था. इसमें 29 फीसदी लोगों ने बेरोजगारी, 22 फीसदी लोगों ने महंगाई, 17 फीसदी लोगों ने भ्रष्टाचार और 15 फीसदी लोगों ने गरीबी को सबसे बड़ा मुद्दा बताया था. अयोध्या, मथुरा, काशी जैसे मुद्दों को मतदाताओं ने खारिज कर दिया था.
अधिकतर लोग यूपी में कानून व्यवस्था की बदहाली स्वीकार करते हैं. 60 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कहा था कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है. 68 फीसदी लोग मानते हैं कि उन्होंने अपने इलाके में किसी बड़े विकास का काम होते हुए नहीं देखा. 39 फीसदी लोगों ने कहा कि अखिलेश सरकार में भी काफी भ्रष्टाचार हुआ.

# के लिए रगड़ा, नोटबंदी पर भाजपा का जोर तगड़ा

पृष्ठ 12 का शेष

अयोध्या तक की रथ यात्रा ने राम जन्मभूमि आंदोलन को धार्मिक उन्माद की शक्ल में बदल डाला. भाजपा के समर्थन वापस लेने के बाद कांग्रेस के समर्थन से चन्द्रशेखर की सरकार बनी. उत्तर प्रदेश में भी जनता दल का विभाजन हो गया. यूपी में भी कांग्रेस के समर्थन से मुलायम सिंह यादव सरकार बची रही. दिसम्बर 1989 से 24 जून 1991(भाजपा सरकार के गठन तक) उत्तर प्रदेश में अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर धार्मिक उन्माद कायम रहा. आडवाणी की रथयात्रा को बिहार में लालू प्रसाद यादव ने रोका, उनकी गिरफ्तारी की नौटंकी हुई. उत्तर प्रदेश में मुलायम ने 45 दिनों में 48 रैलियां कीं और अपने मुस्लिम-यादव वफादारों से प्रतिशोधी माहौल खड़ा कर दिया. हिंदू और मुसलमानों के बीच जबरदस्त तनाव बन गया. लेकिन इस उन्माद से बने ध्रुवीकरण का फायदा भाजपा को मिला और उत्तर प्रदेश में भाजपा की बहुमत की सरकार बनी. यूपी में मंडल पर कमंडल जीत गया. कल्याण सिंह मुख्यमंत्री तो बने लेकिन अधिक दिन नहीं चल पाए. छह दिसम्बर 1992 से सरकार बर्खास्तगी तक अयोध्या मुद्दा ही छाया रहा. चुनाव के दौरान ही 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हो गई. नतीजतन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 244 सीटों के साथ अप्रत्याशित सफलता मिली. नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने. 120 सीटें पाकर भाजपा दूसरे स्थान पर रही और 69 सीटों के साथ जनता दल को तीसरा स्थान मिला. इधर यूपी में 1991 के विधानसभा चुनाव में मंडल-कमंडल के बावजूद बसपा का मत प्रतिशत बढ़ा. बसपा को 9.52 प्रतिशत मत के साथ 12 सीटें मिलीं. भाजपा ने 31.80 प्रतिशत मत के साथ 211 सीटों पर जीत हासिल की. कांग्रेस को 46 सीटें मिलीं. सबसे खराब हालत मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली तत्कालीन जनता पार्टी की हुई. सत्ता पर रहते हुए मुलायम को 12.45 वोट के साथ महज 30 सीटें हासिल हुईं, जबकि उनके प्रत्याशी 411 सीटों पर चुनाव लड़े थे. उस समय यूपी विधानसभा में 425 सीटें थीं. तब उत्तरांचल नहीं बना था.

## 1993 में सपा-बसपा गठबंधन ने बनाया नया जातीय समीकरण

1991 में हाशिए पर जाने के बाद मुलायम ने बसपा के साथ तालमेल बनाया और राजनीति के केंद्र में बने रहे. बसपा के गठजोड़ से 4 दिसम्बर 1993 को दूसरी बार मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने. 1989 के बाद भाजपा ने धार्मिक उन्माद का फायदा उठाया था, लेकिन मुलायम ने इसे अपने दलित-पिछड़े गठजोड़ से कमजोर कर दिया. छह दिसम्बर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिरने के बाद यूपी समेत भाजपा शासित चार राज्यों की सरकार बर्खास्त कर दी गई थी. 1993 में फिर चुनाव हुए और सपा-बसपा गठबंधन ने जातीय समीकरण बना कर जीत हासिल कर ली. सपा 264 सीटों पर चुनाव लड़ी और 17.82 प्रतिशत मत पाकर 109 सीटों पर जीती. बसपा 163 सीटों पर चुनाव लड़ी और 67 सीटों पर जीती. बसपा को 11.11 प्रतिशत वोट मिले थे. 1991 में 30 सीटें पाकर हाशिए पर चली गई समाजवादी पार्टी ने 1993 के चुनाव में पांच प्रतिशत अधिक मत हासिल किए और तीन गुना अधिक सीटें जीतकर राजनीति के केंद्र में आ गई. बसपा को भी इस गठबंधन का फायदा हुआ, उसकी सीटें 12 से बढ़कर 67 हो गईं. कांग्रेस को 28 सीटें मिलीं. लेकिन सपा-बसपा का गठबंधन अधिक दिन तक नहीं चला. दो जून 1995 को हुए बहुचर्चित गेस्ट-हाउस कांड के बाद राजनीतिक समीकरण बदल गए और भाजपा के समर्थन से पहली बार मायावती के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनी. चार महीने बाद ही 17 अक्टूबर 1995 को भाजपा ने समर्थन वापस लिया और प्रदेश में एक बार फिर राष्ट्रपति शासन लग गया.

## 1996 विधानसभा चुनावः मारपीट, विश्वासघात और अमर्यादा का रिकॉर्ड

राम जन्मभूमि आंदोलन और सपा-बसपा के अप्रत्याशित गठबंधन के बाद 1996 में फिर एक नया समीकरण सामने आया. इस बार बसपा ने कांग्रेस से समझौता किया और साम्प्रदायिकता के खिलाफ नारा देकर चुनाव लड़ा गया. लेकिन 1996 के चुनाव में बसपा-कांग्रेस समीकरण नहीं चला और 175 सीटें जीत कर भाजपा सबसे बड़े दल के तौर पर सामने आई. बसपा को 67 सीटें मिलीं और कांग्रेस को 33 सीटें हासिल हुईं. 1996 के चुनाव में बसपा कांग्रेस गठबंधन के साथ मैदान में उतरी थी, लेकिन उस चुनाव में किसी भी दल को बहुमत हासिल नहीं हुआ. सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भाजपा को सरकार बनाने का मौका नहीं मिला और 17 अक्टूबर 1996 को प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया. यह 21 मार्च 1997 तक रहा. इसके बाद प्रदेश का राजनीतिक समीकरण फिर बदला और भाजपा-बसपा में छह-छह महीने सरकार चलाने का करार हुआ. मायावती पहले खेप में मुख्यमंत्री बनीं, लेकिन अपना खेप पूरा कर लेने के बाद उन्होंने एक सितम्बर 1997 को गठबंधन तोड़ दिया और भाजपा से समर्थन वापस ले लिया. मायावती ने इसके पीछे दलित एक्ट को लेकर हुए विवाद को कारण बताया. किसी तरह जद्दोजहद करके भाजपा ने सदन में अपना बहुमत सिद्ध किया. उस दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायकों की मारपीट भी राजनीतिक इतिहास का हिस्सा बनी. इस बीच कल्याण सिंह से लेकर राम प्रकाश गुप्त और राजनाथ सिंह तक मुख्यमंत्री बने. प्रदेश के इतिहास में यह भी पहली बार ही हुआ कि 103 विधायकों में से 100 विधायकों को मंत्री की कुर्सी मिली.

## राजनीतिक अस्थिरता और जम्बो मंत्रिमंडल था 2002 का चुनावी उत्पाद

2002 के विधानसभा चुनाव में राजनाथ सिंह कार्यकाल का सौ सदस्यीय जम्बोजेट मंत्रिमंडल भी एक बड़ा बना चुनावी मुद्दा था. लेकिन चुनाव परिणाम किसी भी दल के पक्ष में निर्णायक रूप में नहीं आया. उस समय भाजपा और चौधरी अजित सिंह साथ मिलकर चुनाव लड़े थे. भाजपा 86 सीटें जीती और चौधरी के 14 विधायक चुने गए. सपा 141 सीटों पर जीत हासिल कर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी. बसपा 1996 की तुलना में 4.5 प्रतिशत मत अधिक पाने 23.1 प्रतिशत मत पाकर 98 सीटों पर काबिज हुई. कांग्रेस के पास 25 सीटें रह गईं. सबसे बड़े दल के रूप में आने के बावजूद सरकार बनाने का मौका नहीं दिए जाने के विरोध में सपा ने राजभवन के आगे धरना दिया था. उसी धरने में एक विधायक की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. आठ मार्च 2002 को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया. दो महीने बाद ही भाजपा ने फिर बसपा को समर्थन दिया और तीन मई 2002 को उत्तर प्रदेश में मायावती के नेतृत्व में बसपा-भाजपा की फिर से मिलीजुली सरकार बनी जो 29 सितम्बर 2003 तक चली. भाजपा से विवाद का बहाना बना कर मायावती ने इस्तीफा दे दिया और विधानसभा चुनाव कराने की सिफारिश कर दी. केंद्र ने मायावती की सिफारिश नहीं मानी और कांग्रेस, रालोद व अन्य दलों के समर्थन से सपा की सरकार बनवा दी. याद करते चलें कि तीन मई 2002 को बसपा-भाजपा की मिली जुली सरकार बनने के बाद से ही मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर विरोध शुरू हो गया था. रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया और अन्य कई विधायक सरकार बनने के बाद से ही असंतोष जाहिर कर रहे थे. मायावती के इस्तीफा देने के बाद सपा को मौका मिल गया और उसने बसपा और भाजपा के नाराज विधायकों को तोड़ कर अपने में शामिल कर लिया. सपा को कांग्रेस का भी समर्थन मिला और सपा की सरकार बन गई. विधायकों को तोड़ने और सरकार बनवाने में अमर सिंह ने भी सक्रिय भूमिका अदा की, लेकिन कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सपा सरकार की साख जाती रही.

## 2007 के चुनाव में कानून व्यवस्था ही मुद्दा थी

वर्ष 2007 का विधानसभा चुनाव यूपी की बदहाल कानून व्यवस्था पर केंद्रित हो गया था. 'चढ़ गुंडों की छाती पर, मुहर लगाओ हाथी पर' का नारा बसपा के ऊंचे हो रहे ग्राफ को इंगित कर रहा था. मायावती की सोशल इंजीनियरिंग ने ब्राह्मण समुदाय को बसपा की तरफ झुका दिया था. दलित-ब्राह्मण गठजोड़ का परिणाम यह रहा कि उत्तर प्रदेश में 1991 के बाद का रिकॉर्ड टूटा और मायावती के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी. बसपा का 2002 का 23.18 मत प्रतिशत बढ़ कर 30.46 प्रतिशत हो गया. सपा की सीटें कम होकर 97 रह गईं. भाजपा का ग्राफ काफी नीचे गिर गया और उसका मत प्रतिशत 20.03 से घट कर 16.93 रह गया.

## मायावती के भ्रष्टचार ने 2012 में सपा को सत्ता पर बिठा दिया

2012 के विधानसभा चुनाव में नए परिसीमन के बाद विधानसभा क्षेत्र के जातीय, धार्मिक और राजनीतिक समीकरण बदले. 2007 के विधानसभा चुनाव में 70 से अधिक विधानसभा सीटें ऐसी थीं, जिनकी आबादी 15 लाख से अधिक थी और 107 विधानसभा सीटें ऐसी थीं, जिनकी आबादी तीन से चार लाख थी. विधानसभा क्षेत्र के नए परिसीमन में 403 विधानसभाओं की आबादी लगभग बराबर हो गई. औसत जनसंख्या साढ़े चार लाख हो गई. नए परिसीमन से सभी विधानसभा क्षेत्रों में बदलाव आया. 2012 के विधान सभा चुनाव में मायावती सरकार का भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा रहा. जिस तरह लखनऊ से लेकर नोएडा तक मूर्तियों, पार्कों और स्मारकों के निर्माण में अरबों-खरबों रुपये खर्च किए गए, उससे जनता में बसपा के खिलाफ भीषण आक्रोश था. इसके अलावा बसपा ने 2007 में सपा सरकार में बढ़ते अपराध के खिलाफ मुहिम चला कर सत्ता हासिल की थी, लेकिन बसपा सरकार में भी कानून व्यवस्था की वही बदहाल हालत हो गई. सपा सरकार के आपराधिक छवि के कई नेता पैसे के बूते बसपा में शामिल हो गए. बसपा सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल में एनआरएचएम घोटाला, दो-दो सीएमओ की हत्या, अकूतखनन घोटाला, आबकारी घोटाला, पत्थर घोटाला और स्मारक घोटाला जनता के दिमाग पर छा गया. समाजवादी पार्टी ने इसका फायदा उठाया. सपा के अखिलेश यादव के नौजवान नेतृत्व के प्रति आशा रखते हुए जनता ने सपा को रिकॉर्ड बहुमत के साथ सत्ता तक पहुंचा दिया. पंचायतों के चुनाव में प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर जिस तरह बसपा ने धन-बल के बूते कब्जा किया था, वह भी बसपा के ताबूत में ढेर सारे कील की तरह धंस गया. 2012 में सपा ने 224 सीटें जीतीं. उसे 29.15 प्रतिशत वोट मिले. बसपा 80 सीटों पर सिमट गई. भाजपा को 47 सीटें और कांग्रेस को 28 सीटें मिलीं. राष्ट्रीय लोक दल को नौ सीटें ही मिलीं. इसी तरह पीस पार्टी को चार, कौमी एकता दल को दो, एनसीपी, अपना दल और तृणमूल कांग्रेस को एक-एक सीटें मिलीं. आधा दर्जन निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव जीते.

## अब सामने है 2017 का विधानसभा चुनाव

कुछ दिन पहले तक यह लग रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ केंद्र सरकार का सर्जिकल स्ट्राइक उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए चुनावी मुद्दा बनेगा. इसकी जोरशोर से शुरुआत भी कर दी गई थी. लेकिन अचानक अब नोटबंदी का मसाला सामने आ गया. नोटबंदी के मसले को लेकर ही सारे राजनीतिक दल भाजपा को घेरने में लग गए हैं. अब तक के दूसरे राजनीतिक सर्जीकल और मसले-मसाएल ध्वस्त हो गए हैं. समाजवादी पार्टी विकास के मसले को चुनाव में उठा रही है, लेकिन सपा का अंदरूनी झगड़ा सारे दावों पर विरोधाभास की स्थिति पैदा कर रहा है. बसपा के सारे बड़े नेता दल छोड़ कर अलग हो गए. इस झटके से उबरने के लिए मायावती दलित-मुस्लिम गठजोड़ स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं. यह प्रयास सपा के खोट वैंक में सेंधमारी करने जैसा है. बसपा की यह नई सोशल इंजीनियरिंग है.

अभी तक यही लग रहा था कि चुनावी मुद्दा विकास, भ्रष्टाचार, जातिवाद और सख्त कानून व्यवस्था वाली स्थिर सरकार देने का ही होगा, लेकिन स्थितियां जिस तरह बदलीं, उससे चुनावी मुद्दा भी बदलेगा. सपा और बसपा के अलावा भाजपा भी अति-पिछड़े मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने में लगी है. सपा और बसपा मुसलमानों को रिझाने में लगी है, तो भाजपा अति पिछड़ों के साथ-साथ दलितों और सवर्ण मतों को एकीकृत करने की कवायद में लगी है. 27 वर्षों से सत्ता से बाहर कांग्रेस भी जद्दोजहद कर रही है. लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए फिल्म अभिनेता राजबब्बर को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, तो ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री के प्रत्याशी के बतौर प्रोजेक्ट कर दिया. ठाकुर, ब्राह्मण और पिछड़े व दलित और अल्पसंख्यक मतों को जोड़ने के लिए भी कांग्रेस के बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है. प्रियंका गांधी को भी आगे बढ़ाया जा रहा है. इसके साथ ही कांग्रेस छोटे दलों के साथ महागठबंधन कायम करने की तैयारी में लगी है. प्रदेश की राजनीति में जातीय और धार्मिक ध्रुवीकरण के प्रयासों पर नोटबंदी का मसला हावी हो गया है. ऐसे साम्प्रदायिकता, विकास, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था का मुद्दा कहीं छाया-क्षेत्र में न चला जाए, इस बात की आशंका है. वाकई 2017 में होने वाला उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

## 2017 में गठित होगी 17वीं विधानसभा

उत्तर प्रदेश विधानसभा दो सदनों वाले विधानमंडल का निचला सदन है. इसमें 403 निर्वाचित सदस्य और राज्यपाल द्वारा मनोनीत एक आंग्ल भारतीय सदस्य होते हैं. शीर्ष सदन विधान परिषद में कुल 100 सदस्य होते हैं. वर्ष 1967 तक एक आंग्ल भारतीय सदस्य को सम्मिलित करते हुए विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 431 हुआ करती थी. वर्ष 1967 के बाद विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 426 हो गई. नौ नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 403 और एक आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनीत सदस्य को मिला कर 404 हो गई. उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन आठ मार्च 1952 को हुआ था. तब से इसका गठन 16 बार हो चुका है. मौजूदा सोलहवीं विधानसभा का गठन आठ 8 मार्च 2012 को हुआ था. 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का 17वीं बार गठन होगा.

# अभी से महसूस हो रहा नोटबंदी का असर

चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि नोटबंदी का मसला उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रभावकारी रोल अदा करेगा. उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप माथुर का भी कहना है कि नोटबंदी के बाद की स्थितियों में नए तरीके से चुनावी रणनीति बनानी होगी. अब छोटी रैलियों पर आना पड़ेगा और वोटरों को खुश करने के तौर-तरीकों में भी काफी कटौती हो जाएगी. कई अन्य नेताओं ने यह संकेत दिया कि अब चुनाव में सीधे तौर पर कॉरपोरेट धन दाताओं की मुख्य भूमिका होगी. प्रचार अभियानों की फंडिंग का आंकलन करने वाली संस्था सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (सीएमएस) के मुताबिक, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कुल फंडिंग के दो-तिहाई से भी कम के लिए भाजपा नकद पर निर्भर है. जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे क्षेत्रीय दल अपने प्रचार पर होने वाले कुल खर्च के 80 से 95 प्रतिशत हिस्से के लिए नकदी पर निर्भर करते हैं. चुनावों के लिए सरकारी फंडिंग नहीं होने के कारण गैरकानूनी नकदी ही राजनीतिक दलों के काम आती रही है. उसी से रैलियों के आयोजन, हेलीकॉप्टरों के इंतजाम और मतदाताओं को खुश किए जाने पर खर्च होता रहा है. नोटबंदी के कारण इस पर अचानक रोक लग गई. नोटबंदी पर बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि नोटबंदी का समय राजनीतिक इरादे से चुना गया. मायावती पर पार्टी टिकट के बदले प्रत्याशियों से पैसा लेकर काला धन जमा करने का आरोप लगता रहा है. मायावती के करीबी एक नेता ने कहा कि नोटबंदी के कारण बसपा की कुछ रैलियां रद्द कर दी जाएंगी और उसके स्थान पर घर-घर जाकर प्रचार ज़्यादा किया जाएगा. नोटबंदी के पहले बसपा की लखनऊ रैली में लोगों को जुटाने में काफी नकद खर्च हो गया. अब नकदी मुश्किल में आ गई. सपा के भी एक नेता ने कहा कि चुनाव प्रचार के नए खास-खट तौर-तरीके अख्तियार में लाए जाएंगे. नोटबंदी के कारण राजनीतिक दलों के लिए काम करने वाले इवेंट मैनेजर भी विलोप-भवन में चले गए हैं. उनका कामकाज चुनाव के दिनों में काफी फलता-फूलता था. पिछले 10 साल से लाउड स्पीकरों, आउटडोर एक्सकंडीशनर्स और रैलियों में तमाम इंतजामात करने का कारोबार करने वाले एक व्यापारी ने कहा कि अब कोई भी राजनीतिक दल जनवरी से पहले बड़ी रैली आयोजित करने के मूड में नहीं दिख रहा. तभी पार्टियां नकदी पर ही निर्भर रहती हैं. सीएमएस की रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2014 के चुनाव में पार्टियों ने 37 हजार करोड़ रुपये खर्च किए थे. ■

# युवा लेखकों को आर्चर की नसीहत

अनंत विजय

अंग्रेजी के मशहूर लेखक जैफ्री आर्चर ने भारत के युवा लेखकों को सलाह दी है कि वो सेक्स, हिंसा और भूत प्रेत के बारे में नहीं लिखें. उनकी सलाह है कि खराब भाषा से भी भारत के युवा लेखकों को बचना चाहिए. उन्होंने साफ कहा है कि भारतीय युवा लेखकों को उन्हीं विषयों पर लिखना चाहिए, जिनको लेकर लेखक को खुद पर पूरा यकीन हो यानि वो विषय को लेकर कन्विंस हों. जैफ्री आर्चर ने कहा कि लेखक को अपना काम करना चाहिए और फिर उसको जनता पर छोड़ देना चाहिए कि वो उसको पसंद करती हैं या नहीं. उन्होंने साफ तौर पर जोर देकर ये भी कहा कि जो जनता चाहती है, उस हिसाब से नहीं लिखना चाहिए बल्कि लेखक को अपने हिसाब से साहित्य सृजन करना चाहिए. जैफ्री आर्चर कोई मामूली लेखक नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया में उनके लेखन का डंका बजता है. 70 साल की उम्र में भी वो खुद के लेखन को चुनौती देते रहे हैं और लगातार नए-नए विषयों पर लिखते रहे हैं. जब उपन्यास से मन भरने लगा तो नाटक लिखना शुरू कर दिया फिर कहानी की ओर मुड़ गए. एक अनुमान के मुताबिक उनकी किताब केन एंड एबेल की करीब साढ़े तीन करोड़ प्रतियां बिक चुकी हैं. यह साहित्य में एक घटना की तरह है. इस किताब से पहले प्रकाशित जैफ्री आर्चर की दो किताबें भी बेस्ट सेलर रही हैं. दरअसल अगर हम देखें तो जैफ्री आर्चर ने अपना करियर लेखक के तौर पर तब शुरू किया, जब वो लगभग दिवालिया हो गए थे और उनपर कर्ज का भारी बोझ आ गया था. जैफ्री ऑर्चर सौ मीटर रेस के धावक रह चुके हैं, ब्रिटेन में सांसद रह चुके हैं लेकिन कारोबार में ठोकर खाने के बाद लेखक बने. कर्ज उतारा फिर राजनीति में गए.

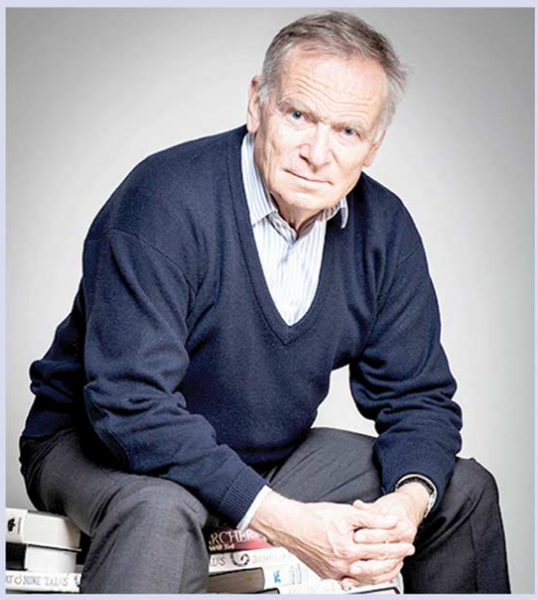

आर्थिक रूप से घिरे जैफ्री ऑर्चर ने सबसे पहले नॉट अ पेनी मोर, नॉट अ पेनी लेस लिखा जिसकी सोलह देशों में जमकर बिक्री हुई. उसके बाद तो उन्होंने लेखन को ही अपना लिया और अपने बैलेंस शीट को लेखन की कमाई से ठीक किया. गूगल के मुताबिक उनका तीसरा उपन्यास केन एंड एबेल विश्व साहित्य के इतिहास में ग्यारहवां सबसे सफलतम उपन्यास है. लियो टॉलस्टॉय के वॉर एंड पीस से सिर्फ एक पायदान नीचे. जैफ्री आर्चर का जीवन विवादों से भी भरा रहा है और वे जेल भी काट चुके हैं. लिहाजा उनका अनुभव संसार वैविध्यपूर्ण है. जैफ्री आर्चर के बारे में ये बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि उनकी सलाह को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए. उसको माना जाए या नहीं इस बात पर कम से कम विमर्श तो होना ही चाहिए. इस लेख का मकसद भी यही है.



जैफ्री आर्चर की भारत के युवा लेखकों की इस सलाह पर कई लोगों ने ये सवाल उठाए कि उनको भारत के पाठकों की रुचि का और भारतीय लेखन का क्या पता. अब ऐसे लोगों की अज्ञानता पर क्या कहा जाए. जैफ्री आर्चर का भारत से बहुत पुराना और गहरा नाता रहा है और वो नियमित तौर पर भारत आते जाते रहे हैं और भारत के बारे में उनकी एक राय भी है. भारतीय महिलाओं के बारे में जैफ्री ऑर्चर ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जब भी वो भारत आते हैं तो यहां की महिलाओं को मजबूत होते देखकर खुश होते हैं. वो भारतीय महिलाओं के सशक्तीकरण की भावना का सम्मान करते हुए कहते हैं कि नई पीढ़ी को रोकने की ताकत अब किसी में नहीं है. जैफ्री आर्चर भारत के प्रकाशन जगत की सच्चाईयों से भी वाकिफ हैं और अपनी कई किताबों को सबसे पहले भारत में ही लॉन्च करते रहे हैं. उनका मानना है कि भारत में पाइरेसी एक बड़ी समस्या है और अगर भारत में किताब बाद में लॉन्च की जाती है, तो लेखक और प्रकाशक दोनों का नुकसान हो जाता है. लिहाजा वो इसकी काट के लिए सबसे पहले अपनी किताब भारतीय बाजार में ही लॉन्च करते हैं.

अब हम आते हैं, जैफ्री आर्चर की युवा लेखकों को दी जानेवाली सलाह पर. उन्होंने सेक्स संबंध से लेकर भूत-प्रेत की कहानियां नहीं लिखने की सलाह दी है. लेकिन इन दिनों सेक्स संबंध युवा लेखकों के लेखन में लगभग अनिवार्य उपस्थिति की तरह है. कई युवा लेखकों को लगता है कि उपन्यासों में बगैर यौन संबंधों के छौंक के उसको सफल नहीं बनाया जा सकता है जबकि उनके सामने ही अमिष त्रिपाठी का उदाहरण है. जो बगैर इस तरह के विषयों को छुए दुनिया के बड़े लेखकों की लीग में शामिल हो गए हैं. दरअसल कुछ युवा, कुछ युवापन की दहलीज पार कर चुके लेखक, अपनी कहानियों में यौन संबंधों का इस्तेमाल उसी तरह करते हैं जैसे कुछ फिल्मकार अपनी फिल्मों की सफलता के लिए नायिकाओं से अंग प्रदर्शन करवाते हैं. उन्हें ये सफलता का शॉर्टकट फॉर्मूला लगता है. फिल्मों में भी जहां कहानी की मांग हो वहां अंगप्रदर्शन से परहेज नहीं करना चाहिए और साहित्य में भी जहां सिचुएशन की मांग हो वहां यौन संबंधों का वर्णन होना चाहिए. साहित्य में यौन संबंधों के वर्णन को लेकर बहस पुरानी है लेकिन जिस तरह से चेतन भगत जैसे लेखकों ने जुगुप्साजनक तरीके से चटखारे लेने के अंदाज में इस तरह से प्रसंगों पर विस्तार से लिखा है उसको जैफ्री आर्चर की टिप्पणी के आइने में देखे जाने की जरूरत है. चेतन के नए उपन्यास वन इंडियन गर्ल के कई पन्ने तो पोर्नोग्राफी को मात देते हैं. हिंदी में जब मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास चाक या फिर अल्मा कबूतरी प्रकाशित हुआ था तब भी उसमें वर्णित यौन संबंधों को लेकर साहित्य जगत में अच्छा खासा विवाद हुआ था. साहित्य के शुद्धतावादियों ने तब मैत्रेयी पुष्पा के लेखन को कटघरे में खड़ा किया था. बाद में भी इस तरह के प्रसंगों को लेकर कई कृतियां आईं. कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा के दो खंड- लगता नहीं है दिल मेरा तथा ...और औरत में इस तरह के प्रसंगों की भरमार है. हद तो बुजुर्ग लेखिका रमणिका गुप्ता ने अपनी आत्मकथा में कर दी. उनकी आत्मकथा आपहुदरी में जिस तरह के जुगुप्साजनक प्रसंगों की भरमार है वो उस किताब को साहित्य के अलग ही कोष्टक में रख देता है. जैफ्री आर्चर की सलाह युवा लेखकों को लेकर है. इन वरिष्ठ लेखकों की रचनाओं का उल्लेख इस वजह से किया गया ताकि लेखन की इस परंपरा को समझने में मदद मिले. यौन संबंध मानव जीवन की अनिवार्यता है लेकिन उसको कितना और कैसे उभारा जाए ये लेखक पर निर्भर करता है. अभी पिछले दिनों युवा लेखिका सोनी सिंह का संग्रह क्लियोपेट्रा प्रकाशित हुआ था. उनकी कहानियों में इस तरह के कई प्रसंग बेवजह आते हैं और जिस तरह के बिंबो का वो इस्तेमाल करती हैं, वो हिंदी कहानी में कुछ जोड़ता हो इसमे संदेह है. हालांकि राजेन्द्र यादव को सोनी सिंह की कहानियां अपने बेबाक बयानी के बावजूद बौद्धिक खुराक मुहैया करवाने वाली लगती हैं. संभव है कि यादव जी की तरह के कुछ पाठक साहित्य में हों. सोनी सिंह के अलावा भी कई लेखक-लेखिका इस तरह की कहानियां लिख रहे हैं. पर उनमें से ज्यादातर अपनी इस तरह की कहानियों से पाठकों को झकझोरने के बाद अलग भावभूमि पर विचरण करने लगी हैं. जिसको उनके कोर्स करेक्शन की तरह देखा जा रहा है.

जैफ्री आर्चर की इस सलाह के बाद एक बार फिर से साहित्य में इस बात पर बहस होनी चाहिए कि साहित्यिक शुचिता की सीमा कितनी हो. लेखक सिचुएशन की मांग पर कहां तक जा सकता है या जा सकती है. यौन संबंधों पर लिखने के लिए दरअसल बहुत सधे हुए दिमाग और लेखनी की जरूरत होती है. ये प्रसंग ऐसे होते हैं कि अगर लिखते वक्त लेखक का संतुलन खो गया तो वो उसके लेखन को हल्का भी कर दे सकता है या पाठक उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं. खुद लेखक को भी इस तरह के लेखन के पहले कन्विंस होना चाहिए. पाठकों को कहानियों की ओर आकर्षित करने के लिए इस तरह के प्रसंग जबरदस्ती नहीं ठूंसने चाहिए. जैफ्री आर्चर ने एक और बात कही कि बाजार की मांग के हिसाब से लेखकों को नहीं लिखना चाहिए. वो इस ओर इशारा करते है कि लेखक तो पाठकों की रुचि का निर्माण करते हैं, रुचियों के आधार पर साहित्य सृजन करने वाले लेखक नहीं बल्कि कारोबारी होते हैं. अब हिंदी के युवा लेखकों को तय करना है कि वो वैश्विक लेखक की सलाह मानते हैं या फिर शॉर्टकट सफलता के लिए पुराने फॉर्मूले को अपनाते हैं. ■

anant.ibn@gmail.com

# कर्कोटकी

## परिचय

यह भारत के सभी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 1600 मी की उंचाई तक के पहाड़ी भागों में तथा कई स्थानों की रेतीली एवं जंगली भूमि में प्रचूरता से पाया जाता है. इसके फलों का प्रयोग साग के रूप में किया जाता है. इसमें गाजर के जैसी बहुवर्षायु जड़ होती है. जिसका प्रयोग मस्तिष्क विकार, रक्तार्श, ग्रन्थि तथा मधुमेह की चिकित्सा में किया जाता है.

## औषधीय प्रयोग मात्रा एवं विधि

❖ **शिरो रोग-** कड़वे व जंगली ककोड़े के पत्तों के रस 1-2 बूंद का नस्य देने से सिर में होने वाली पीड़ा शान्त होती है.

❖ ककोड़ा मूल को गाय के घी में पकाकर, घी को छानकर, 1-2 बूंद नाक में टपकाने से आधासीसी के दर्द में लाभ होता है.

❖ **केश विकार-** कर्कोटकी मूल को घीसकर बालों की जड़ों में लगाने से बाल मजबूत होते हैं तथा बालों का गिरना बंद हो जाता है.

❖ कर्कोटकी मूल को काली मिर्च तथा लाल चन्दन के साथ पीसकर उसमें नारियल तेल मिलाकर मस्तक पर लगाने से सिरदर्द में लाभ होता है.

❖ **कान दर्द-** कर्कोटकी मूल को पीसकर घी में पकाकर, छानकर, 1-2 बूंद कान में डालने से कान की वेदना का शमन होता है.

❖ **श्वास-कास-** 1-2 ग्राम बांझ ककोड़ा कन्द चूर्ण में 4 नग काली मरिच चूर्ण मिलाकर जल के साथ पीसकर पिलाएं तथा एक घंटे पश्चात् एक गिलास दूध पिलाने से कफ का नि:सरण होकर श्वास-कास में लाभ होता है.

❖ 1 ग्राम बांझ ककोड़ा कन्द चूर्ण को गुनगुने जल के साथ खिलाने से खांसी में लाभ होता है.

❖ कर्कोटकी मूल की भस्म बनाकर 125 मिग्रा भस्म में 1 चम्मच शहद तथा 1 चम्मच आर्द्रक स्वरस मिलाकर खाने से कास-श्वास में लाभ होता है.



❖ **पीलिया-** कर्कोटकी के मूल स्वरस को 1-2 बूंद नाक में डालने से पीलिया में लाभ होता है.

❖ बांझ ककोड़ा मूल चूर्ण का नस्य देने से तथा गिलोय पत्र को तक्र के साथ पीसकर पिलाने से कामला में लाभ होता है. औषध सेवन काल में पथ्य पालन अनिवार्य है.

❖ **प्लीहावृद्धि-** 1-2 ग्राम बांझ ककोड़ा के मूल चूर्ण में 5 काली मरिच का चूर्ण मिलाकर शहद के साथ खाने से प्लीहावृद्धि का शमन होता है.

❖ 500 मिग्रा कर्कोटकी मूल के सूक्ष्म चूर्ण को दस दिन तक दूध के साथ सेवन करने से अश्मरी टूटकर निकल जाती है.

❖ **मधुमेह-** 1-2 ग्राम कर्कोटकी मूल चूर्ण का सेवन करने से मधुमेह में लाभ होता है.

❖ **दाद-** कर्कोटकी के पत्र-स्वरस में चार गुना तेल मिलाकर पका लें, ठंडा होने पर छानकर रख लें. इस तेल को लगाने से दाद, खुजली आदि त्वचा विकारों में लाभ होता है.

❖ **खुजली-** सायंकाल या ठंड के समय अधिक बढ़ने वाली खुजली में कर्कोटकी के कन्द को पीसकर उसमें तेल मिलाकर उबटन की तरह लगाने से खुजली मिटती है.

❖ **अपस्मार-** बांझ ककोड़ा की जड़ को घी के साथ घिसकर उसमें थोड़ी-सी शर्करा मिलाकर अच्छी तरह पीसकर 1-2 बूंद नस्य देने से तथा 1-2 ग्राम मूल चूर्ण का सेवन करने से अपस्मार में लाभ होता है.

❖ **ज्वर-** कर्कोटक का शाक बनाकर सेवन करने से ज्वर में लाभ होता है.

❖ मूल को पीसकर स्मस्त शरीर पर लेप करने से ज्वर का शमन होता है.

❖ ककोड़ा कन्द चूर्ण को उष्ण जल में पीसकर शोथ युक्त स्थान पर लगाने से शोथ का शमन होता है.

❖ बांझ ककोड़ा के कंद चूर्ण में कुलथी, पीपल, वच, कायफल तथा काला जीरा पीसकर, मिलाकर शरीर पर मालिश करने से लाभ होता है.

❖ **सर्पदंश-** मूल को पीसकर सर्पदंश स्थान पर लेप करने से दंश-जन्य वेदना, दाह आदि का शमन होता है. ■

*प्रयोज्यांग : मूल, अपक्व, फल.*

*मात्रा : चिकित्सक के परामर्शानुसार.*



साईं वंदना

# कार्मिक ऋण-सिद्धान्त

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

विपत्ति के समय हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारी मदद करे. हम ईश्वर से सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं. इसके लिए हम अपने सगे-संबंधियों एवं मित्रों के सामाजिक पदों से भी लाभ उठाना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि वे हमारे जीवन में आई विपत्ति को दूर करके हमारी सहायता करें. लेकिन हमारे लाखों प्रयासों के बावजूद भी कभी-कभी कोई मदद प्राप्त नहीं हो पाती है. परन्तु दूसरी ओर कभी-कभी कोई अकस्मात् आकर हमारी मदद कर देता है. ऐसी अकस्मात् मदद मिलने पर हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं. फिर हम लोगों को जब उसका परिचय देते हैं तो यह बताते हैं कि वह हमारा मित्र है. इससे मूलभूत प्रश्न यह उठता है कि वह व्यक्ति जो सहायता करने आया है, क्या वह कर्म-फल-गति का परिणाम है? (जैसा कि हिंदू कर्म-फल सिद्धांत में बताया गया है और सद्गुरुओं द्वारा जिसका पालन किया गया है). कार्मिक सिद्धांतों के अनुसार यह माना जाता है कि वह व्यक्ति जो मुसिबत में सहायता कर रहा है, वह पूर्व जन्म के ऋणानुबंध के कारण सहायता कर रहा है और जिसकी सहायता वह कर रहा है, उसने भी पिछले जन्म में उसके लिए कुछ किया होगा. इसका अर्थ यह है कि पूर्व जन्मों के कर्म-फल के द्वारा किसी को ऐसा मित्र मिला. यही नहीं, यदि हम जीवन में किसी संकट की घड़ी में किसी को शत्रु रूप में मानें तो हमारी तात्कालिक प्रतिक्रिया उस व्यक्ति के प्रति झुंझलाहट से आरम्भ होती है. यह झुंझलाहट आगे चलकर बदले की भावना और फिर क्रोध के रूप में पकट होती है. फिर हम उसकी निंदा करनी आरंभ करते हैं और उसे अपना शत्रु मानते हैं. इस आधार पर जीवन भर यह संसार हमें 'मेरे मित्र' और 'मेरे शत्रु' के रूप में दिखाई देता है. लेकिन यदि हमारे मित्र हमें पूर्व जन्म के कर्मफल से मिले हैं (जिनके विषय में हम गर्व अनुभव करते हैं) तो क्या तार्किक रूप से यह सिद्ध नहीं होता कि पूर्व जन्म में हमारे दुष्कर्म के कारण ही हमारे शत्रु भी बने हैं. इससे यह प्रमाणित होता है कि जैसे हमारे मित्र बने हैं, वैसे ही हमारे शत्रु भी बने हैं. अत: हमे जीवन में अपने मित्र एवं शत्रु के प्रति सम-भाव रखना चाहिए क्योंकि दोनों ही कार्मिक बंधन से हैं, तो क्या हमारा कर्त्तव्य यह नहीं है कि हम अपने इस जन्म में दोनों को ही प्रभावहीन कर दें या दोनों के ऋणानुबन्ध से मुक्त हो जाएं. 'कर्म-सिद्धान्त' की यह मान्यता है कि मित्र वह है, जो हमें वह सुखद अनुभव प्रदान करता है, जो कि हमने किसी जन्म में उसे दिये होंगे. ठीक इसी प्रकार शत्रु भी हमें दु:खदायक या पीड़ादायक अनुभव प्रदान करता है क्योंकि विगत जन्म/जन्मों में हमने भी उसे उस प्रकार के दु:ख या कष्टदायक अनुभव दिये होंगे.

जब हम शत्रु के द्वारा उत्पन्न दु:खदायक स्थिति का सामना करते हैं तो उस समय कहा जा सकता है कि आत्मा/जीवात्मा परमात्मा का अंश होने के कारण, परमात्मा के सभी गुण उसमें हैं. हमारे समझ दो विकल्प होते हैं- या तो उसके द्वारा दिये गये दु:ख को झेल लें और अपनी सहनशीलता से उसे प्रभावहीन बना दें या फिर बदले में प्रतिक्रिया करके कर्म-फल की प्रतिक्रियात्मक श्रृखंला को अगले जन्मों में ले जाएं. इस संदर्भ में श्री शिरडी साईं बाबा द्वारा प्रदान क गई शिक्षा महत्तवपूर्ण है, जो कि ऐसी स्थिति से उबारने में सहायक है. 'श्री साईं सच्चरित्र' में उल्लिखित चेनबसाप्पा एवं वीरभ्रप्पा नामक मेंढक और सांप की कथा हमारे प्रश्न के सही उत्तर को सूचित और हमारा दिशा-निर्देश करती है. श्री शिरडी साईं बाबा ने अपने भक्तों को यह शिक्षा दी है कि वे अपने शत्रुओं के प्रति शत्रुवत् नकारात्मक भावना के साथ कटुतापूर्ण प्रतिक्रिया न करें बल्कि उसके शत्रुता के व्यवहार को सहन करते हुए अपने पिछले जन्मों के पापों को मिटाएं. चलें, इस अत्यंत विकसित एवं सूक्ष्म कर्म-फल के सिद्धांत को एक साधारण की सहायता से और भी अच्छी तरह समझने का प्रयास करें. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

**साईं भक्तों!** आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरन भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बनें आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

# टेस्ट क्रिकेट में भारत का वर्चस्व पक्का

# इंग्लैंड हक्का-बक्का

**टीम इंडिया ने एक बार फिर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया. इंग्लैंड की टीम भारत में सीरीज जीतने का सपना लेकर पहुंची थी, लेकिन विराट की टीम के आगे उनकी एक नहीं चली. कोहली भारत के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में शामिल हो चुके हैं.**

सैयद मोहम्मद अब्बास

भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतने की तरफ अग्रसर है. टीम इंडिया ने विराट की कप्तानी में नया इतिहास बनाने की ओर कदम बढ़ा दिया है. पहले न्यूजीलैंड को धूल चटाया अब इंग्लैंड को चारो खाने चित किया है. विराट की सेना इंग्लैंड पर अब भारी पड़ रही है. मौजूदा टेस्ट सीरीज में मेहमान भारतीय धरती पर कमाल करने में नाकाम रहे हैं. इंग्लैंड की टीम ने भले ही पहले टेस्ट में टीम इंडिया को कड़ी टक्कर देने का दावा किया हो, लेकिन बाद के टेस्ट में उनकी हालात बेहद खस्ता हो गई. गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी में इंग्लैंड का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. इंग्लैंड की टीम भारतीय सरजमीं पर अच्छा प्रदर्शन करने का हुनर रखने वाली टीम मानी जाती है, परंतु इस बार विराट की युवा टीम के खिलाफ उसका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा. मेहमान टीम भी मानती है कोहली की यह टीम माही की तुलना में बेहद मजबूत दिख रही है. इंग्लैंड टीम के कप्तान के अनुसार विराट के टीम की ताकत है युवा खिलाड़ी. दरअसल इससे पूर्व इंग्लैंड की टीम माही की अगुवाई वाली टीम पर भारी पड़ी थी. मौजूदा समय में टीम इंडिया बेहद शानदार क्रिकेट खेल रही है. टीम के पास अच्छा बॉलिंग अटैक है और युवा बल्लेबाजों की लम्बी फौज भी है. विराट की टीम में हर खिलाड़ी अपने रोल से वाकिफ है. इस टीम की खास बात यह है कि एक ही खिलाड़ी पर निर्भरता नहीं है. मध्यक्रम के नाकाम होने पर ऑलरांडर बनने की ओर कदम बढ़ा रहे कुछ खिलाड़ियों ने कई मौकों पर टीम को बिखरने से बचाया है. गेंदबाजी में भी भारतीय टीम एक अलग ताकत के रूप में उभरी है. इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट को छोड़ दिया जाये तो टीम ने मैदान पर अपनी बादशाहत कायम की है. टीम के मौजूदा प्रदर्शन की बात की जाये तो इसमें बल्लेबाजों की भूमिका भी अहम कही जा सकती है. ओपनर के तौर पर टीम भले ही जूझ रही हो लेकिन तीसरे टेस्ट में पार्थिव ने अपने बल्ले से कमाल कर विराट को बड़ी राहत दी. बतौर विकेटकीपर टीम में शामिल किये गये पार्थिव पटेल ने दूसरी पारी में अच्छा प्रदर्शन करते हुए पचासा जड़ कर अपनी बल्लेबाजी का भी लोहा मनवाया. दूसरी ओर मुरली विजय हालांकि मोहाली टेस्ट में चले नहीं लेकिन बड़े मैचों में उनका बल्ला रनों की बारिश करता है. मोहाली टेस्ट में इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 283 रन के स्कोर पर ढेर हो गई थी. इसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने भले ही कुछ मौकों पर निराश किया, लेकिन टीम ने किसी तरह से 417 रन का स्कोर बनाकर मेहमान टीम पर अच्छा खासा दबाव बना डाला. दूसरी पारी में इंग्लैंड के बल्लेबाज एक बार फिर रन बनाने में असफल रहे. इसके बाद टीम इंडिया ने यह मुकाबला आठ विकेट से जीतकर इंग्लैंड पर अपनी बढ़त बना डाली.

**मौजूदा समय में टीम इंडिया बेहद शानदार क्रिकेट खेल रही है. टीम के पास अच्छा बॉलिंग अटैक है और युवा बल्लेबाजों की लम्बी फौज भी है. विराट की टीम में हर खिलाड़ी अपने रोल से वाकिफ है. इस टीम की खास बात यह है कि एक ही खिलाड़ी पर निर्भरता नहीं है. मध्यक्रम के नाकाम होने पर ऑलरांडर बनने की ओर कदम बढ़ा रहे कुछ खिलाड़ियों ने कई मौकों पर टीम को बिखरने से बचाया है. गेंदबाजी में भी भारतीय टीम एक अलग ताकत के रूप में उभरी है.**

न्यूजीलैंड सीरीज की तरह एक बार फिर रविचंद्रन अश्विन बतौर ऑलरांडर खिलाड़ी के तौर पर सामने आये हैं. उनकी गेंदबाजी तो कमाल की रही है और अब वह बल्ले से भी जौहर दिखा रहे हैं. उनकी स्पिन की धार लगातार बढ़ रही है. उनका बल्ला ऐसे मौकों पर गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटता है जब टीम इंडिया की बल्लेबाजी कमजोर पड़ती दिखती है. उनका प्रदर्शन भी इस बात का गवाह है. अश्विन भारत के तीसरे गेंदबाज है जिन्होंने एक सीजन में 500 रन बनाने के साथ-साथ 50 विकेट भी चटकाये हैं. इससे पूर्व कपिल देव ने 1979 और 1983 में यह कारनामा किया था. कपिल 1979 के सीजन में कुल 17 टेस्ट में 619 रन के साथ-साथ 74 विकेट चटका कर भारत के सर्वश्रेष्ठ ऑलरांडर के रूप में सामने आये थे. इसके बाद 1983 में भी कपिल ने इसी तरह 18 टेस्ट में 579 रन और 75 विकेट लेकर विश्व क्रिकेट में खूब नाम कमाया. अश्विन भी कपिल के नक्शेकदम पर चल रहे हैं. मैच दर मैच अश्विन लगातार दोनों विधाओं में अपनी छाप छोड़ रहे हैं. उनके इस प्रदर्शन को देखकर कई खिलाड़ियों ने तारीफ के पुल बांधे हैं. जानकारों की मानें तो आर अश्विन का प्रदर्शन वॉर्थम व इमरान खान जैसे खिलाड़ियों से बेहतर लग रहा है. तमिलनाडु का यह खिलाड़ी टीम इंडिया के संकटमोचक के रूप में देखा जा सकता है.

भारत की बल्लेबाजी की बात की जाये तो इतना तो साफ है कि टीम किसी एक बल्लेबाज के सहारे टेस्ट में जलवा नहीं दिखा रही है बल्कि उसका बल्लेबाजी क्रम निचले स्तर पर बेहद मजबूत दिख रहा है. शुरुआत में भले ही टॉप आर्डर फेल हो जाता है, लेकिन इस नाकामी को निचले क्रम के बल्लेबाज छुपा लेने में माहिर साबित हो रहे हैं. मोहाली टेस्ट में टीम इंडिया की बल्लेबाजी कमजोर दिखी. पांच विकेट बेहद कम स्कोर पर चलते बने, लेकिन बाद में निचले क्रम के बल्लेबाजों ने 400 से ज्यादा रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिये. इसके बाद कुक की टीम के पसीने छूट गये. निचले क्रम में एक ओर अश्विन कमाल करते हैं, तो दूसरी ओर जडेजा भी कम नहीं हैं. बतौर गेंदबाज उनकी फिरकी की खूब तारीफ होती है, साथ ही उन्होंने मोहाली टेस्ट में अश्विन के साथ मिलकर 97 रन की साझेदारी कर टीम को संकट से निकाल लिया, यह भी नायाब है. जडेजा इस मैच में शतक बनाने से चूक गये जबकि जयंत यादव ने भी अच्छे हाथ दिखाते हुए मेहमान टीम को करारा जवाब दिया. इसी टेस्ट में अरसे बाद टीम इंडिया में बतौर विकेटकीपर शामिल हुए पार्थिव पटेल ने दबाव में बेहद शानदार प्रदर्शन किया. उनको साहा के चोटिल होने के बाद टीम में मौका मिला. उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए दूसरी पारी में शानदार अर्धशतक जमाया जबकि विकेट के पीछे भी उन्होंने बेहद कमाल का प्रदर्शन किया. उनके इस प्रदर्शन की वजह से साहा के लिए थोड़ी चिंता बढ़ सकती है. खैर इस प्रदर्शन से पटेल टीम में अपनी तगड़ी दावेदारी पेश कर रहे हैं. इस तरह से भारतीय टीम के पास एक और विकेटकीपर मिल गया है. कुल मिलाकर टीम इंडिया ने एक बार फिर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया. इंग्लैंड की टीम भारत में सीरीज जीतने का सपना लेकर पहुंची थी लेकिन विराट की टीम के आगे उनकी एक नहीं चली. कोहली भारत के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में शामिल हो चुके हैं.■

## पार्थिव अच्छे, पर कई और अच्छे लाईन में

पार्थिव पटेल के चयन को लेकर काफी आलोचना भी हुई, क्योंकि कई और काबिल विकेटकीपर लाइन में थे. टीम के कोच अनिल कुम्बले ने पटेल के चयन का पक्ष लिया. दरअसल माही के टेस्ट क्रिकेट से अलग होने के बाद साहा का चयन हुआ. साहा ने भी अपनी शानदार बल्लेबाजी के साथ-साथ विकेटकीपिंग के जौहर भी दिखाए. लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए वह चोटिल हो गये. इस मौके का लाभ पार्थिव को मिल गया. पार्थिव 31 साल के हो चुके हैं. इस कतार में ऋषभ पंत भी थे जो रणजी में लगातार रनों का अम्बार लगा रहे हैं. दूसरी ओर दिनेश कार्तिक व नमन ओझा भी लाइन में लगे थे. पार्थिव पटेल ने एक समय टीम इंडिया के टेस्ट क्रिकेट में अव्वल विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी. बाद में खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें हटा दिया गया था. पार्थिव पटेल को अंतिम बार साल 2008 में श्रीलंका के खिलाफ भारत की तरफ से विकेटकीपर के तौर पर शामिल किया गया था. पार्थिव आठ साल बाद टीम में शामिल हुए हैं. उन्होंने 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था. उस समय उनकी आयु केवल 17 साल थी. इसके बाद पार्थिव ने 20 टेस्ट खेले और इस दौरान उन्होंने 29.69 की औसत से 683 रन बनाये. पार्थिव ने पांच अर्धशतक भी जड़े हैं. विकेटकीपर के तौर पर 41 कैच और आठ स्टंपिंग शामिल है. टीम इंडिया से बाहर होने के बाद पार्थिव ने आईपीएल में अपनी बल्लेबाजी का खूब लोहा मनवाया. घरेलू क्रिकेट में भी उनकी बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग की चर्चा थी. पार्थिव ने मौजूदा रणजी सीजन में कुल पांच मैचों में तीन अर्धशतक के साथ-साथ एक शतक भी जड़ा है. आईपीएल के 2015 में भी शानदार क्रिकेट खेलते हुए पटेल ने 339 रन बनाये थे. बहरहाल, विकेटकीपर की लाईन में नमन ओझा और लोकेश राहुल भी प्रमुख दावेदारों के रूप में देखे जा रहे हैं. ■

# जूनियर विश्व कप हॉकी में भारत से उम्मीदें

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आठ दिसम्बर से शुरू हुई जूनियर विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता में भारतीय हॉकी टीम मजूबत इरादे से उतरी है. दस दिनों तक चलने वाले इस हॉकी मेले में 16 देश की बड़ी टीमें अपना दम-खम दिखाने उतरी हैं. प्रतियोगिता में भारत के आलावा दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, मिस्र, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, कोरिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड व स्पेन जैसी ताकतवार टीमें शमिल हैं, ऐसे में भारतीय टीम के लिए चुनौती आसान नहीं होगी, टीम के कई खिलाड़ी अपनी जोरदार हॉकी चमकाने के लिए बेताब हैं. भारतीय टीम में कई अनुभवी खिलाड़ियों को मौका दिया गया है. टीम में हरमनप्रीत सिंह जैसे मजबूत खिलाड़ी को भी जगह दी गई है. एफआईएच की तरफ से साल 2016 के इस राइजिंग स्टार खिलाड़ी पर अच्छे प्रदर्शन का दबाव होगा. वह देश में ड्रैग फ्लिकर और डिफेंडर के रूप में सफल खिलाड़ियों में शुमार हो चुके हैं. वह रियो ओलम्पिक में भारत की टीम के सदस्य रह चुके हैं. वहीं टीम में मनदीप को भी मौका दिया गया है. इससे पहले वह सीनियर स्तर पर भी अपना जलवा दिखा चुके हैं, मनदीप फॉरवर्ड लाइन को मजबूती प्रदान कर सकते हैं. टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारतीय सीनियर टीम में अपनी हॉकी का लोहा मनवा चुके हैं. भारतीय हॉकी टीम के कोच रोलैंड ओल्टमैंस ने जूनियर खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद लगायी है. कोच के अनुसार यह टीम इस विश्व कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सक्षम लग रही है. भारतीय टीम के अन्य खिलाड़ियों की बात की जाये तो इसमें फारवर्ड लाइन में अजित कुमार, सिमरनजीत सिंह के साथ-साथ अरमान कुरैशी व गुरजंत सिंह सबसे अहम साबित हो सकते हैं. डिफेंडर और ड्रैग फ्लिकर वरूण कुमार का नाम भी शामिल है. टीम की कमान पंजाब के हरजीत सिंह के कंधों पर है. वह मिडफिल्डर के रूप में भरोसे के खिलाड़ी माने जाते हैं. दूसरी ओर टीम की उपकप्तानी का जिम्मा दीपसान तिर्की सम्भाल रहे हैं. हरजीत सिंह भारतीय जूनियर हॉकी टीम में कोई नया नाम नहीं है. 20 साल के उभरते हुए इस खिलाड़ी को अपने खेल के आलावा दूसरी चीजों के लिए भी जाना जाता है. टीम में उन्हें कड़क चाय पिलाने वाले के रूप में भी जाना जाता है. एक ट्रक चालक का बेटा अब भारतीय टीम की कप्तानी कर रहा है. अभी हाल में उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें सबसे बेहतरीन युवा खिलाड़ी के रूप में दस लाख इनाम दिया गया था. कोच भी उनकी हॉकी के मुरीद रहे हैं. टीम का दावा इस बार ज्यादा मजबूत लग रहा है क्योंकि इस टीम को बनाने में कोच रोलैंड ओल्टमैंस ने कड़ी मेहनत की है. इस बार भारतीय टीम के ग्रुप में कनाडा, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसी उभरती हुई टीमें शामिल हैं. टीम का पहला मुकाबला आठ दिसम्बर को कनाडा से होगा जबकि 10 दिसम्बर को इंग्लैंड व 12 दिसम्बर को दक्षिण अफ्रीका से दो-दो हाथ करना है.

यूपी में हॉकी के काफी प्रशंसक हैं. इससे पहले लखनऊ को हॉकी इंडिया लीग के मैचों की मेजबानी मिल चुकी है, लेकिन इस बार जूनियर विश्व की मेजबानी को लेकर सूबे के खेल प्रेमी काफी उत्साहित हैं. यूपी की राजधानी लखनऊ में इस प्रतियोगिता के लिए आयोजकों ने भी कड़ी मेहनत की है. शहर के सबसे बड़े मेजर ध्यानचंद स्टेडियम इस प्रतियोगिता के लिए खास तरीके से तैयार किया गया है. यूपी हमेशा हॉकी का गढ़ रहा है. यहां से मेजर ध्यानचंद और केडी सिंह बाबू जैसे हॉकी के जादूगर हुए हैं. यहीं से मोहम्मद शाहिद के आलावा सैयद अली, सुजीत कुमार जैसी प्रतिभाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी हॉकी के लिए ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं. वर्तमान में दानिश मुज्तबा सीनियर टीम में अपना दम-खम दिखा रहे हैं. सूबे में अब हॉकी को बड़े स्तर पर लाने की तैयारी की जा रही है. इसी कड़ी में जूनियर विश्व कप हॉकी का आयोजन हुआ है. युवाओं को हॉकी के बारे में बताना होगा. एक वक्त था, जब भारतीय हॉकी की तूती पूरे विश्व में बोलती थी लेकिन बाद में खराब राजनीति के चलते हॉकी का स्तर एकदम से जमीन पर आ गया. ओलम्पिक जैसी प्रतियोगिता में टीम फिसड्डी साबित होने लगी थी लेकिन हाल के दिनों में हॉकी की तस्वीर बदली है. अब भारतीय टीम ने सीनियर स्तर पर जोरदार प्रदर्शन किया है ऐसे में देश में हॉकी को लेकर लोगों का नजरिया बदला है. भारतीय हॉकी को अपने प्रदर्शन से लोगों को जवाब देना होगा. अगर टीम फिर से जीत की पटरी पर लौटती है, तो यह भारतीय हॉकी एक बार स्वर्णिम इतिहास को फिर वापस पा सकती है. यह तभी सम्भव जब टीम हर टूर्नामेंट में अपनी हॉकी डंका बजवाये. ■

feedback@chauthiduniya.com

## शिवाय का अगला क़दम

अरे रुकिए हम फिल्म शिवाय की बात नहीं कर रहें बल्कि शिवाय के हीरो अजय देवगन की बात कर रहे हैं जो अपने अगले प्रोजेक्ट फिल्म *बादशाहों* में आजकल व्यस्त हैं. करीब पिछले 1 साल से अजय देवगन लगातार सिर्फ शिवाय की वजह से चर्चा में थे. आखिरकार अजय देवगन शिवाय के बाद अगली फिल्म की तैयारी में भी जुट चुके हैं. जी हां हम बात कर रहे हैं उनकी आने वाली फिल्म बादशाहों की जिसकी पुष्टि खुद अजय देवगन ने की. ट्विटर पर खुद ही अजय देवगन ने लोकेशन की एक तस्वीर भी डाली और साथ ही कैप्शन भी डाला बादशाहों टाइम. आपको बता दें कि फिल्म इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान की इमरजेंसी के समय की है. बादशाहों के बाद अजय जल्द ही रोहित शेट्टी की फिल्म *गोलमाल 4* में व्यस्त हो जाएंगे. बता दें पिछले 2 साल से अजय अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म शिवाय में व्यस्त थे जिसको खुद अजय ने ही डायरेक्ट किया है. फिल्म तो औसत रही पर शिवाय ने किसी तरह 100 करोड़ के क्लब में एंट्री कर ही ली. शिवाय अजय देवगन के करियर की 6वीं 100 करोड़ी फिल्म है.■

# श्रद्धा को साइंटिस्ट बनाना चाहते थे शक्ति कपूर

शक्ति ने आगे बताया कि वह बेटी को हमेशा फिल्म इंडस्ट्री से दूर रखते थे, ताकि वो पढ़ाई पूरी कर साइंटिस्ट बन सके. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था. जब वो छुट्टियों में घर आई, तो उसे हिंदुजा से *तीन पत्ती* का आफर मिला, जिसे वो ठुकरा नहीं सकी और एक्ट्रेस बन गई.

बॉलीवुड में शक्ति कपूर को आज कौन नहीं जानता. एक लंबे अर्से से फिल्म इंडस्ट्री में शक्ति कपूर ने विलेन, भाई, पिता, कॉमेडी लगभग हर किरदार परदे पर जिया है. कॉमेडी को लेकर गोविंदा और कादर खान के साथ तो शक्ति कपूर की कैमिस्ट्री इतनी ज्यादा फेमस है कि जब भी ये तीनों सिलवर स्क्रीन पर आते, तो दर्शकों को लोटपट करके ही दम लेते.

बॉलीवुड फेम एक्टर शक्ति कपूर ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से अपने जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातों को जगजाहिर किया और अपनी लाईफ के कई राज़ खोले. शक्ति ने बताया कि वो अपनी बेटी श्रद्धा कपूर को सांइटिस्ट बनाना चाहते थे. इसके लिए वो पढ़ाई भी कर रही थी, लेकिन उसकी सुंदरता ने उसे एक्ट्रेस बना दिया. शक्ति कपूर ने बताया कि वो अपनी बेटी को सांइटिस्ट बनाने के लिए उसकी हर जरूरत को पूरा करते थे. उसकी अच्छी पढ़ाई के लिए उन्होंने उसे पढ़ने के लिए बोस्टन भेजा. वहां वो 40 लाख फीस भरते थे. उन्होंने बताया कि वो आने वाले दिनों में *शिमला मिर्ची* और *परेशानपुर* फिल्म में दिखाई देंगे. शक्ति ने आगे कहा कि वह बेटी को हमेशा फिल्म इंडस्ट्री से दूर रखते थे, ताकि वो पढ़ाई पूरी कर साइंटिस्ट बन सके. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था. जब वो छुट्टियों में घर आई, तो उसे हिंदुजा से *तीन पत्ती* का आफर मिला, जिसे वो ठुकरा नहीं सकी और एक्ट्रेस बन गई. शक्ति आगे बताते हैं कि फिल्मों में जगह बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन टैलेंट है, तो मंजिल अपने आप मिल जाती है. अब सुविधाओं के साथ बॉलीवुड में परेशानी भी बढ़ गई हैं.■

## अलाउद्दीन ख़िलजी के किरदार में नज़र आएंगे रणवीर

रणवीर सिंह हो या पूरी *पद्मावती* की टीम, सभी फिल्म को लेकर उनके किरदार को लेकर बोलने से बचते जा रहे हैं. लेकिन रणवीर सिंह ने पद्मावती में अपने रोल के बारे में खुलकर बात की और बताया कि आखिर वो कैसा किरदार फिल्म में निभा रहे हैं. दरअसल ये तो सभी को पता है कि फिल्म में रणवीर सिंह अलाउद्दीन ख़िलज़ी का रोल निभा रहे हैं और इसे रणवीर सिंह अपने करियर का अब तक का सबसे मुश्किल रोल मानते हैं क्योंकि ये एक निगेटिव किरदार है. करियर के इस पड़ाव में रणवीर सिंह इसे एक बड़ा रिस्क भी मानते हैं लेकिन करियर है तो क्रिएटिविटी भी जरुरी है इसलिए वो इस किरदार के लिए राजी हो गए.

फिल्म के साइन करने के बारे में भी उन्होंने कहा कि बेफिक्रे में वो एक लवी-डवी, क्यूट, प्यार, इश्क और मोहब्बत टाइप किरदार निभा रहे हैं और इसके बाद इस तरह का उनका ट्रांजिशन दर्शक पसंद करेंगे.■

# जब परिणीति ने चिप्स के 1500 खाली पैकेट जमा किए
# सैफ़ की दीवानी है परिणीति चोपड़ा!

"हाल ही में परिणीति को रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल 4 के लिए साइन किया गया है, जिसमें वह अजय देवगन के अपोजिट दिखाई देंगी."

अक्सर देखा जाता है कि दो हीरोइनों के बीच कभी नहीं पटती, मगर बॉलीवुड की युवा पीढ़ी इस धारणा को तोड़ती नज़र आ रही है. मौजूदा समय में कई ऐसी हीरोइनें हैं, जो दोस्ती की मिसाल पेश कर रही हैं और खुलकर एक दूसरे की तारीफें कर रही हैं. अब परिणीति चोपड़ा को ही ले लीजिए, जिनका दिल अनुष्का शर्मा पर आ गया है. दरअसल करण जौहर की फिल्म *ऐ दिल है मुश्किल* के दौरान ही परिणीति को अनुष्का से प्यार हो गया है. उन्होंने जब अनुष्का को देखा तो उनकी नज़रें उनसे हटी ही नहीं. परिणीति के बारे में एक बात और पता चली है कि वो सैफ अली खान की बहुत बड़ी फैन हैं. उनके भाई सहेज़ ने खुलासा किया कि परिणीति अंबाला में स्कूल के दिनों में सैफ अली खान की बहुत बड़ी फैन थीं. परिणीति ने चिप्स के 1500 खाली पैकेट जमा किए थे, जिन पर सैफ का फेस छपा हुआ था. दिन में कम से कम तीन पैकेट चिप्स तो परिणीति खाती ही थीं. इसके अलावा परिणीति ने अपने भाई-बहनों को भी यह कह रखा था कि वो सिर्फ वही चिप्स का पैकेट लें, जिस पर सैफ अली खान की फोटो छपी हो. चिप्स खाने के बाद परिणीति वो खाली पैकेट अपने पास रख लेती थीं. देखा, तो ये होती है दीवानगी, अब तो परिणीति की इस लिस्ट में अनुष्का भी जुड़ गई हैं.■

## काजोल ने दिया बेटी नाइसा को ख़ूबसूरती का टिप्स

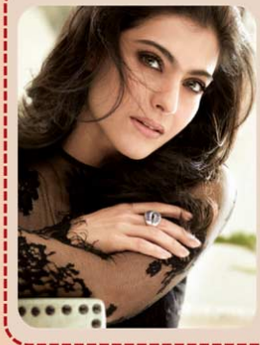

काजोल ऐसी एक्ट्रेस हैं जो लोगों की ऑल टाइम फेवरेट हैं. इसमें कोई शक नहीं कि काजोल अभिनय के मामले में दूसरी एक्ट्रेस पर भारी हैं, वह आज भी फिल्मों में जब काम करती है तो उनके अभिनय की तारीफ हमेशा होती हैं. इसके साथ साथ उनके फैंस काजोल की ख़ूबसूरती के भी दीवाने हैं. देखा जाए तो हक़ीक़त यही है कि 42 वर्षीय काजोल की ख़ूबसूरती कई सालों से दिन ब दिन निखरती जा रही हैं.

जब काजोल से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, *जब मैं ख़ूबसूरत लगती हूं तो अजय मेरी तारीफ करते हैं और कई बार मुझे पता ही नहीं होता कि मैं आकर्षक लग रही हूं और वो मुझसे कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो.* काजोल ने आगे यह भी कहा कि मैं आज भी ख़ूबसूरत हूं, ये मानने में मुझे लंबा वक्त लगा. इसलिए मेरी अपने बारे में राय बदल गई है और अब मैं समझती हूं कि पहले से बेहतर हूं. इसके मायने में अब बड़ी हो गई हूं. काजोल ने खुलासा किया कि उन्होंने अपनी बेटी नाइसा को ख़ूबसूरती के लिए जो सबसे अहम टिप दिए है वो है पर्याप्त मात्रा में पानी पीना.

मुंबई में एक इवेंट के दौरान काजोल ने ख़ूबसूरती के मामले में अपनी मां और बीते जमाने की एक्ट्रेस तनूजा की तारीफ की. काजोल ने कहा कि उनकी विश है कि वो जब अपनी मां की उम्र में पहुंचे तो उन्हीं की तरह दिखें. उन पर उम्र का कोई असर ना हो.■

# क्या सलमान को मना पाएंगे आमिर खान

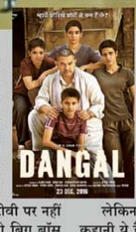


आमिर खान ने दंगल का प्रमोशन शुरू कर दिया है और इस बार दंगल को लेकर उनका प्लान कुछ ख़ास ही नहीं बल्कि कुछ अलग है. इसमें सबसे पहला रूल है दंगल को टीवी पर प्रमोट ना करना. जी हां, दंगल का प्रमोशन आमिर टीवी पर नहीं करेंगे और यही कारण है कि वो बिग बॉस 10 में नहीं दिखाई देंगे. हालांकि आमिर का कहना है कि वो सलमान खान को दंगल दिखाने के लिए काफी उतावले हैं और वो जल्द ही मौका मिलते ही सलमान के लिए दंगल की स्क्रीनिंग रखेंगे.

दरअसल, सलमान आमिर से ज़रा खफा चल रहे हैं. जब सुलतान का ट्रेलर रिलीज़ हुआ तो आमिर खान ने सोशल मीडिया पर उसकी काफी तारीफ की और फिर जब सुलतान रिलीज़ हुई तो आमिर खान बाल्टी भर भर कर रोए. लेकिन ये सब हुआ सामने. पीछे की कहानी ये है कि आमिर खान थोड़े गरम हुए और उन्होंने तुरंत आदित्य चोपड़ा को फोन करते हुए कहा कि ये तो दंगल जैसी फिल्म बनाई है. वहीं उन्होंने कई चीज़ें भी गिनाईं जो दंगल जैसी है. इस बात से सलमान नाराज़ हुए. लेकिन कुछ नहीं कहा. फिर आया दंगल का ट्रेलर, जिसके ठीक पहले आमिर खान केंट्रोवर्सी से भी घिर गए. लेकिन ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद ही आमिर-शाहरूख -सलमान की एक तस्वीर वायरल हुई, जिसने दंगल को बेस्ट बता दिया. हाल ही में सलमान खान से दंगल के ट्रेलर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि वो तो सुलतान जैसा ही है. जिससे आमिर खान को बुरा भी लगा. लेकिन कहते है ना कि समय के साथ सब ठीक हो जाता है, तो देखते है अब आमिर और सलमान की दोस्ती क्या पहले वाले मिज़ाज़ में देखने को मिलती है? ■

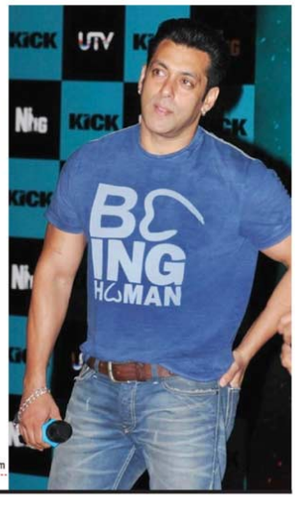


चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com